चौथी दुनिया

www.chauthiduniya.com

मूल्य 5 रुपये

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

1986 से प्रकाशित | 19 जनवरी-25 जनवरी 2015 | Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2015-17, RNI No. DELHI/2009/30467

उड़ीसा में जिंदल का मेगा माइनिंग घोटाला

बिभूति पति

उड़ीसा में जिंदल ग्रुप की कंपनी जेएसपीएल (जिंदल स्टील एंड पॉवर लिमिटेड) ने वन और पर्यावरण कानूनों का खुले तौर पर उल्लंघन किया है. चौथी दुनिया ने पहले भी जिंदल ग्रुप के अवैध और अनियमित क्रियाकलापों को उजागर करते हुए एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी. (देखें: http:// www.eng.chauthiduniya.com/habitat-natural-resources-poorpeople-all-under-threat-locals-suffer-as-jindal- group). यह कहा जा रहा है कि उड़ीसा सरकार और उसके आला अधिकारियों की मिलीभगत से जिंदल ग्रुप के अवैध और अनियमित क्रियाकलाप फल-फूल रहे हैं, और उन्हें क़ानून का उल्लंघन करने की खुली छूट मिली हुई है. जिंदल ग्रुप द्वारा कानूनों के उल्लंघन का एक और गंभीर मामला सामने आया है. सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (सीईसी) ने अपनी जांच भी इसी पर केंद्रित की है.

भारत में स्टील के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक, जिंदल ग्रुप उड़ीसा के एक बड़े खनन घोटाले में लिप्त दिखाई दे रहा है. सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित समिति ने अपनी हालिया रिपोर्ट में शारदा माइंस प्राइवेट लिमिटेड (एसएमपीएल) द्वारा ख़नन कानूनों के उल्लंघन और दुरुपयोग के कई मामलों का उल्लेख किया है. जिंदल स्टील एंड पॉवर लिमिटेड (जेएसपीएल) और एसएमपीएल के बीच व्यावसायिक समझौता है, जिसके तहत जिंदल स्टील अपनी उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के रायगढ़ स्थित स्टील इकाइयों के लिए एसएमपीएल से लौह अयस्क खरीदता है.

सुप्रीम कोर्ट ने पीवी जयाकृष्णन की अध्यक्षता में अवैध खनन की जांच के लिए सीईसी का गठन किया. सीईसी ने एसएमपीएल की खदानों का दौरा किया और सुप्रीम कोर्ट के समक्ष इसकी विस्तृत रिपोर्ट पेश की. समिति ने अपनी रिपोर्ट में एसएमपीएल द्वारा की गई कई अनियमिताओं को उजागर करते हुए बताया है कि किस तरह लौह अयस्क के खनन का लाभ जेएसपीएल को मिला. जांच में यह भी पाया गया कि जेएसपीएल ने साल 2000 में एसएमपीएल के साथ एक विवादास्पद समझौते के तहत शारदा मांइस के लीज होल्ड एरिया में एक लौह अयस्क क्रशर स्थापित किया जबकि राज्य का खनन क़ानून इसकी इजाज़त नहीं देता है. क़ानूनन किसी भी खदान के लीज एरिया के अंदर तीसरे पक्ष द्वारा किसी भी तरह का क्रशर या प्रोसेसिंग इकाई के संचालन पर पाबंदी है.

> **“सुप्रीम कोर्ट ने पीवी जयाकृष्णन की अध्यक्षता में अवैध खनन की जांच के लिए सीईसी का गठन किया. सीईसी ने एसएमपीएल की खदानों का दौरा किया और सुप्रीम कोर्ट के समक्ष इसकी विस्तृत रिपोर्ट पेश की. समिति ने अपनी रिपोर्ट में एसएमपीएल द्वारा की गई कई अनियमिताओं को उजागर करते हुए बताया है कि किस तरह लौह अयस्क के खनन का लाभ जेएसपीएल को मिला.”**

एसएमपीएल उड़ीसा के क्योंझर जिले में स्थित ठकुरानी माइंस के ब्लॉक-बी के विशाल लौह अयस्क खदानों का संचालन करती है. एक अनुमान के मुताबिक इस खदान में 45,000 करोड़ रुपये का लौह अयस्क रिजर्व मौजूद है.

सीईसी के मुताबिक खदान और खनिज विकास एवं विनियमन अधिनियम 1957 की धारा-19 और खनिज रियायत नियमावली-1960 (एमसीआर,1960) की अनदेखी करते हुए खदानों की लीज का गैर क़ानूनी तरीके से नवीनीकरण किया गया, जिसे 14 अगस्त 2001 से प्रभावी माना गया, जबकि खनिज विकास एवं विनियमन अधिनियम की धारा-19 के अनुसार ख़नन क़ानून का उल्लंघन करके किया गया. इस तरह का नवीनीकरण शुरू से ही गैर-क़ानूनी था और इसे प्रभावी नहीं माना जा सकता. इस प्रकार, पिछले 12 वर्षों में इस खदान से करोड़ों रुपये की कीमत का अवैध उत्पादन होता रहा है. खनिज विकास एवं विनियमन अधिनियम, 1957 की धारा-21 (5) के मुताबिक राज्य सरकार को यह अधिकार है कि वह इस तरह के उत्पादन के मूल्य का आंकलन करके उसकी वसूली करे. दरअसल, जेएसपीएल उस समय से इस खदान के उत्पादन की लाभार्थी रही है जब से उसने उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में अपने स्टील प्लांटों के लिए इस खदान से कच्चे माल की खरीदारी करना शुरू की.

> **“भारत में स्टील के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक, जिंदल ग्रुप उड़ीसा के एक बड़े खनन घोटाले में लिप्त दिखाई दे रहा है. सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित एक समिति ने अपनी हालिया रिपोर्ट में शारदा माइंस प्राइवेट लिमिटेड (एसएमपीएल) द्वारा खनन कानूनों के उल्लंघन और दुरुपयोग के कई मामलों का उल्लेख किया है.”**

सीईसी की टिप्पणियों से यह स्पष्ट हो जाता है कि राज्य सरकार के अधिकारियों को इस बात की जानकारी थी कि 616 हेक्टेयर के एक क्षेत्र को बतौर वन क्षेत्र संरक्षित करना जरूरी था, बावजूद इसके उन्होंने खनन के लिए 367 हेक्टेयर भूमि आवंटित करने की सिफारिश की. इससे स्पष्ट हो जाता है कि अधिकारियों और पट्टेदारों (lessee) की मिलीभगत से यह सब कुछ हुआ. चूंकि इसकी जांच राज्य के सतर्कता विभाग से नहीं कराई गई है, इसलिये आरोप तय करने के लिए सीबीआई से जांच कराना आवश्यक है.

ठकुरानी लौह अयस्क खदान के ब्लॉक-बी का कुल लीज क्षेत्र 947.06 हेक्टेयर है, जिसमें से 941.49 हेक्टेयर भूमि संरक्षित वन के दायरे में आती है. खनन के लिए आवंटित की गई 249.276 हेक्टेयर भूमि में से 166.320 हेक्टेयर भूमि को खनन (खदानों से खनिज की खुदाई) के लिये, 20.351 हेक्टेयर निम्न स्तर के खनिज के भंडारण के लिए, 32.104 हेक्टेयर अतरिक्त बोझ को कम करने के लिए, 0.150 हेक्टेयर बारूद रखने के लिए, 11.650 हेक्टेयर बुनियादी सुविधाओं के लिए और 18.521 हेक्टेयर सड़क, रोपवे और रेलवे लाइन बिछाने के लिए आवंटित की गई थी. सीईसी की रिपोर्ट के मुताबिक राज्य सरकार ने उपरोक्त प्रस्ताव की सिफारिश करते वक़्त लीज क्षेत्र में गैर-वानिकी उपयोग को स्पष्ट किया था, जो कि वन संरक्षण अधिनियम-1980 का उल्लंघन था. रिपोर्ट में एक बहुत बड़े वाशिंग प्लांट के निर्माण की बात भी कही गई है.

राज्य सरकार द्वारा खनन के लिए 367.832 हेक्टेयर अतिरिक्त वन क्षेत्र आवंटित करने का प्रस्ताव पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पास विचाराधीन था. सीईसी के मुताबिक 29 अक्टूबर 2008 को मिली पर्यावरण मंजूरी उस वक़्त तक मान्य नहीं होगी, जब तक कि वन विभाग से इसके लिए मंज़ूरी नहीं मिल जाती. खनन और उससे संबंधित गतिविधियों के लिए अतिरिक्त वन भूमि के आवंटन को उस स्थिति में वैध माना जायेगा, जब इसकी मंज़ूरी वन (संरक्षण) अधिनियम-1980 के मुताबिक ली गई हो. बहरहाल, शारदा माइंस ने इस खदान से कुल 15 मिलियन मीट्रिक टन लौह अयस्क का उत्पादन किया. सीईसी के मुताबिक यह उत्पादन

(शेष पृष्ठ 2 पर)

विलय के चक्कर में कहीं गिर न जाए मांझी सरकार पेज-03

कोल ब्लॉक आवंटन के ख़िलाफ़ ग्राम सभाओं ने पारित किया प्रस्ताव पेज-04

चेहरा देखकर बंटे टिकट, कर्मठ हाशिये पर पेज-05

साई की महिमा पेज-12

उड़ीसा में जिंदल का मेगा माइनिंग घोटाला

पृष्ठ एक का शेष

वन विभाग की मंजूरी के बाद ही किया जा सकता था. जबकि 22 सितंबर 2004 के पर्यावरण क्लीयरेंस में निर्धारित 4.0 मिलियन मीट्रिक टन से अधिक वार्षिक उत्पादन को पर्यावरण मंजूरी के विरुद्ध माना जाएगा.

खनिज का उत्पादन तभी बढ़ सकता है जब पट्टेदार उस वर्जिन (शुद्ध) वन भूमि का इस्तेमाल करता. इस भूमि पर खनन करने का प्रस्ताव वन विभाग के पास लंबित था. राज्य के वन और पर्यावरण विभाग के अधिकारियों को मालूम था कि 15 मिलियन टन प्रति वर्ष का बढ़ा हुआ उत्पादन स्तर तभी प्राप्त किया जा सकता था, जब वन विभाग कंपनी को वर्जिन वन भूमि में खनन करने की इज़ाजत मिली होती. इसके बावजूद उन्होंने अतिरिक्त उत्पादन पर रोक नहीं लगाई. इससे तो यही ज़ाहिर होता है कि यह सब राज्य सरकार की मिलीभगत से हो रहा था. चूंकि राज्य सतर्कता विभाग ने इस पर संज्ञान नहीं लिया और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं की, इसलिए इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की आवश्यकता है.

14 अगस्त 2001 को खनन पट्टे के नवीनीकरण के बाद खदान से निकलने वाले लौह अयस्क की क्रशिंग और स्क्रीनिंग का ठेका जेएसपीएल को दे दिया गया. क्रशिंग और स्क्रीनिंग के बाद पट्टेदार इस लौह अयस्क को जेएसपीएल को बेच देता था. बहरहाल, 27 मार्च 2004 के बाद डिप्टी डायरेक्टर ऑफ़ माइंस (डीडीएम), जोड़ा, ने पट्टेदार को यह अनुमति दी थी की वह बिना प्रोसेस किया लौह अयस्क जेएसपीएल को बेच सकता है बशर्ते कि पट्टेदार (शारदा माइंस) 63.7 प्रतिशत लौह मात्रा वाले लौह अयस्क (आरओएम-रन ऑफ द माइन) के लिए उच्चतम निर्धारित रॉयल्टी अदा करे. इसके बाद से पट्टेदार आरओएम के रूप में खनिज का अपना पूरा उत्पादन जेएसपीएल को बेच रही है.

सीईसी की टीम ने अपनी जांच में पाया कि माइनिंग लीज क्षेत्र में जेएसपीएल द्वारा स्थापित 3000 टन प्रति घंटा और 1000 टन प्रति घंटा क्षमता वाले दो क्रशर काम कर रहे थे. जबकि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इन दोनों क्रशरों के संचालन का सर्टिफिकेट जेएसपीएल के नाम से जारी किया था. यह सरासर गैर-क़ानूनी था, लेकिन राज्य सरकार पर जेएसपीएल के असाधारण प्रभाव के कारण राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की. जेएसपीएल को आरओएम के रूप में लौह अयस्क वर्ष 2007-08 के दौरान 239 रुपये प्रति मीट्रिक टन और 2012-13 के दौरान 2,113 रुपये प्रति मीट्रिक टन की दर से बेचा गया, जो कि बाजार मूल्य से कम था. क्योंकि 2007-08 में एस्सेल माइनिंग ने उत्पादित लौह अयस्क लमप्स (ग्रेडिंग) को 4,351 रुपये प्रति मीट्रिक टन और रूंगटा माइन्स ने 4,253 रुपये प्रति मीट्रिक टन की दर से बेचा था. राज्य के अधिकारी इस बात को भली-भांति जानते थे कि आरओएम रूप में लौह अयस्क की बिक्री ग़ैरक़ानूनी है. लौह अयस्क की लमप्स (ग्रेडिंग) के बजाये

आरओएम के आधार पर मूल्य निर्धारण की वजह से राज्य को रॉयल्टी/वैट के रूप में राजस्व का काफी नुकसान उठाना पड़ा. राजस्व का यह नुक़सान खनन विभाग और बिक्री कर विभाग की मिलीभगत से हुआ.

सीईसी ने अपनी जांच में यह भी पाया कि पूरे राज्य में जेएसपीएल ही एक ऐसी कंपनी थी जिसे राज्य सरकार से किसी दूसरी कंपनी के लीज क्षेत्र में क्रशिंग और स्क्रीनिंग इकाई स्थापित करने की अनुमति मिली थी. खनन संबंधित क़ानून किसी ख़नन लीज के भीतर किसी तीसरे पक्ष को क्रशिंग इकाई की स्थापना या संचालन की अनुमति नहीं देते. उड़ीसा सरकार का कहना है कि उसने किसी अन्य मामले में किसी तीसरे पक्ष को खनन लीज के भीतर 25 किलोमीटर के दायरे में क्रशिंग इकाई की स्थापना या संचालन की अनुमति नहीं दी है. सीईसी ने भी कहा है कि राज्य सरकार ने (1) पट्टेदार को आरओएम रूप में खनिज बेचने की अनुमति दी थी, और (2) किसी तीसरे पक्ष के लीज एरिया में क्रशिंग और स्क्रीनिंग प्लांट की स्थापना ही सभी अवैध कार्यों और अनियमितताओं की जड़ है.

आरओएम(सीधे खदान से निकला अयस्क) रूप में लौह अयस्क की बिक्री गैर कानूनी थी और यह राज्य के अधिकारी जानते थे. लम्प (ग्रेडिंग) के बजाये आरओएम के आधार पर मूल्य निर्धारण की वजह से राज्य को रॉयल्टी/वैट के रूप में राजस्व का काफी नुकसान उठाना पड़ा. राजस्व का यह नुकसान खनन विभाग और बिक्री कर विभाग की मिलीभगत से हुआ. चूंकि राज्य सतर्कता विभाग ने ऐसे अधिकारियों पर आज तक कोई कारवाई नहीं की इसलिए इस मामले की जांच सीबीआई से करवानी चाहिए. सीईसी ने इस मामले में रॉयल्टी और वैट का पुनः अनुमान लगाकर इसकी उगाही पट्टेदार से करने का सुझाव दिया है. लेकिन राज्य सरकार ने इस सुझाव पर अभी तक कोई अमल नहीं किया है. हालांकि ऐसा करके राज्य सरकार करोड़ों रुपये के राजस्व की उगाही कर सकती थी.

9 नवम्बर, 2011 को राज्य सरकार ने नियम 37 की अवहेलना की जांच करने के लिए पी सी पात्रा, डिप्टी डायरेक्टर ऑफ मांइस(भुवनेश्वर) की अध्यक्षता में एक जांच समिति गठित की थी. इस कमेटी की जांच रिपोर्ट में कहा गया कि खनन का सबसे अधिक लाभ जेएसपीएल को मिला. रिपोर्ट में जेएसपीएल द्वारा क्रशर की स्थापना करने, राज्य सरकार द्वारा वैट की कम वसूली और एसएमपीएल द्वारा लौह अयस्क की ढुलाई के लिए पाइप कनवेयर लगवाने की अनुमति मांगने जैसी अनियमिताओं को उजागर किया. सरकार पहली जांच रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं थी इसलिए राज्य सरकार ने दूसरी जांच समिति का गठन किया. 30 जुलाई 2012 को दूसरी जांच रिपोर्ट में कहा गया कि पट्टेदार ने आरओएम रूप में खनिज की बिक्री की अनुमति खनन निदेशक (डायरेक्टर ऑफ़ माइंस) से ली थी और सारी गतिविधियां कानून के मुताबिक चल रही थीं. इस जांच रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि राज्य सरकार को रॉयल्टी का कोई नुकसान नहीं हुआ है. हालांकि, यह समिति इस नतीजे पर पहुंची थी कि नियम 37 (1) के पूर्ण रूप से प्रथम दृष्टया उल्लंघन को नकारा नहीं जा सकता है, क्योंकि समिति के समक्ष जेएसपीएल का कोई रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं किया गया.

बहरहाल, सीईसी ने इस जांच समिति की रिपोर्ट पर अपनी असहमति जताई है, क्योंकि इस रिपोर्ट में बाज़ार मूल्य से बहुत कम कीमत पर खनिज की बिक्री जैसे अहम मुद्दे को नज़रंदाज़ किया गया था. साथ ही नतीजतन एमसीआर-1960, के नियम 37 का उल्लंघन करते हुए खनन लीज का लाभ किसी तीसरे पक्ष को हस्तांतरित किया गया था.जब पहली जांच समिति ने पट्टेदार द्वारा एमसीआर-1960, के नियम 37 की अवहेलना और दूसरी अनियमिताओं पर अपनी सख्त रिपोर्ट पेश की तो राज्य सरकार ने इस पर असहमति जताते हुए दूसरी जांच समिति गठित की. यह समिति इसलिए गठित की गई थी ताकि पट्टेदार द्वारा क़ानून की अनदेखी पर पर्दा डाला जा सके. यह समिति किसी नतीजे पर सिर्फ इसलिए नहीं पहुंच सकी, क्योंकि जेएसपीएल से संबंधित रिकॉर्ड उसके समक्ष नहीं रखे गये थे. इस तरह राज्य सरकार ने दिखावे के लिए एक जांच समिति का गठन किया, जिसका एक मात्र उद्देश्य पट्टेदार को बचाना था. सरकार ने दूसरी समिति गठित करके नियम 37 के उल्लंघन को छिपाने की कोशिश की. अब ज़रुरत यह है कि सीबीआई इस मामले की जांच करे और उन अधिकारियों की पहचान करे जिन्होंने इस मामले को छिपाने की कोशिश की, जिसकी वजह से राज्य सरकार को करोड़ों रुपये के राजस्व का नुकसान हुआ.

नियम 37 के उल्लंघन के पूरे प्रकरण को तर्क संगत तरीके से तभी निपटाया जा सकता है लेकिन तब जब एसएमपीएल के साझेदारों और इससे फायदा उठाने वाली दूसरी इकाइयों की पहचान हो सके और उनकी जांच करके कंपनी में उनकी साझेदारी का सही-सही हिसाब लगाया जा सके. सीईसी ने इस दृष्टिकोण से इस मामले की जांच नहीं की. क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 13 जनवरी 2014 के अपने आदेश में कहा था कि सीईसी अपने जांच का दायरा वन और पर्यावरण क़ानून के उल्लंघन तक ही सीमित रखे. लिहाज़ा, इस बात की जांच ज़रूरी है कि एसएमपीएल का असली मालिक कौन है? सीईसी ने राज्य के मुख्य सचिव की फाइल नोटिंग्स के आधार पर गंभीर टिप्पणी की है कि उड़ीसा के मुख्य सचिव ने अपनी 13 अप्रैल 2002 की नोटिंग में यह लिखा है कि यह सबको मालूम है कि खनन का काम जिंदल ग्रुप द्वारा किया जा रहा है, तो क्या यह धोखाधड़ी नहीं है?

हालांकि वर्ष 2002 में उड़ीसा के मुख्य सचिव ने लीज हस्तांतरण के समय विधि संगत आपत्ति जताई थी, लेकिन उसे ख़ारिज करके खदान लीज एसएमपीएल को दे दी गई. नवीन पटनायक लंबे समय से राज्य के वन मंत्रालय का कार्य संभाले हुए हैं और उन्हीं के कार्यकाल के दौरान नियमों के उल्लंघन की बात की गई थी, जिसे बाद में नज़र अंदाज़ कर दिया गया. इसी तरह, उस दौरान भी खनन कानूनों की धज्जियां उड़ाई गई थी, लेकिन उस पर भी राज्य सरकार ने लीपा पोती कर दी. जिंदल ग्रुप ने कौड़ियों के भाव में ख़रीदे गए लौह अयस्क से बहुत मुनाफा कमाया. जबकि वह खदान के असल पट्टेदार नहीं थे, लेकिन राज्य का सरकारी तंत्र इस गैरक़ानूनी काम में उसका सहयोगी था. अब सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट की ओर हैं जो सीईसी की रिपोर्ट के आधार पर अपना फैसला सुनाएगी. ■

feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया
हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

वर्ष 06 अंक 46
दिल्ली, 19 जनवरी-25 जनवरी 2015
RNI-DELHIN/2009/30467

संपादक
संतोष भारतीय

संपादक समन्वय
डॉ. मनीष कुमार

सहायक संपादक
सरोज कुमार सिंह (बिहार-झारखंड)
सरयू भवन, वेस्ट बोरिंग केनाल रोड,
हरीलाल स्वीट्स के निकट, पटना-800001
फोन: 0612 3211869, 09431421901

मैसर्स अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक रामपाल सिंह भदौरिया द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड डी 210-211 सेक्टर 63 नोएडा उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं के- 2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय
के-2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001
कैंप कार्यालय एफ-2, सेक्टर -11, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश-201301

फोन न.

संपादकीय	0120-6451999
	6450888
विज्ञापन व प्रसार	022-42296060
	+91-8451050786
	+91-9266627379
फैक्स न.	0120-2544378

पृष्ठ-16+4 (बिहार-झारखंड, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड) हर शुक्रवार को प्रकाशित

चौथी दुनिया में छपे सभी लेख अथवा सामग्री पर चौथी दुनिया का कॉपीराइट है. बिना अनुमति के किसी लेख अथवा सामग्री के पुन: प्रकाशन पर क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी.

समस्त कानूनी विवादों का क्षेत्राधिकार दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा.

दिल्ली का बाबू

दिलीप चेरियन

कैडर विवाद

दो राज्यों की राजधानी और केंद्र शासित प्रदेश होने की वजह से चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा और केन्द्र शासित प्रदेश कैडर के बाबुओं के बीच संघर्ष का गवाह रहा है. इसकी वजह है कि आईएएस, आईपीएस और राज्य संवर्ग से प्रतिनियुक्ति पर आने वाले अधिकारियों के बीच से भरे जाने वाले पदों में अद्वितीय 60:40 का अनुपात होता है. इस अनुपात का संतुलन कभी एक राज्य तो कभी दूसरे राज्य की ओर झुकता है. यही विवाद की वजह भी बनता है. लेकिन केन्द्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ प्रशासन में नव नियुक्त सलाहकार विजय कुमार देव उम्मीद कर रहे हैं कि यह कलह समाप्त हो जाएगी. केन्द्र शासित प्रदेशों के बाबुओं के साथ अपनी पहली बातचीत में उन्होंने कड़ी लाइन ली और उनसे कहा कि चंडीगढ़ में प्रतिनियुक्ति पर आने के बाद वे अपने कैडर को छोड़ चंडीगढ़ की बेहतरी के लिए काम करें. लेकिन सूत्रों का कहना है कि बैठक में हरियाणा कैडर के कई आईएएस अधिकारियों ने इस बात की शिकायत की कि केन्द्र शासित प्रदेशों या पंजाब कैडर के अधिकारियों की कीमत पर चंडीगढ़ में उन्हें दरकिनार किया जाता है. विजय कुमार देव को इस पुरानी समस्या यानी कैडर प्रतिद्वंद्विता को ख़त्म करना होगा. ■

प्रतिनियुक्ति से परेशानी

हिमाचल राज्य कैडर से 28 आईएएस अधिकारी पहले से ही प्रतिनियुक्ति पर केंद्र में सेवा दे रहे हैं. ऐसे में मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह अब किसी अधिकारी को राज्य के बाहर जाने की अनुमति नहीं दोना चाहते हैं. सूत्र बताते हैं कि तीन अतिरिक्त मुख्य सचिव तरुण श्रीधर, विनीत चौधरी और उपमा चौधरी ने प्रतिनियुक्ति के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय से अनुरोध किया है, जबकि इससे पहले भी उनके आवेदनों को खारिज कर दिया गया था. मुख्यमंत्री द्वारा इस नए अनुरोध को स्वीकारे जाने की भी संभावना नहीं है. हिमाचल प्रदेश सरकार भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की कमी का सामना कर रही है. आखिरी बार सचिव स्तर के आईएएस अधिकारियों अली रजा रिजवी, संजय मूर्ति, भरत केरा, अमनदीप गर्ग समेत कुछ अन्य लोगों को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया था. इस पलायन ने मामले को और अधिक कठिन बना दिया. इस बीच, मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह अब उन बाबुओं को वापस लाना चाहते हैं, जिनकी प्रतिनियुक्ति अवधि समाप्त हो रही है. ■

कुलकर्णी की किस्मत

किस्मत कैसे पलटती है, आनंद कुलकर्णी इसका बेहतरीन उदाहरण हैं. कुलकर्णी कभी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण के कार्यकाल के दौरान प्रोटोकॉल, पर्यटन और आबकारी विभागों का नेतृत्व करते थे. जब किस्मत रूठी तो उन्हें महाराष्ट्र राज्य वित्त निगम भेज दिया गया. लेकिन अब फिर से उनका वक्त आ गया है. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उन्हें लोक निर्माण विभाग में वापस ला कर अतिरिक्त मुख्य सचिव का पद दिया है. महाराष्ट्र के बाबुओं में यह लोकप्रिय है की सरकार की चपेट में आए अधिकारियों के दिन नहीं फिरते. लेकिन कुलकर्णी के दिन तो फिर गए. उन्होंने अपनी खोई जमीन को पुन: वापस पा लिया है. यह उनके किस्मत का ही कमाल कहा जाएगा. ■

dilipcherian@gmail.com

> भाजपा को तीन निर्दलीय विधायकों का भी समर्थन है यानि कुल ताकत 99 हो सकती है. इसके अलावा 25 से 30 जदयू विधायकों ने भी अगर विलय का समर्थन नहीं किया और मूल पार्टी में बने रहे तो फिर मांझी सरकार पर गंभीर खतरा पैदा हो सकता है. अगर जदयू के पृथक समूह को भाजपा बाहर से समर्थन दे देती है तो पृथक समूह अपनी सरकार भी बना सकता है. अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर राष्ट्रपति शासन की आशंका भी पैदा हो सकती है.

विलय के चक्कर में

कहीं गिर न जाए मांझी सरकार

राष्ट्रीय जनता दल या फिर जनता दल यूनाइटेड के लिए असल दिक्कत तो विधायक दल के सदस्यों के विलय में है. इस विलय को लेकर तमाम तरह की आशंका है और उसमें खतरे भी हैं. हो सकता है कि कहीं जीतन राम मांझी की सरकार ही दांव पर न लग जाए. अगर नीतीश और लालू इस बाधा को पार करने में सफल हो जाते हैं तो फिर ये दोनों भाजपा के लिए चुनावी मैदान में बड़ी चुनौती पेश कर सकते हैं पर अगर किसी भी वजह से ऐसा नहीं हो पाया तो फिर सरकार पर भी खतरा पैदा हो सकता है और हो सकता है कि बिहार में या तो राष्ट्रपति शासन लगे या फिर भाजपा के सहयोग से किसी नई सरकार का गठन हो जाए. पहले यह समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर विधायक दल के विलय में दिक्कत क्या आने वाली है?

सरोज सिंह

चुनावी साल में बिहार की राजनीति उम्मीद से कहीं ज्यादा संभावनाओं और आशंकाओं को जन्म देकर रोज नई-नई सुर्खियां बटोर रही है. अपनी पार्टियों का एक-दूसरे में विलय करने पर आमादा नीतीश कुमार और लालू प्रसाद सूबे में एक ऐसी राजनीतिक लाइन खींचने की तैयारी कर रहे हैं, जिससे पार पाना भाजपा और उसके सहयोगी दलों के लिए लगभग असंभव हो जाए. दोनों नेताओं ने अब सार्वजनिक तौर पर इसकी मुकम्मल तैयारी करने के प्लान का ऐलान भी शुरू कर दिया है. अखबारों और न्यूज चैनलों की हेडलाइंस में विलय की खबरों की भरमार है. विलय कब होगा, कैसे होगा, दिल्ली और पटना में इसका नेता कौन होगा, जैसे सवाल चटखारे लेकर चौपालों और सत्ता के गलियारों में कहे और सुने जा रहे हैं.चाय की दुकान पर बैठे पके-पकाए राजनीतिक कार्यकर्ताओं की अपनी-अलग समीक्षा है तो राजनीतिक पंडितों की अपनी अलग. कोई विलय को नरेंद्र मोदी के खिलाफ ब्रह्मास्त्र मान रहा है तो कोई इसे आत्मघाती कदम. कोई कहता है कि नरेंद्र मोदी का विजय रथ बिहार में नीतीश और लालू की जोड़ी रोक देगी तो कोई कह रहा है कि विलय ने भाजपा का रास्ता और भी आसान कर दिया है, देखिएगा नेता विपक्ष खोजना मुश्किल हो जाएगा. इन सब दावों और अनुमानों के बीच विलय प्रक्रिया के एक सबसे अहम पहलू पर फोकस कम हो रहा है.

यहां एक संवैधानिक हकीकत को समझना जरूरी है कि सदन के भीतर और सदन के बाहर राजनीतिक दलों की विलय प्रक्रिया के नियम अलग-अलग हैं. विलय के यही अलग-अलग नियम बहुत सारे पेंच पैदा कर रहे हैं और कई आशंकाओं को जन्म दे रहे हैं. राजनीतिक दलों के लिए सदन के बाहर विलय जितना आसान है, उतना सदन के भीतर नहीं. खासकर आज के राजनीतिक माहौल

में जब पार्टी नेतृत्व या पार्टी से किसी न किसी को कोई न कोई गिला-शिकवा जरूर होता है. खासकर बिहार के संदर्भ में यह बात और भी प्रासंगिक है. गौरतलब है कि राजनीतिक दलों के विलय के मामले में चुनाव आयोग ऑल पार्टी हिल लीडर कांफ्रेंस बनाम कैप्टन डब्ल्यू ए संगमा व अन्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वार दिए गए निर्णय और दिशा निर्देश को मान्यता देता है, वहीं विधायक दल के सदस्यों की विलय प्रक्रिया एवं प्रावधान संविधान की दसवीं अनुसूची की धारा 4 में निर्धारित है. सदन के बाहर राजनीतिक दलों के विलय से संबंधित 1977 के उक्त निर्णय और दिशा-निर्देश में अन्य बातों के अलावा यह भी कहा गया है कि पार्टियों के विलय का अर्थ हुआ कि किसी पार्टी को समाप्त कर देना, मतलब पार्टी के मृत्युदंड पर हस्ताक्षर करना. इसलिए ऐसे दूरगामी परिणाम वाले फैसले के लिए पार्टी की प्राथमिक सदस्यों की सहमति अनिवार्य है. ऐसा निर्णय केवल कुछ नेताओं अथवा दल के किसी अंग द्वारा नहीं लिया जा सकता है. राष्ट्रीय जनता दल या फिर जनता दल यूनाइटेड के लिए इस मापदंड पर उतरने में कोई परेशानी नहीं है. जदयू ने इस तरह की प्रक्रिया को पूरा करना शुरू भी कर दिया है. यहां तक तो ठीक है पर असल दिक्कत तो विधायक दल के सदस्यों के विलय में है. इस विलय को लेकर तमाम तरह की आशंका है और उसमें खतरे भी हैं. हो सकता है कि कहीं जीतन राम मांझी की सरकार ही दांव पर न लग जाए. अगर नीतीश और लालू इस बाधा को पार करने में सफल हो जाते हैं तो फिर ये दोनों भाजपा के लिए चुनावी मैदान में बड़ी चुनौती पेश कर सकते हैं पर अगर किसी भी वजह से ऐसा नहीं हो पाया तो फिर सरकार पर भी खतरा पैदा हो सकता है और हो सकता है कि बिहार में या तो राष्ट्रपति शासन लगे या फिर भाजपा के सहयोग से किसी नई सरकार का गठन हो जाए. पहले यह समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर विधायक दल के विलय में दिक्कत क्या आने वाली है? विधायक दल के सदस्यों के विलय का प्रावधान संविधान की दसवीं अनुसूची की धारा 4 में निर्धारित है. सदन के किसी सदस्य के मूल राजनीतिक दल का विलय हुआ तभी समझा जाएगा जब संबंधित विधान दल के कम से कम दो तिहाई सदस्य ऐसे विलय के लिए सहमत हों. सदन का कोई सदस्य पैरा 2 के उप पैरा एक के अधीन अयोग्य नहीं होगा यदि इसके मूल राजनीतिक दल का किसी अन्य राजनीतिक दल में विलय हो जाता है, और वह यह दावा करता है कि वह और उसके मूल राजनीतिक दल के अन्य सदस्य ने विलय स्वीकार नहीं किया है और एक अलग समूह के रूप में कार्य करने का फैसला किया है. संविधान के इन प्रावधानों को एक उदाहरण के माध्यम से आसानी से समझा जा सकता है. 2003 में जब समता पार्टी का जदयू में विलय हुआ था तो उस समय तीन सदस्यों ने उमाशंकर सिंह, भाई वीरेंद्र और गणेश पासवान ने विलय को स्वीकार नहीं किया था. विलय के विरोध के बावजूद इन विधायकों की सदस्यता नहीं गई और एक अलग गुट के तौर पर समता पार्टी भी बरकरार रह गई.

सदन के भीतर विलय के लिए एक-एक सदस्य को इस आशय का शपथ पत्र स्पीकर महोदय को देना अनिवार्य है. अब इन प्रावधानों के रहते जदयू व राजद के सभी विधायकों को पूरी तरह एकजुट कर उन्हें विलय के लिए राजी करना लालू प्रसाद और नीतीश कुमार के लिए एक बड़ी चुनौती होगी. जदयू के भीतर बागी विधायकों के जो तेवर हैं वह किसी से छिपे हुए नहीं हैं. हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद पूरा ज्ञानू खेमा एक नए जोश के साथ नीतीश कुमार के खिलाफ गोलबंदी में जुट गया है. यह गुट अब पचास से अधिक विधायकों का दावा कर रहा है. अगर यह खेमा 30 विधायकों का भी जुगाड़ कर लेता है तो फिर पासा पलट सकता है. सूत्र बताते हैं कि ज्ञानू खेमा जीतन राम मांझी के खिलाफ अभी कुछ नहीं बोलेगा. यह गुट चाहता है कि मांझी भी उनकी मुहिम का हिस्सा बनें और जदयू और भाजपा के पुराने गठबंधन को फिर से जिंदा कर पहले सरकार बनाई जाए और फिर चुनावी मैदान में उतरा जाए. चूंकि पार्टी को बरकरार रखने में सदस्यता जाने का खतरा नहीं है, इसलिए ज्ञानू खेमे को लग रहा है कि नीतीश और लालू से नाराज विधायक ज्यादा से ज्यादा संख्या में उनकी मुहिम में शामिल हो जाएंगे. ज्ञानू लगातार भाजपा नेताओं के संपर्क में हैं और भाजपा का खेमा भी इस पूरे अवसर को गंभीरता से देख रहा है. भाजपा सूत्रों का कहना है कि पार्टी अपने स्तर से कोई पहल नहीं करेगी. मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों के हिसाब से राज्य के हित में जो होगा, वह किया जाएगा. फिलहाल तो वेट एंड वाच की रणनीति लागू है. अब ऐसे हालात में दो तिहाई विधायकों को विलय के लिए तैयार करना नीतीश कुमार के लिए कठिन काम हो सकता है. जदयू के बागी विधायकों के नेता ज्ञानू सिंह कहते हैं कि हम 18 नहीं बल्कि पचास से ज्यादा हैं. उचित समय पर सभी को हमारी ताकत का एहसास हो जाएगा. नीतीश कुमार केवल अपनी जिद के कारण लालू प्रसाद के चरणों में जाकर बैठ गए हैं. बिहार की जनता इसका जवाब नीतीश कुमार को देगी. ज्ञानू कहते हैं कि हमारे सभी साथी विलय के खिलाफ हैं और सदन के भीतर व सदन के बाहर दोनों ही जगहों पर हमलोग इसका पूरा विरोध करेंगे. बागी विधायक अजीत कुमार कहते हैं कि जनता ने लालू प्रसाद के खिलाफ जनमत दिया था और हमलोगों को भेजा था, अब किस मुंह से हमलोग लालू प्रसाद के साथ जा सकते हैं. हम नीतीश के नापाक मंसूबे को ध्वस्त कर देंगे. रवींद्र राय कहते हैं कि हमें उच्च न्यायालय से न्याय मिलने का पूरा भरोसा था और हमें खुशी है कि हमें न्याय मिला.

उल्लेखनीय है कि हाईकोर्ट द्वारा चार विधायकों की सदस्यता बहाल कर देने से विलय प्रक्रिया को भारी आघात लगा है. 243 सदस्यीय विधानसभा में जदयू के 111 सदस्य हैं. भाजपा के 88 सदस्य हैं. आठ लोगों को जदयू ने पार्टी से निकाल दिया है. इन आठ विधायकों का अगर साथ भाजपा को मिलता है तो भाजपा के समर्थक विधायकों की संख्या 96 हो जाएगी. भाजपा को तीन निर्दलीय विधायकों का भी समर्थन है यानि कुल ताकत 99 हो सकती है. इसके अलावा 25 से 30 जदयू विधायकों ने भी अगर विलय का समर्थन नहीं किया और मूल पार्टी में बने रहे तो फिर मांझी सरकार पर गंभीर खतरा पैदा हो सकता है. अगर जदयू के पृथक समूह को भाजपा बाहर से समर्थन दे देती है तो पृथक समूह अपनी सरकार भी बना सकता है. अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर राष्ट्रपति शासन की आशंका भी पैदा हो सकती है. कहने का अर्थ यह है कि मामला पूरी तरह फंसा हुआ है. जिस तरह की संवैधानिक प्रकिया है और जिस तरह के समीकरण बिहार की राजनीति में बन रहे हैं, उनमें किसी भी संभावना या आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है. पूर्व विधान पार्षद पी के सिन्हा कहते हैं कि नीतीश कुमार ने मांझी सरकार के भविष्य को संकट में डाल दिया है. दल-बदल और पार्टियों के विलय को लेकर जो नियम हैं उनके मद्देनजर आज की राजनीतिक परिस्थतियों में राजद और जदयू का विलय नियम के तहत लगभग असंभव है. गलती का खामियाजा अभी हाईकोर्ट के फैसले से जदयू भुगत रही है. अगर विलय में भी नियमों की अवेहलना हुई तो फिर लेने के देने पड़ सकते हैं. जीतन राम मांझी ने हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत कर कई तरह की अटकलों को जन्म दे दिया है. देखना है बिहार की राजनीति अब किस करवट बैठती है. ■

feedback@chauthiduniya.com

छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन इस नए अध्यादेश को कोर्ट में चुनौती देने पर भी विचार कर रहा है. प्रियांशु गुप्ता बताते हैं कि हम इस अध्यादेश को कोर्ट में इस आधार पर चुनौती देने पर विचार कर रहे हैं कि क्या इससे पेसा एक्ट का महत्व कम नहीं होता. इससे पहले हसदेव अरण्य बचाओ संघर्ष समिति ने हसदेव अरण्य सुरक्षा यात्रा भी निकाली थी. हसदेव अरण्य बचाओ संघर्ष समिति की यह यात्रा कोरबा, सरगुजा जिले के ग्रामीण इलाकों में चलाई गयी ताकि लोगों को पेसा एक्ट और वनाधिकार कानून 2006 के बारे में जागरूक किया जा सके.

हसदेव अरण्य क्षेत्र में कोल ब्लॉक आवंटन के ख़िलाफ़

ग्राम सभाओं ने पारित किया प्रस्ताव

शशि शेखर

सुप्रीम कोर्ट द्वारा कोल ब्लॉक आवंटन को रद्द करने के बाद सरकार ने सारे कोल ब्लॉक के पुन: आवंटन की प्रक्रिया फिर से शुरू कर दी है. इसके लिए बाक़ायदा सरकार ने नए नियम भी बना दिए है. कोल ऑर्डिनेंस आ चुका है. कोल ब्लॉक आवंटन के लिए आवेदन मंगवाने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है और अगले दो-तीन महीने में आवंटन का काम भी हो जाएगा. कोल ब्लॉक की नीलामी के लिए 31 जनवरी तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं और मार्च तक नीलामी की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी. लेकिन, इस बीच खबर ये है की छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य क्षेत्र की करीब 20 ग्राम सभाओं ने एक प्रस्ताव पारित कर यह साफ़ कर दिया है कि वे अपने क्षेत्र में होने वाले कोल ब्लॉक आवंटन और कोयला खनन का विरोध करेंगी. ग़ौरतलब है कि पिछली बार जब कोयला के ब्लॉक का आवंटन हुआ था तब 218 कोल ब्लॉक मे 30 फीसदी सिर्फ छत्तीसगढ़ में आवंटित हुए थे. छत्तीसगढ़ के सरगुजा और कोरबा में फैले हसदेव अरण्य में करीब 30 कोल ब्लॉक है. इसमें से 16 कोल ब्लॉक पहले जिन कंपनियों को आवंटित हुए थे, उन्हें आजतक पर्यावरण मंजूरी नहीं मिली, और इस वजह से वहां खनन नहीं शुरू हो सका था. अलबत्ता, तीन कोल ब्लॉक ऐसे थे, जहां अदानी की कंपनी ज्वायंट वेंचर के तहत खनन का काम कर रही थी. इन तीन कोल ब्लॉक को पर्यावारणीय मंजूरी भी मिल गई थी. हालांकि, बाद में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इस मंजूरी को रद्द कर दिया था और अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यहां भी खनन कार्य रुका हुआ है.

बहरहाल, नई प्रक्रिया के तहत अब फिर से कोल ब्लॉक आवंटन का काम शुरू होने जा रहा है लेकिन हसदेव अरण्य क्षेत्र के गांववालों ने अभी से ही अपना विरोध दर्ज कराना शुरू कर दिया है. इस क्षेत्र में आने वाली करीब बीस ग्राम पंचायतों ने ग्राम सभा की बैठक कर के एक प्रस्ताव पारित किया है. इस प्रस्ताव में गांव वालों ने स्पष्ट रूप से इस क्षेत्र में खनन कार्य का विरोध किया है. यहां के निवासियों का कहना है कि चूंकि हमारे क्षेत्र में पेसा एक्ट(पंचायत एक्सटेंशन टू शिड्यूल एरिया एक्ट. यह आदिवासी इलाकों को विशेषाधिकार देता है) लागू है, इसलिए किसी भी कोल ब्लॉक के लिए जमीन अधिग्रहण करने से पहले सरकार के लिए यहां की ग्राम सभाओं की अनुमति लेना आवश्यक है. हसदेव अरण्य क्षेत्र में भी पेसा कानून लागू है. ग्राम सभा के इस प्रस्ताव के मुताबिक़ कोल ब्लॉक के आवंटन से पर्यावरण प्रभावित होगा, आदिवासी विस्थापित होंगे. यह प्रस्ताव कहता है कि किसी भी खनन परियोजना के आवंटन या नीलामी से पहले ग्रामसभा से पूर्व सहमति प्राप्त करनी जरूरी है. यहां के लोगों का मानना है कि जैव विविधता से समृद्ध इस वन्यक्षेत्र में किसी भी प्रकार की खनन नहीं होना चाहिए. छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन से जुड़े आलोक शुक्ला और प्रियांशु गुप्ता का मानना है कि छत्तीसगढ़ का हसदेव अरण्य का इलाका महत्वपूर्ण जैव विविधता वाला क्षेत्र है. प्रियांशु गुप्ता के मुताबिक़ देश के दूसरे इलाक़ों में 100 साल तक कोयले की आपूर्ति लायक खदान हैं. आलोक शुक्ला कहते है कि प्रकृति को नुकसान पहुंचा कर छत्तीसगढ़ के इस नो गो घोषित हो चुके क्षेत्र में कोयला खनन सही नहीं है.

इसके अलावा, हसदेव अरण्य बचाओ संघर्ष समिति इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री, वन एवं पर्यावरण मंत्री, कोयला मंत्री और आदिवासी मामलों के मंत्री से भी मिलने वाली है. बाक़ायदा, इनकी तरफ से छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के सदस्य प्रियांशु गुप्ता ने प्रधानमंत्री कार्यालय और उपरोक्त सभी मंत्रालय से मिलने के लिए समय भी मांगा है. चौथी दुनिया से बात करते हुए प्रियांशु गुप्ता ने बताया कि वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से उन्हें मुलाक़ात का समय भी मिल गया है. इस मुलाकात में हसदेव अरण्य बचाओ संघर्ष समिति के सदस्य भी शामिल होंगे. इस समिति में हसदेव अरण्य क्षेत्र के ग्रामीण शामिल हैं. दरअसल, यहां के लोगों की मुख्य चिंता यह है कि अब कोल ब्लाक के आवंटन और इसके लिए जरूरी जमीन अधिग्रहण की पूरी प्रक्रिया में उनकी भागीदारी, नए अध्यादेश (कोल माइनिंग/भूमि अधिग्रहण क़ानून में नए अध्यादेश के जरिए किए गए संशोधन) के आने के बाद से नगण्य हो गयी है. हसदेव अरण्य के आदिवासी, जो मूलरूप से गोंड आदिवासी है, यहां पड़ने वाले प्रभाव से चिंतित है. उन्हें इस बात की भी चिंता है की अगर एक बार सरकार ने नीलामी करा ली, कंपनियों से पैसे ले लिए तो उसके बाद उनकी ग्राम सभा की सहमति, पर्यावरण मंजूरी (एनवायरमेंटल क्लियरेंस) लेने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा.

बहरहाल, छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन इस नए अध्यादेश को कोर्ट में चुनौती देने पर भी विचार कर रहा है. प्रियांशु गुप्ता बताते हैं कि हम इस अध्यादेश को कोर्ट में इस आधार पर चुनौती देने पर विचार कर रहे हैं कि क्या इससे पेसा एक्ट का महत्व कम नहीं होता. इससे पहले हसदेव अरण्य बचाओ संघर्ष समिति ने हसदेव अरण्य सुरक्षा यात्रा भी निकाली थी. हसदेव अरण्य बचाओ संघर्ष समिति की यह यात्रा कोरबा, सरगुजा जिले के ग्रामीण इलाकों में चलाई गयी ताकि लोगों को पेसा एक्ट और वनाधिकार कानून 2006 के बारे में जागरूक किया जा सके. यात्रा का असर ये हुआ है कि गांववालों ने एक स्वर में अपने जंगल, जमीन किसी भी परियोजना के लिए नहीं देने की बात कही है. लोगों को लगता है कि कोल ब्लॉक के खनन से उनकी आजीविका छिन जाएगी, विस्थापन होगा और उनकी आदिवासी संस्कृति भी खतरे में पड़ जाएगी. लेकिन, सबसे बड़ा सवाल है की क्या इन लोगों के विरोध का कोई मायना है. क्योंकि, नए कोल ऑर्डिनेंस में ऐसे प्रावधान है जिससे इन ग्रामीनों के विरोध के कोई मायने नहीं रहेंगे. इस अध्यादेश में कहा गया है कि कोयला खनन का विरोध करने पर प्रति दिन एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. अगर इस तरह का काम दोबारा होता है तो प्रति दिन दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. ■

shashishekhar@chauthiduniya.com

प्रस्ताव पारित करने वाली ग्राम सभाओं के नाम

हंसदेव अरण्य क्षेत्र की मोरगा, मदनपुर, खिलती, धज्जाक, उचलेंगा, घाटवल्ला, साली, हरिहरपुर, फतेहपुर, सेंदू, सुष्कम, पटोगिया, पुटा, पतुरिया डांड, अरसिया और करहियापारा ग्रामसभा. मांड रायगढ़ की चार ग्राम सभा नरकारोह, करौंधा, दुलियामोड़ और चैनपुर. ■

कितना कोयला है छत्तीसगढ़ में

छत्तीसगढ़ राज्य में भारत का कुल 16 फीसदी कोयला है. यहां के रायगढ़ा, सरगुजा, कोरिया और कोरबा जिले के 12 कोलफील्ड में करीब 44483 मिलियन टन कोयले का भण्डार है. अकेले यह राज्य राष्ट्रीय उत्पादन का 18 फीसदी हिस्सा कोयला उत्पादित करता है. ज्यादातर कोयला पावर ग्रेड का है यानी इनका ज्यादातर इस्तेमाल थर्मल पावर बनाने के लिए किया जाता है. ■

कोल ऑर्डिनेंस आ चुका है, कोल ब्लॉक आवंटन के लिए आवेदन मंगवाने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है और अगले दो-तीन महीने में आवंटन का काम भी हो जाएगा, कोल ब्लॉक की नीलामी के लिए 31 जनवरी तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं और अगले साल 23 मार्च तक नीलामी की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, लेकिन, इस बीच खबर है कि छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य क्षेत्र की करीब 20 ग्राम सभाओं ने एक प्रस्ताव पारित कर यह साफ़ कर दिया है कि वे अपने क्षेत्र में होने वाले कोल ब्लॉक आवंटन और कोयला खनन का विरोध करेंगे.

हसदेव अरण्य संरक्षित क्षेत्र क्यों घोषित नहीं होता

हसदेव अरण्य वन क्षेत्र उत्तरी छत्तीसगढ़ कोरबा और सरगुजा जिले में फैला हुआ है. यहां मध्य भारत के कुछ बड़े वन क्षेत्रों में से एक है. जैवविविधता से भरे इस क्षेत्र में कई दुर्लभ जड़ी-बूटियां और वन्यजीव आदि पाए जाते हैं. इस समृद्ध पर्यावरणीय क्षेत्र में, कोयला मंत्रालय के मुताबिक, 1878 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में एक बिलियन मीट्रिक टन कोयला का भंडार है. इसमें से 1502 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र वन क्षेत्र है. 2010 में वन एवं कोयला मंत्रालय की एक रिपोर्ट आई थी. इस रिपोर्ट के आधार पर हसदेव अरण्य क्षेत्र को नो गो एरिया घोषित कर दिया गया. इसका अर्थ यह हुआ कि इस क्षेत्र में कोई कंपनी जाकर खनन का काम नहीं कर सकती. इससे पहले भी राज्य सरकार ने हसदेव अरण्य क्षेत्र को हाथी अभयारण्य घोषित करने के लिए एक प्रस्ताव पारित कर के केंद्र सरकार को भेजा था. वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने इस पर अपनी मुहर भी लगा दी थी. लेकिन राज्य सरकार ने इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया. ये कहा जाता है कि सीआईआई ने छत्तीसगढ़ में कोयले की प्रचुरता को देखते हुए इस फैसले पर आपत्ति जताई थी. दरअसल, एक बार अगर कोई वन्य क्षेत्र संरक्षित क्षेत्र या राष्ट्रीय अभ्यारण्य घोषित हो जाता है तो उस इलाके में खनन कार्य नहीं किया जा सकता है. ■

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रो. राम गोपाल यादव ने चार जनवरी को शाम पौने चार बजे विधान परिषद प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी. पार्टी की ओर से घोषित आठ प्रत्याशियों में यशवंत सिंह का नाम भी शामिल था. इस सूची पर देखते ही देखते प्रदेश भर में आग लग गई. कार्यकर्ताओं की तो छोड़िए, नेताओं को भी यह समझ में नहीं आया कि पार्टी आलाकमान यह कौन–सी राजनीति करने लगा. एक आम कार्यकर्ता को भी पता है कि विधान परिषद में यशवंत सिंह का कार्यकाल 6 जुलाई, 2016 तक है.

विधान परिषद चुनाव : सपा ने जारी कर दी गलत लिस्ट

चेहरा देखकर बंटे टिकट, कर्मठ हाशिये पर

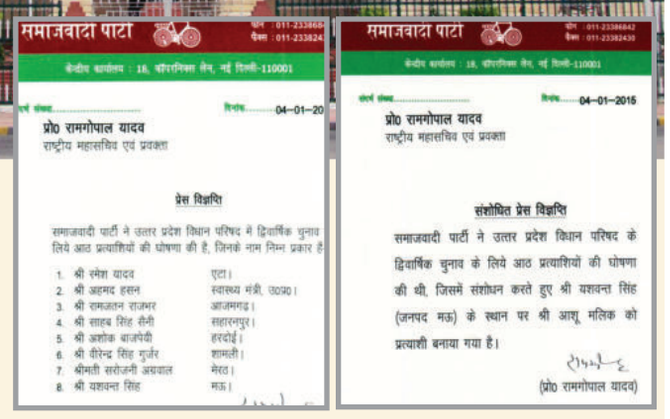

प्रभात रंजन दीन

सत्ता और सैफई के आनंद में डूबी समाजवादी पार्टी को यह भी होश नहीं रहा कि 23 जनवरी को होने वाले विधान परिषद चुनाव में किसे प्रत्याशी बनाना है और किसे नहीं. जिस विधान परिषद सदस्य का कार्यकाल अभी डेढ़ साल बाकी था, उसे भी सपा का आधिकारिक प्रत्याशी घोषित कर दिया गया. सैफई में नाच की रफ्तार कम हुई और किसी ने याद दिलाया, तब नेताओं को होश आया. आनन–फानन सूची बदली गई और फिर नए प्रत्याशी का नाम घोषित किया गया. सपा प्रत्याशियों की नई सूची भी एकाधिकारवाद का उत्पाद है. इससे सपा कार्यकर्ताओं में बहुत नाराज़गी है. उधर, बहुजन समाज पार्टी अलग ही बौखलाहट में है. शिराजा बिखर रहा है. डॉ. अखिलेश दास ने कह दिया कि मायावती टिकट और पद बेचती हैं, तो उन्हें बहुत खराब लगा था. अब जुगल किशोर ने उसकी पुष्टि कर दी, तो सामंतशाहाना अंदाज़ वाली मायावती को दलित याद आने लगे. भारत रत्न की घोषणा के एक पखवाड़े के बाद भारत रत्न को लेकर शुरू की गई दलित–सियासत दरअसल पार्टी के अंदर के भूचाल और सोशल इंजीनियरिंग की खीलें बिखरने की बौखलाहट से ही पैदा हुई. बसपा ने विधान परिषद चुनाव के लिए अपने प्रत्याशी भी इसी बौखलाहट में घोषणा होने के पहले ही कई बार बदल दिए.

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रो. राम गोपाल यादव ने चार जनवरी को शाम पौने चार बजे विधान परिषद प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी. पार्टी की ओर से घोषित आठ प्रत्याशियों में यशवंत सिंह का नाम भी शामिल था. इस सूची पर देखते ही देखते प्रदेश भर में आग लग गई. कार्यकर्ताओं की तो छोड़िए, नेताओं को भी यह समझ में नहीं आया कि पार्टी आलाकमान यह कौन–सी राजनीति करने लगा. एक आम कार्यकर्ता को भी पता है कि विधान परिषद में यशवंत सिंह का कार्यकाल 6 जुलाई, 2016 तक है. फिर यह क्या हुआ! सपा के एक वरिष्ठ नेता ने यह तस्दीक की कि खुद यशवंत सिंह तक चक्करघिन्नी हो गए कि यह कौन–सी विशेष कृपादृष्टि उन्हें प्राप्त हो गई. कोई यह सपने में भी नहीं सोच सकता था कि विधान परिषद के लिए प्रत्याशी तय करने वाले नेता अलग ही सत्ता पिनक में रहते हैं और उन्हें अपनी ही पार्टी के विधान परिषद सदस्यों का कार्यकाल नहीं पता रहता. नेताओं से लेकर पार्टी दफ्तर तक के फोन घनघना उठे. यहां तक कि पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव के आवास तक फोन पहुंचने लगे. फिर मुलायम के यहां से फोन करके यशवंत सिंह से ही उनका कार्यकाल पूछा गया. मुलायम के आवास पर तैनात एक अधिकारी ने कहा कि नेताजी ने खुद यशवंत सिंह से बातचीत की. तब जाकर शाम के क़रीब आठ बजे यशवंत सिंह का नाम हटाकर आशू मलिक को प्रत्याशी बनाए जाने की घोषणा हुई. यह संशोधन भी सपा के राष्ट्रीय महासचिव प्रो. राम गोपाल यादव ने अपने कर–कमलों से ही किया. पार्टी के कई नेताओं ने कहा, इस भारी, किंतु मजाकिया भूल को सुधार कर जारी हुई सूची में से अभी कई और नाम हट सकते हैं और जुड़ सकते हैं, आप देखते जाइए.

बहरहाल, आशू मलिक को सूची में शामिल करते हुए समाजवादी पार्टी ने अहमद हसन, रमेश यादव, डॉ. अशोक वाजपेयी, सरोजनी अग्रवाल, राम जतन राजभर, साहब सिंह सैनी एवं वीरेंद्र सिंह गुर्जर को विधान परिषद के लिए अपना प्रत्याशी घोषित किया है. अहमद हसन, रमेश यादव एवं सरोजनी अग्रवाल को विधान परिषद के लिए एक्सटेंशन मिला है, जबकि अन्य पांच प्रत्याशी नए हैं. प्रत्याशियों के चयन को लेकर पार्टी गलियारे में जो चर्चा है, उसके मुताबिक, इस चयन में राम गोपाल का निर्णय एकतरफ़ा चला. मुख्यमंत्री की टीम के केवल एक सदस्य आशू मलिक को सूची में स्थान मिला, वह भी भूल सुधार की गुंजाइश के बाद. डॉ. अशोक वाजपेयी को विधान परिषद का प्रत्याशी बनाए जाने के पीछे पार्टी नेताओं का अपनी थू–थू से बचने का प्रयास मुख्य वजह है. लोकसभा चुनाव में लखनऊ संसदीय क्षेत्र से सपा के बुद्धिजीवी एवं साफ़–सुथरी छवि वाले डॉ. अशोक वाजपेयी को प्रत्याशी बनाया गया था, लेकिन भाजपा की तरफ़ से राजनाथ सिंह को उम्मीदवार बनाए जाने के बाद सपा ने डॉ. वाजपेयी को हटाकर अखिलेश मिश्र को प्रत्याशी बना दिया था. पार्टी नेताओं का ही कहना था कि राजनाथ सिंह से मुलायम की नज़दीकियों को देखते हुए कड़ी टक्कर देने वाले प्रत्याशी को हटाकर राजनाथ का रास्ता आसान कर दिया गया था. इससे पार्टी नेताओं की पार्टी के अंदर ही कड़ी आलोचना हुई थी. फिर पार्टी ने डॉ. अशोक वाजपेयी को राज्यसभा का मौक़ा भी नहीं दिया. इससे नेताओं के ख़िलाफ़ पार्टी में घोर नाराज़गी बढ़ी. इस बार विधान परिषद के लिए डॉ. अशोक वाजपेयी को अपना प्रत्याशी घोषित कर पार्टी आलाकमान ने अपनी झेंप ही मिटाई है.

अहमद हसन अखिलेश सरकार के वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री हैं, लिहाजा उनके एक्सटेंशन की तार्किक वजह है. लेकिन, रमेश यादव और सरोजनी अग्रवाल के एक्सटेंशन से पार्टी नेताओं में काफी टेंशन है. इसे वे राम गोपाल यादव का एकतरफ़ा निर्णय मानते हैं. यह चर्चा आम है कि क्या पार्टी में ऊर्जावान, प्रभावी, जनप्रिय एवं तेज–तर्रार नेताओं का अभाव हो गया है कि प्रभावहीन एवं घिसे–पिटे लोगों को इस तरह मौक़ा दिया जा रहा है. पार्टी कार्यकर्ता रमेश यादव, सरोजनी अग्रवाल एवं राम जतन राजभर जैसे उम्मीदवारों पर हैरत जताते हैं. पार्टी कार्यकर्ता कहते हैं कि रमेश यादव को तो आलाकमान से रिश्तेदारी का उपहार दिया गया है. अति पिछड़ों में लौटन राम निषाद, विद्यावती राजभर या सुशीला राजभर, यादवों में डॉ. उमा शंकर यादव, सुनील यादव एवं राम वृक्ष यादव जैसे नेताओं को लेकर पार्टी के कार्यकर्ता उम्मीद लगाए थे कि विधान परिषद के लिए उन्हें मौक़ा मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. साहब सिंह सैनी बसपा, भाजपा और कांग्रेस जैसे दलों की परिक्रमा करते हुए 2014 में सपा में शामिल हुए थे. सपा ने उन्हें इस बहुदलीय परिक्रमा का पुरस्कार दिया. अखिलेश सरकार में राज्य मंत्री रह चुके आशू मलिक के बारे में तो पार्टी कार्यकर्ताओं का आकलन था कि उन्हें विधान परिषद के लिए मौक़ा मिल सकता है, लेकिन साहब सिंह सैनी का नाम आने से पश्चिमी उत्तर प्रदेश, खासकर सहारनपुर में सपा के कई वरिष्ठ नेताओं एवं पूर्व मंत्रियों की उम्मीदें धराशायी हो गईं. विधान परिषद के लिए ज़िला अध्यक्ष चौधरी जगपाल दास प्रबल दावेदार माने जा रहे थे. जगपाल दास सपा के आजीवन प्रदेश अध्यक्ष रहे स्वर्गीय चौधरी राम शरण दास गूजर के बेटे हैं.

सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव सहारनपुर में राम शरण दास के नाम पर विश्वविद्यालय बनवाने का वादा भी कर चुके हैं, लेकिन उनके जैसे प्रतिबद्ध सपाई के बेटे को मौक़ा न दिए जाने से पार्टी नेता एवं कार्यकर्ता हतप्रभ हैं. पूर्व राज्य मंत्री संजय गर्ग लोकसभा चुनाव से पहले बसपा छोड़कर सपा में शामिल हो गए थे. सपा आलाकमान ने उन्हें उपचुनाव में पार्टी प्रत्याशी घोषित किया था. चुनाव हारने के बावजूद गर्ग वोट बैंक बढ़ाने में सफल रहे. ऐसे में उन्हें विधान परिषद के लिए मौक़ा दिए जाने की लोगों को उम्मीद थी. पार्टी कार्यकर्ताओं को आलाकमान के दोरंगी फ़ैसले पर आश्चर्य है. वोट बैंक बढ़ाने वाले संजय गर्ग को मौक़ा नहीं दिया गया. जबकि उपचुनाव में सहारनपुर के चुनाव प्रभारी के बतौर वीरेंद्र सिंह गुर्जर को वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए पुरस्कृत किया गया. नगर विकास मंत्री आजम खान के खास एवं पूर्व राज्य मंत्री सरफराज खान को भी इस सूची से झटका लगा. मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन पर रामपुर में उनके इर्द–गिर्द घूमते रहे सरफराज को मिला झटका आजम खान के लिए सांकेतिक झटका माना जा रहा है. गुर्जर समाज के झंडाबरदार माने जाने वाले पूर्व मंत्री चौधरी यशपाल सिंह के पुत्र चौधरी रुद्रसेन भी विधान परिषद के लिए भाग–दौड़ कर रहे थे. एक जनवरी को उन्होंने बड़ी सभा करके अपनी जन शक्ति भी दिखाई, लेकिन पार्टी ने उन्हें मौक़ा नहीं दिया. सकल जैन समाज के अध्यक्ष राजेश जैन भी कतार में थे. विधानसभा उपचुनाव में कैबिनेट मंत्री बलराम सिंह यादव की पहल पर राजेश जैन ने बड़ी तादाद में जैनियों को सपा से जोड़ा. लखनऊ की समीक्षा बैठक में मुलायम सिंह ने सहारनपुर के जैन समाज का आभार भी जताया था. लेकिन, बलराम सिंह यादव की सिफारिश के बावजूद राजेश जैन को विधान परिषद के लिए मौक़ा नहीं दिया गया. पूर्व मंत्री रशीद मसूद के बेटे शादान मसूद की एमएलसी बनने की दौड़ भी नाकाम साबित हुई.

सरोजनी अग्रवाल को विधान परिषद के लिए एक्सटेंशन मिलने से वैश्य समुदाय के प्रमुख दावेदार सुरेंद्र मोहन, गोपाल अग्रवाल, संजय गर्ग एवं संदीप बंसल जैसे नेताओं का पटाक्षेप हो गया. पिछड़ों में डॉ. राजपाल कश्यप, संजय लाठर, उमा शंकर यादव, राम वृक्ष यादव एवं सुनील साजन जैसे नेताओं का पटाक्षेप हुआ, तो मुस्लिमों में जावेद आब्दी और जफर अमीन डक्कू जैसे नेताओं का. भूमिहार शिरोमणि कुंअर रेवती रमण के पुत्र उज्ज्वल रमण सिंह और जुझारू नेता आनंद भदौरिया की दावेदारी धराशायी होने से क्रमश: भूमिहार और राजपूत समुदाय में गहरी नाराज़गी है. ■

feedback@chauthiduniya.com

टूटने की कगार पर बसपा

विधानसभा चुनाव में हाशिये पर पहुंची और लोकसभा चुनाव में पूरी तरह विलुप्त हो चुकी बहुजन समाज पार्टी अब अपना बिखराव नज़दीक देखकर बौखला गई है. जिस ब्राह्मण समुदाय को लेकर मायावती ने सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला फिट करके सत्ता हासिल की थी, वह ब्राह्मण समुदाय बड़ी तेजी से भाजपा और सपा की तरफ़ खिसका है. दलित समुदाय में एक जाति विशेष (मायावती की जाति) को छोड़कर अन्य दलित जातियां भाजपा की तरफ़ खिसकी हैं. बसपा के कई बड़े नेता भाजपा और सपा से सीधे संवाद में हैं. पार्टी के टूटने की आशंका गहराती जा रही है. इन हालात को देखते हुए मायावती को एक बार फिर से दलित कार्ड खेलने की याद आई. इसी आपाधापी में भारत रत्न की सियासत खेली गई, लेकिन यह कार्ड फेंकने में पखवाड़े भर की देरी हो चुकी थी. बसपा के ही कार्यकर्ता बुदबुदाते हैं कि जब भारत रत्न की घोषणा हुई थी, तब बहन जी कहां थीं, क्यों चुप थीं, तब अटल जी के नाम पर क्यों सहमति जता रही थीं और उनमें उन्हें ब्राह्मण क्यों नहीं दिख रहा था. मायावती को पार्टी के अंदर चल रही सुगबुगाहटों का सही अंदाज़ा बाद में लगा. बसपा के वरिष्ठ नेता एवं राज्यसभा सदस्य जुगल किशोर की बगावत की अंदर–अंदर चल रही तैयारियों की भनक लगते ही मायावती बौखला गईं. इसी में विधान परिषद के प्रत्याशियों के चयन में कई–कई फेरबदल किए गए और केवल नसीमुद्दीन सिद्दीकी को एक्सटेंशन देकर बुलंदशहर के धर्मवीर सिंह अशोक एवं गाजियाबाद के प्रदीप सिंह जैसे नए उम्मीदवारों को मौक़ा दे दिया गया. अशोक कुमार सिद्धार्थ और धर्म प्रकाश भारती के मुंह से जलेबी खिसक गई. राज्यसभा चुनाव में भी डॉ. अखिलेश दास गुप्ता और ब्रजेश पाठक को एक्सटेंशन न दिए जाने से क्रमश: वैश्य और ब्राह्मण समुदाय मायावती से खासा नाराज़ चल रहा था. डॉ. अखिलेश दास ने तो इसी वजह से पार्टी से इस्तीफ़ा भी दे दिया था. बसपा के मौजूदा राज्यसभा सदस्य जुगल किशोर की खुली बगावत को भी पार्टी के टूटने की स्थिति में आने से ही जोड़कर देखा जा रहा है. जुगल किशोर ने मीडिया से बाकायदा कहा कि बसपा प्रमुख मायावती विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा और राज्यसभा के लिए टिकट बेचती हैं. जुगल किशोर ने कहा कि बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती दलित की बेटी नहीं, दौलत की बेटी बनकर रह गई हैं. वह चुनाव में पार्टी का टिकट देने के लिए मोटी रकम लेती हैं. पार्टी के बिहार और दिल्ली के सह–प्रभारी अमित तिवारी ने भी इसी अंदाज़ में मायावती पर हमला बोला और समर्थकों सहित पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफ़ा देने का ऐलान किया. जुगल किशोर का राज्यसभा का कार्यकाल चार जुलाई, 2016 तक है. उन्होंने पार्टी या राज्यसभा से इस्तीफ़ा देने की घोषणा नहीं की है. राज्यसभा का कार्यकाल पूरा होने तक अब जुगल किशोर बहुजन समाज पार्टी के गले में हड्डी की तरह चुभते रहेंगे. पार्टी से निकाले जाने पर भी उनकी राज्यसभा की सदस्यता बनी रहेगी. ■

सपा–बसपा ने फंसाया विधान परिषद चुनाव

समाजवादी पार्टी की ओर से विधान परिषद के लिए आठ प्रत्याशी मैदान में उतारे जाने से चुनाव काफी रोचक और खींचतान वाला हो गया है. अब निर्विरोध चयन के बजाय बाकायदा मतदान का रास्ता साफ़ हो गया दिखता है. 30 जनवरी को उत्तर प्रदेश में 12 विधान परिषद सदस्यों का छह साल का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है. इन्हीं सीटों के लिए 23 जनवरी को चुनाव होना है. 403 सदस्यों वाली राज्य विधानसभा में सपा के 232, बसपा के 80, भाजपा के 39, कांग्रेस के 28, रालोद के आठ, पीस पार्टी के चार, निर्दलीय छह, कौमी एकता दल के दो, तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एवं अपना दल के एक-एक और एक मनोनीत सदस्य हैं. एक विधान परिषद सदस्य के लिए 34 विधायकों का समर्थन ज़रूरी है. ऐसे में 232 सदस्यों के साथ सपा अपने सात सदस्यों को आसानी से जिता लेगी, पर उसके एक उम्मीदवार के लिए निर्दलीय और पीस पार्टी से वोट मैनेज करने पड़ेंगे. इसी तरह बसपा अपने दो सदस्यों को जिता लेगी, लेकिन तीसरे के लिए उसे भी वोट मैनेज करने पड़ेंगे. भाजपा अपना एक सदस्य विधान परिषद पहुंचा लेगी. ■

जुगल किशोर भ्रष्टाचारी: मौर्य

बसपा सांसद जुगल किशोर के आरोपों को नकारते हुए पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि बेटे का विधानसभा टिकट कटने की वजह से जुगल किशोर बसपा प्रमुख के ख़िलाफ़ अनाप-शनाप बोल रहे हैं. पिछले विधानसभा चुनाव में पूर्वी उत्तर प्रदेश में पार्टी के खराब प्रदर्शन के लिए जुगल किशोर को ज़िम्मेदार ठहराते हुए मौर्य ने कहा कि कुछ कार्यकर्ताओं का आरोप है कि बसपा में रहते हुए जुगल किशोर ने अपने पद का दुरुपयोग करके लखीमपुर और लखनऊ में करोड़ों रुपये की संपत्ति बनाई. जुगल किशोर पार्टी से निष्कासित नेता बाबू सिंह कुशवाहा की भाषा बोल रहे हैं, जिनका काफी पैसा जुगल किशोर के ग़लत कार्यों में लगा हुआ है. मौर्य ने यह भी कहा कि जुगल किशोर के गृह जनपद के लोगों का मानना है कि वह जल्दी ही भाजपा में शामिल होंगे. उन्होंने कहा कि जिन्होंने भी पार्टी के साथ गद्दारी की है, वे राजनीति से ख़त्म हो गए. ■

> मुनव्वर राना ने कहा, जब मेरी उम्र प्यार मोहब्बत की शायरी करने की थी तब मेरा ध्यान बारात में गैस बत्ती उठाए बच्चे पर गया. मां की ममता, उसकी कुर्बानी और औलाद के प्रति उसका असीम प्यार भी मेरी शायरी का विषय बना. राना मानते हैं कि कूड़ा–करकट, रेल के डिब्बों में झाड़ू लगाते बच्चे और फुटपाथ पर बिना नींद की गोली खाए निश्चिंत सोते हुए मजदूरों को खूबसूरती के साथ शायरी का विषय बनाया जा सकता है.

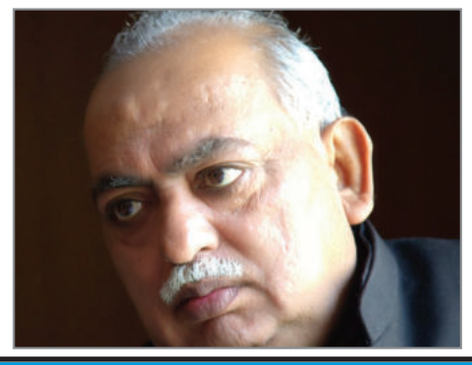

छत्तीसगढ़ निकाय चुनाव : किसकी जीत, किसकी हार

सुषमा गुप्ता

छत्तीसगढ़ के नगरीय निकाय के नतीजे सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ गए. क्यों गए, इस पर मंथन शुरू हो चुका है. लेकिन जिन हालात में यह नतीजे ख़िलाफ गए उसने चौंकाने से ज़्यादा पार्टी को चिंतित कर दिया है. जब देशभर में कांग्रेसमुक्त देश करने के लिए मोदी का अश्वमेध का घोड़ा पूरे देश में दौड़ रहा है तब भाजपा के सबसे मजबूत गढ़ बन चुके छत्तीसगढ़ में कैसे रुक गया? वह भी तब जब तीन–तीन विधानसभा और लोकसभा चुनाव में भाजपा को एकतरफा जीत दिलाने वाले रमन सिंह ने प्रदेश में हर जगह खुद नगरीय निकायों को कांग्रेस मुक्त बनाने के नारे के साथ वोट मांगे थे. कांग्रेस के सामने एक समस्या यह भी थी कि उनके सबसे बड़े जनाधार वाले नेता अजीत जोगी ने बिलासपुर के टिकट विवाद के बाद खुद को प्रचार से अलग कर लिया था. जोगी के बाद कांग्रेस में कोई नेता नहीं बचा था, जिसकी पकड़ पूरे प्रदेश में हो.

चुनाव परिणाम आने के एक दिन पहले कांग्रेस खेमे के तमाम नेता और भाजपा के नेता यही मान रहे थे कि अपने कुशल चुनावी मैनेजमेंट और रमन सिंह व नरेंद्र मोदी की इमेज के सहारे छत्तीसगढ़ में भाजपा ज्यादातर सीटों पर काबिज होगी. लेकिन 4 जनवरी को जब परिणाम आए तो कहानी पूरी तरह से पलट गई. पिछली बार की तुलना में भाजपा के हाथ से 2 निगम निकल गए. नगर पालिका में कांग्रेस भाजपा से आगे और नगर पंचायत में काफी आगे निकल गई. दो निगमों पर निर्दलीयों की जीत हुई, जिसमें से एक कांग्रेस से जुड़ा है.

नगरीय निकायों में खराब प्रदर्शन ने संघ से लेकर भाजपा के शीर्ष नेतृत्व दोनों को परेशानी में डाल दिया है. हार के कारणों की समीक्षा की जा रही है. कोई भितरघात को इसकी

> **नगरीय निकायों में खराब प्रदर्शन ने संघ से लेकर भाजपा के शीर्ष नेतृत्व दोनों को परेशानी में डाल दिया है. हार के कारणों की समीक्षा की जा रही है. कोई भितरघात को इसकी वजह बता रहा है तो कोई प्रत्याशी चयन को इसकी वजह मान रहा है लेकिन इस हार को रमन सिंह सरकार के ख़िलाफ जनाधार माना जा रहा है. तीसरी बार सत्ता हासिल करने के बाद भाजपा की राज्य सरकार ने एक के बाद एक कई फैसले लिए, जिनका खूब विरोध हो रहा था.**

वजह बता रहा है तो कोई प्रत्याशी चयन को इसकी वजह मान रहा है लेकिन इस हार को रमन सिंह सरकार के ख़िलाफ जनाधार माना जा रहा है. तीसरी बार सत्ता हासिल करने के बाद भाजपा की राज्य सरकार ने एक के बाद एक कई फैसले लिए, जिनका खूब विरोध हो रहा था. पहले लाखों लोगों के राशनकार्ड रद्द कर दिए. उसके बाद धान की खरीद की सीमा घटा दी गई. इस फैसले के खिलाफ पूरे प्रदेश में आंदोलन हुआ. रही सही कसर बिलासपुर में नसबंदी कांड और उस पर स्वास्थ्यमंत्री अमर अग्रवाल और मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के बयानों ने पूरी कर दी.

नसबंदी कांड और सुकमा नक्सली हमले की हताशा से सरकार उबरी भी नहीं थी कि नगरीय निकाय चुनाव आ गए. हालात को भांपते हुए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह खुद रायपुर आए और निकाय चुनाव पर पार्टी की रणनीति तैयार की. उन्होंने कार्यकर्ताओं को स्पष्ट संदेश दे दिया था कि आलाकमान निकाय चुनाव में हार को बर्दाश्त नहीं करेगी.

तमाम बातों के बाद भी जोगी के चुनाव से हटने और अपने बेहतर मैनेजमेंट कौशल के बूते भाजपा को उम्मीद थी कि वह चुनाव मोदी और रमन के नाम के सहारे निकाल लेगी. ऐसा मानने की एक बड़ी वजह थी कि राशनकार्ड पर विरोध के बाद सरकार ने राशन चालू कर दिया था. जबकि नसबंदी कांड और धान के मसलों का संबंध गांवों से था, लिहाज़ा पार्टी यह मानकर चल रही थी कि इसका असर नगरीय क्षेत्रों में नहीं होगा. भाजपा को मोदी के तिलस्म का भी सहारा था. चुनाव से पहले झारखंड के नतीजे आने थे. पार्टी को लगा कि नतीजे पक्ष में आएंगे तो माहौल बन जाएगा और उसी माहौल में पार्टी जीत हासिल कर लेगी.

इन सब हालात के बीच छत्तीसगढ़ में भाजपा का चेहरा बन चुके रमन सिंह ने दस दिनों का अपना तूफानी दौरा किया. उन्होंने मोदी के कांग्रेस मुक्त देश की तर्ज पर कांग्रेस मुक्त नगरीय निकाय का नारा दिया. दूसरी तरफ प्रचार में कांग्रेस पूरी तरह से स्टारविहीन दिखाई दी. प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल ने राज्य के मध्य और दक्षिणी इलाके में प्रचार किया जबकि नेता प्रतिपक्ष टीएस सिंहेदव ने उत्तरी हिस्सों में कमान संभाल रखी थी. परिणाम आने के बाद सत्ता और राजनीति के नए समीकरण बनते और पुराने टूटते दिखाई दे रहे हैं. परिणामों के बाद नेताओं के बयानों से इसके संकेत भी मिलने लगे. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल ने रमन सिंह से इस्तीफा मांगकर उन पर दबाव बनाने की कोशिश की तो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष धरमलाल कौशिक ने ज्यादा संख्या में भाजपा पार्षदों के जीतने का दावा करके हार पर रफू लगाने की कोशिश की.

भाजपा में हार पर मंथन का दौर चल रहा है. रमन सिंह ने खुद ही कमान अपने हाथ में लेकर, पार्षद या मेयर पर नहीं, अपने नाम पर वोट देने की अपील की थी. ज़ाहिर है यह हार उनकी लोकप्रियता कम होने का संकेत देती है. जब से मनोहर पर्रिकर को गोवा से दिल्ली बुलाया गया है तब से ये चर्चा जोरों पर है कि अगला नंबर रमन सिंह का भी हो सकता है. हालांकि रमन सिंह इससे इनकार करते रहे हैं. लेकिन नसबंदी कांड और सुकमा नक्सल हमले के बाद राष्ट्रीय स्तर पर उनकी छवि काफी फीकी पड़ी है. उनके विरोधी कैंप के माने जाने वाले नेता रमेश बैस, बृजमोहन अग्रवाल, प्रेम प्रकाश पांडेय की सक्रियता दिल्ली में काफी बढ़ी है. इससे भी इस बात को हवा मिलती रही है दिल्ली में रमन की पहुंच कमजोर हो रही है. अब नगरीय निकाय चुनाव की हार के बाद उनके विरोधियों की मुहिम तेज हो जाएगी.

दूसरी तरफ कांग्रेस की कामयाबी से दिल्ली भी गदगद है. लगातार हार से हताश आलाकमान को आशा की एक किरण छत्तीसगढ़ की कामयाबी से मिली है. मध्यप्रदेश की इकाई को छत्तीसगढ़ से सबक लेने की सलाह दी जा रही है. इस कामयाबी से प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल और नेता प्रतिपक्ष टीएस सिंहदेव गदगद हैं. जब अजीत जोगी के सबसे बड़े विरोधी भूपेश बघेल को विधानसभा चुनाव में हार के बाद प्रदेश की कमान दी गई थी तो यह चर्चा का विषय रहा कि क्या आलाकमान अब जोगी को हाशिए पर डालना चाहता है. क्योंकि विधानसभा चुनाव से पहले दोनों नेताओं के बीच घमासान हो चुका था. जोगी भूपेश बघेल के क्षेत्र में जाकर उनके खिलाफ प्रचार कर चुके थे तो भूपेश ने जोगी की शिकायत आलाकमान से कर दी थी.

अध्यक्ष बनते ही भूपेश जोगी की दमदारी को कमजोर करने में लग गए. एक एक करके उन्होंने कई ऐसे फैसले लिये जिससे ये संकेत मिला कि वे जोछो' मुहिम पर लगे हैं. सबसे पहले उन्होंने विधानसभा में विपक्ष के नेता टीएस सिंहदेव और प्रदेश में दूसरे सबसे कद्दावर कांग्रेसी चरणदास महंत का समर्थन लिया फिर जोगी के समर्थकों में सेंधमारी शुरु की. बदरुद्दीन कुरैशी, ताम्रध्वज साहू जैसे कम जोगी कट्टर नेताओं को उन्होंने अपने खेमे में शामिल कर लिया जबकि जोगी के कट्टर समर्थकों को एक एक करके किनारे लगाते गए. जोगी की ताकत रहे एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस के रही है. भूपेश बघेल ने विकास उपाध्याय और देवेंद्र यादव के जरिए दोनों संगठनों पर अपनी पकड़ मज़बूत की. एनएसयूआई चुनाव में जोगी खेमे को पहली बार पटखनी मिली. जोगी के खिलाफ अब से पहले ऐसी गुस्ताखी करने का साहस कोई कांग्रेसी नहीं दिखा पाया था. लिहाज़ा भूपेश और टीएस ने जमीन पर काफी काम किया. सड़क से सदन तक राज्य सरकार को घेरते हुए कई आंदोलन खड़े किए. जोगी के गृह जिले में नसबंदी कांड पर भूपेश बघेल रात में ही पहुंच कर राज्य सरकार के खिलाफ आंदोलन खड़ा कर दिया. लेकिन जोगी भी खामोश नहीं बैठे है. जोगी को जानने वाले कहते हैं कि सिर्फ एक चुनाव के परिणाम जोगी की राजनीति में दखल को कमतर नहीं कर सकते. जोगी ने इसके संकेत भी दे दिए. परिणाम आने के फौरन बाद आया उनका बयान यही बताता है. उन्होंने कहा कि अगर वे होते तो जीत और बड़ी होती. ■

feedback@chauthiduniya.com

साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता मुनव्वर राना से खास बातचीत

बस एक मां है जो मुझसे खफा नहीं होती...

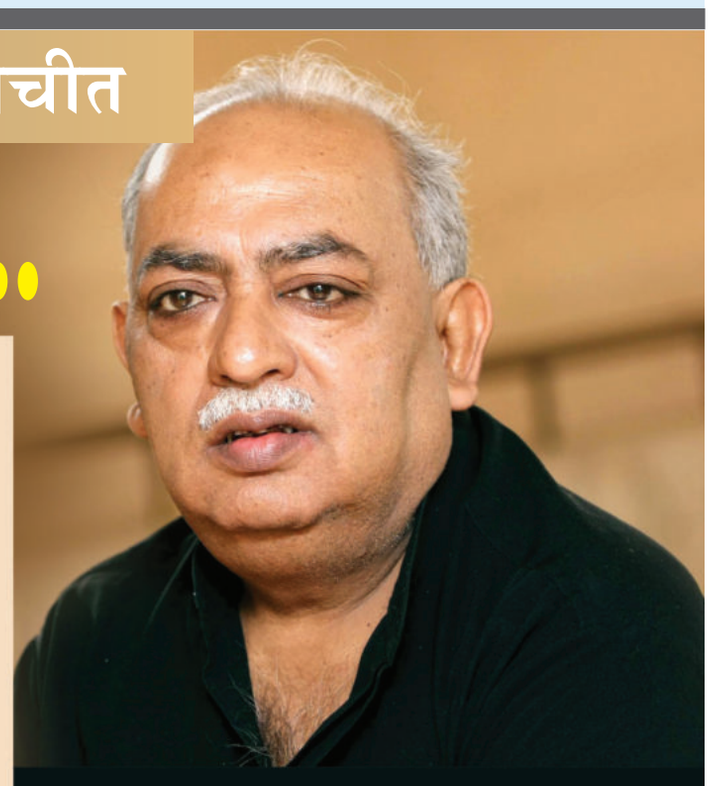

विवेक त्रिपाठी

साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाज़े गए देश के प्रख्यात शायर मुनव्वर राना ने कहा कि शायरी पर हमेशा से इल्ज़ाम लगता रहा है कि वह कच्चे गोश्त की दुकान है. शायरी को इस दलदल से बाहर निकालने के लिए ही उन्होंने अपनी शायरी में मां जैसे पवित्र रिश्ते को तरजीह देने की शुरुआत की. राना इस बात को बड़ी बेबाकी से स्वीकार करते हुए हैं कि जब तुलसीदास की महबूबा राम हो सकते हैं तो मेरी महबूबा मेरी मां क्यों नहीं हो सकती है. इसीलिए राना ने अपनी शायरी में मां को एक आदर्श के रूप में लोगों के सामने पेश करने का सिलसिला शुरू किया.

प्रख्यात शायर मुनव्वर राना ने विशेष बातचीत में अपने जीवन के कई अनछुए पहलुओं को भी उजागर किया. उन्होंने कहा कि धर्मांतरण और लव जिहाद दोनों भारतीय जनता पार्टी की देन हैं. मुनव्वर कहते हैं कि सत्ता में बैठे लोग शुतुरमुर्ग की तरह मिट्टी से गर्दन तब निकालते हैं जब उनके पैरों के नीचे से सत्ता की ज़मीन खिसक जाती है. लोकतांत्रिक देश में एक हुकूमत ऐसे बयानों और ऐसे लोगों पर काबू नहीं पाती है तो इसका मतलब यह है कि वहां पर नकारा लोगों की हुकूमत है.

मुनव्वर राना ने कहा, जब मेरी उम्र प्यार मोहब्बत की शायरी करने की थी तब मेरा ध्यान बारात में गैस बत्ती उठाए बच्चे पर गया. मां की ममता, उसकी कुर्बानी और औलाद के प्रति उसका असीम प्यार भी मेरी शायरी का विषय बना. राना मानते हैं कि कूड़ा–करकट, रेल के डिब्बों में झाड़ू लगाते बच्चे और फुटपाथ पर बिना नींद की गोली खाए निश्चिंत सोते हुए मजदूरों को खूबसूरती के साथ शायरी का विषय बनाया जा सकता है. मंज़र आते चले गए शेरो–शायरी का अंदाज बनता चला गया. राना ने कहा, मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूं कि उसने मुझे खराब शायरी करने से बचा लिया. क्योंकि उस समय की उम्र की मोहब्बत बचकानी होती है. मुनव्वर कहते हैं कि बंगाल में इंकलाबी शायरी ज्यादा बोली जाती है. वहां का लहज़ा बिल्कुल अलग था, लेकिन उत्तर प्रदेश में मलिक मुहम्मद जायसी, निराला, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मुल्ला दाउद जैसे साहित्य के दिग्गज पैदा हुए. साहित्यकारों, शायरों और कवियों का कोई धर्म थोड़े ही होता है. उनका तो परिवार होता है. यह तो उन जैसे वरिष्ठों की साहित्यिक भूमिका का दबाव था जिसने हमें बचकानी शायारी से बचा लिया.

मुनव्वर ने कहा कि शायरी पर हमेशा से इल्ज़ाम लगता रहा है कि वह कच्चे गोश्त की दुकान है, जहां आंख, कान, नाक, बाज़ू सब अलग–अलग लटके दिखाई देते हैं. उस जाल से निकलने के लिए मैंने अपनी मां को शायरी आइडियल बनाया. ग़ज़ल के

> *प्रख्यात शायर मुनव्वर राना ने विशेष बातचीत में अपने जीवन के कई अनछुए पहलुओं को भी उजागर किया. उन्होंने कहा कि धर्मांतरण और लव जिहाद दोनों भारतीय जनता पार्टी की देन हैं. मुनव्वर कहते हैं कि सत्ता में बैठे लोग शुतुरमुर्ग की तरह मिट्टी से गर्दन तब निकालते हैं जब उनके पैरों के नीचे से सत्ता की ज़मीन खिसक जाती है.*

लिए यह एकदम नई व अटपटी बात थी. आलोचकों ने इस बात पर मेरी जमकर मुख़ालफ़त भी की है. लेकिन मैंने सोचा कि पहले कविता का जन्म होता है, आलोचक तो बाद में आते हैं. इसलिए मैंने अपनी विचारधारा नहीं बदली.

लबों पे उसके कभी बद–दुआ नहीं होती,
बस एक मां है, जो मुझसे खफा नहीं होती...
और
मैंने रोते हुए पोंछे थे किसी दिन आंसू उसके
मुद्दतों मां ने नहीं धोया दुपट्टा अपना...

राना कहते हैं कि भारत–पाक के संबंध न तो हमारी वजह से ख़राब हुए न ही हमारी वजह से अच्छे हो सकते हैं. यह एक सियासी जुआ था जिसमें पाक जीत गया था और मुसलमान हार गए थे.

सहरा–पसंद हो के सिमटने लगा हूं मैं,
अंदर से लग रहा है कि बंटने लगा हूं मैं...

मुनव्वर मानते हैं कि आज से 25 साल पहले तक शायर–कवि की आवाज़ समाज में सुनी जाती थी, उन्हें मार्गदर्शक माना जाता था. लेकिन अब वह बात नहीं रही. मुनव्वर राना किसी परिचय के मोहताज़ नहीं हैं. उन्होंने उर्दू शायरी के ज़रिए आम–आदमी के दर्द को उकेरने का काम किया है. उन्होंने अपनी शायरी के ज़रिए लोगों को बताने की कोशिश की है कि रोमांटिक शायरी के आलावा भी जहां में और दर्द हैं. राना कहते हैं कि नए लोग मेहनत कर रहे हैं, अच्छा कह भी रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी कमी यह है कि क्लासिकी लिटरेचर का उनमें ज्ञान नहीं है, बिना इसके अच्छी शायरी नहीं की जा सकती. रायबरेली में जन्मे मुनव्वर राना की अब तक मां, ग़ज़ल गांव, पीपल छांव, सब उसके लिए, घर अकेला हो गया, सफ़ेद जंगली कबूतर, मुनव्वर राना की सौ ग़ज़लें, नए मौसम के फूल और मुहाज़िरनामा जैसी किताबें खूब प्रशंसा पा चुकी हैं. मुनव्वर कहते हैं कि नौजवानों के लिए मेरा संदेश इतना ही है कि...

बस इतनी इल्तज़ा है कि तुम इसे बर्बाद मत करना,
तुम्हें इस मुल्क का मालिक मैं जीते जी बना दूंगा...

feedback@chauthiduniya.com

खैरा में फ्लोराइड का क़हर

जीवन की बजाय अभिशाप बना जल

कुमार कृष्णन

बिहार के मुंगेर ज़िले के नक्सल प्रभावित हवेली खड़गपुर प्रखंड का खैरा गांव फ्लोराइड युक्त जल के इस्तेमाल से हो रही विकलांगता के चलते इन दिनों सुर्खियों में है. साढ़े चार वर्ष पूर्व सूबे के तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद खैरा गांव आए थे. पूर्वी रमनकाबाद पंचायत के खैरा गांव के लोगों के लिए जल जीवन नहीं, मौत बन गया है. फ्लोराइड युक्त जल पीने से कई लोग अपंग हो गए, तो कई असमय काल के गाल में समा गए. तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ग्रामीणों को फ्लोराइड के अभिशाप से मुक्ति दिलाने के लिए पांच जून, 2010 को अपनी विश्वास यात्रा के दौरान करोड़ों रुपये की लागत वाली जलापूर्ति योजना का शिलान्यास भी किया था. उक्त योजना के अनुसार, खड़गपुर झील से खैरा तक शुद्ध पेयजल ग्रामीणों को एक वर्ष के भीतर उपलब्ध कराया जाना था, लेकिन विभागीय अधिकारियों की उदासीनता के चलते झील का पानी आज तक खैरा गांव नहीं पहुंच सका.

नतीजतन, खैरा के लोग फ्लोराइड युक्त जल का इस्तेमाल पीने के लिए करने को विवश हैं. इस योजना को अमलीजामा पहनाने के लिए खड़गपुर झील परिसर में

पुजलाइट कंपनी द्वारा कार्य शुरू होना था. लगभग 25 करोड़ 27 लाख रुपये की इस योजना पर आपसी विवाद के चलते ग्रहण–सा लग गया है. कई महीने से काम बंद चलने की वजह से वहां मौजूद सामान पर चोरों की गिद्ध दृष्टि लगी हुई है, काफी सामान चोरी भी हो चुका है.खैरा निवासी गौरी देवी, करुणेश कुमार, संजीव कुमार, कन्हैया लाल, नारायण मंडल, सरिता देवी, रूपा देवी एवं किरण देवी ने बताया कि वे फ्लोराइड युक्त जल पीने को विवश हैं. उनकी व्यथा सुनने वाला कोई नहीं है. ग्रामीण कहते हैं कि यदि शुद्ध पेयजल जल्द मुहैया नहीं कराया गया, तो सारे लोग विकलांग हो जाएंगे. बीते 31 दिसंबर को ग्रामीणों ने इस समस्या के स्थायी समाधान की मांग को लेकर प्रखंड एवं अंचल कार्यालय का घेराव किया. लक्ष्मण प्रसाद सिंह, प्रखंड प्रमुख गौरी देवी एवं मुखिया अनामिका सिन्हा के नेतृत्व में लोगों ने शुद्ध पेयजल मुहैया करो–नीतीश कुमार का संकल्प पूरा करो और जल ही जीवन है, फिर भी क्यों हम लोगों के लिए अभिशाप है आदि नारे लगाते हुए अनुमंडल पदाधिकारी को अपना ज्ञापन सौंपा. स्वास्थ्य विभाग के एक सर्वे के मुताबिक, 2010 में ही खैरा गांव के 70 लोग विकलांग घोषित किए जा चुके हैं.

खैरा गांव में जल में फ्लोराइड की अधिक मात्रा के कारण लोग विभिन्न शारीरिक विकृतियों के शिकार हो रहे हैं. हड्डियों से संबंधित कई दिक्कतें सामने आ रही हैं. लोग समय से पहले बूढ़े लगने लगे हैं. रीढ़, गर्दन, हाथ, पैर की हड्डियां टेढ़ी–मेढ़ी और कमज़ोर हो जाती हैं. खड़े होने, चलने, दौड़ने या बोझ ढोने में कठिनाई होती है. हड्डियों, गर्दन एवं जोड़ों में तेज दर्द रहता है. फ्लोराइड के असर के चलते दांत स्थायी रूप से गंदे और पीले हो रहे हैं. इससे बच्चे ज़्यादा पीड़ित हैं. यह बीमारी आठ–नौ वर्ष की उम्र से दिखने लगती है. खैरावासियों के प्रदर्शन की धमक मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के कानों तक भी पहुंची. अपने दो दिवसीय दौरे पर जब मांझी मुंगेर आए, तो अगले दिन यानी बीती तीन जनवरी को ज़िला परिषद के सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में उन्होंने खैरा की खोज–ख़बर ली. मुंगेर के ज़िला पदाधिकारी अमरेंद्र प्रसाद सिंह ने मुख्यमंत्री को बताया कि समय पर काम पूरा न किए जाने के कारण इस योजना से जुड़ी दो कंपनियों जिंदल और पुजलाइट को काली सूची में डाल दिया गया है.

मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि सिर्फ़ काली सूची में डाल देना समस्या का समाधान नहीं है. उक्त दोनों कंपनियों के ख़िलाफ़ प्राथमिकी दर्ज कराई जाए. मामले में हस्तक्षेप करते हुए राज्य के मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह ने लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अधिकारियों से कहा कि वे व्यक्तिगत रूप से खैरा के मामले की समीक्षा करेंगे. मुख्यमंत्री मांझी ने कहा कि आगामी पांच मार्च तक हर हाल में खैरा के लोगों को शुद्ध पेयजल मिलना चाहिए. मुख्यमंत्री मांझी ने अधिकरियों से कहा कि वे सिर्फ़ सरकार की नौकरी करके औपचारिकता न निभाएं, भगवान से डरें और ईमान कायम रखें. उन्होंने कहा कि लोग विकलांग हो रहे हैं और आप मानवता भूले जा रहे हैं. समीक्षा

मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि सिर्फ़ काली सूची में डाल देना समस्या का समाधान नहीं है. उक्त दोनों कंपनियों के ख़िलाफ़ प्राथमिकी दर्ज कराई जाए. मामले में हस्तक्षेप करते हुए राज्य के मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह ने लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अधिकारियों से कहा कि वे व्यक्तिगत रूप से खैरा के मामले की समीक्षा करेंगे.

बैठक में राज्य के मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह, पुलिस महानिदेशक पीके ठाकुर, विभिन्न विभागों के प्रधान सचिव, ज़िलों के प्रभारी सचिव, प्रमंडलीय आयुक्त सुनील कुमार सिंह के साथ–साथ मुंगेर, खगड़िया, बेगूसराय, लखीसराय, जमुई एवं शेखपुरा के ज़िला पदाधिकारी, आरक्षी अधीक्षक, सूचना एवं जनसंपर्क मुंगेर प्रमंडल के उपनिदेशक कमलाकांत उपाध्याय, राज्य के पर्यटन मंत्री सह मुंगेर के प्रभारी मंत्री जावेद इकबाल अंसारी, नगर विकास मंत्री सम्राट चौधरी, विधायक अनंत सत्यार्थी, नीता चौधरी एवं शैलेश कुमार ने हिस्सा लिया. ■

feedback@chauthiduniya.com

कुरैशी का तबादला आज़म प्रेम का नतीजा

राजकुमार शर्मा

उत्तर प्रदेश सरकार के बड़बोले कैबिनेट मंत्री आजम खां 14 वर्षों तक खुली आंखों से जौहर विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक संस्थान बनाने और स्वयं उसका आजीवन कुलाधिपति बनने का सपना देखते रहे. केंद्र में यूपीए के दस वर्षों के शासनकाल में भी किसी राज्यपाल ने जौहर विश्वविद्यालय रामपुर के विधेयक को मंजूरी नहीं दी, लेकिन मोदी सरकार आने के बाद कुछ दिनों के लिए उत्तर प्रदेश का अतिरिक्त प्रभार संभालने वाले उत्तराखंड के राज्यपाल डॉ. अजीज कुरैशी ने उसे मंजूरी दे दी. कुरैशी की यही दरियादिली उनके गले की फांस बन गई. भाजपा नेताओं ने हाईकमान को समझाया कि जो काम कांग्रेस की मनमोहन सरकार में नहीं हुआ, वह केंद्र में मोदी सरकार आते ही हो गया. इससे भाजपाइयों को लगा कि कुरैशी मुख में राम बगल में छूरी रखते हैं. उत्तराखंड के राज्यपाल रहते हुए कुरैशी मोदी सरकार को पटाने के लिए हर दिन गंगा, गाय एवं चार धाम को चार वेद की तर्ज पर विकसित करने का भी शिगूफा छोड़ते रहे. जौहर विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक संस्थान और आजम को आजीवन कुलाधिपति बनाने का यह मामला भाजपा हाईकमान को खासा अखरा.

भाजपा नेताओं ने नेतृत्व के सामने जमकर विरोध जताया. नतीजा यह हुआ कि अजीज कुरैशी केंद्र के निशाने पर आ गए. बाद में कुरैशी ने अदालत में भी दस्तक दी, लेकिन बात कुरैशी की उत्तराखंड से विदाई पर जाकर ख़त्म हुई. स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े रहे कुरैशी इसके पूर्व स्वयं को नेहरू परिवार का अंध समर्थक बताते रहे हैं. हद तो तब हो गई थी, जब उत्तराखंड का राज्यपाल बनते ही उन्होंने कहा था कि सोनिया

गांधी कहें, तो वह झाड़ू भी लगा सकते हैं. अपना तबादला किए जाने के बाद धर्मनगरी हरिद्वार के प्रेमनगर आश्रम में आयोजित एक कार्यक्रम में डॉ. कुरैशी ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड के लिए उन्होंने कई सपने संजोए थे, लेकिन मोदी सरकार ने उनके सपने पूरे नहीं होने दिए. चार धाम के विकास को भी उन्होंने अपने सपनों से जोड़ा

भाजपा नेताओं ने नेतृत्व के सामने जमकर विरोध जताया. नतीजा यह हुआ कि अजीज कुरैशी केंद्र के निशाने पर आ गए. बाद में कुरैशी ने अदालत में भी दस्तक दी, लेकिन बात कुरैशी की उत्तराखंड से विदाई पर जाकर ख़त्म हुई. स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े रहे कुरैशी इसके पूर्व स्वयं को नेहरू परिवार का अंध समर्थक बताते रहे हैं. हद तो तब हो गई थी, जब उत्तराखंड का राज्यपाल बनते ही उन्होंने कहा था कि सोनिया गांधी कहें, तो वह झाड़ू भी लगा सकते हैं.

और कहा कि उम्मीद कभी नहीं मरती. भले ही वह अब उत्तराखंड से जा रहे हैं, लेकिन प्रदेश के लिए जो सपने उन्होंने संजोए थे, वे ज़रूर पूरे होंगे. जाते–जाते डॉ. कुरैशी ने मीडिया को भी जमकर कोसा. उन्होंने कहा कि उनके किसी मजहब के विरोधी होने या दूसरे संप्रदाय की वकालत करने की छवि बनाने के लिए मीडिया पूरी तरह ज़िम्मेदार है. वह न तो किसी मजहब के विरोधी हैं और न उन्होंने कभी किसी संप्रदाय की वकालत की.■

feedback@chauthiduniya.com

ऑपरेशन स्माइल शुरू हुआ

उत्तराखंड ब्यूरो

feedback@chauthiduniya.com

उत्तराखंड की हरीश रावत सरकार ने अपनी घोषणा के अनुपालन में राज्य में 'आपरेशन स्माइल' नए साल से शुरू कर दिया है. यह अभियान गुमशुदा बच्चों को तलाशने से जुड़ा हुआ है. यह ऑपरेशन पूरे जनवरी माह में चलेगा. इस अभियान के तहत एक माह के तय समय में सभी बच्चों की गुमशुदगी का पता लगाना है. इस अभियान का उद्देश्य 14 सालों के दौरान राज्य से गुम हुए बच्चों की तलाश करना, उन्हें परिजनों तक पहुंचाना है. एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल की प्रभारी तथा अपर पुलिस अधीक्षक ममता वोहरा तथा डीएसपी मनोज कात्याल को इसका नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है. इसके लिये सभी जिलों में अलग टीमों का गठन किया गया है. देहरादून में सात टीमों को इसकी ज़िम्मेदारी दी गयी है. इसमें सात दारोगा तथा 28 सिपाही होंगे. इस टीम की ख़ासियत होगी कि वर्दीधारी पुलिसवालों के साथ ही सादे कपड़ों में भी पुलिसवाले होंगे.

वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ही मामले के विशेषज्ञों से बात करने के बाद पुलिस ने कुछ बुनियादी बातें तय की हैं. पुलिस सबसे पहले खोये बच्चों की रंगीन फोटो जुटायेगी. इसके लिये पुलिस

टीम बच्चों के माता–पिता के पास जायेगी. फोटो जुटाने के बाद उसको एक एलबम के रूप में संग्रहित किया जायेगा. इस एलबम की ख़ासियत होगी कि वह हाई रिजोल्यूशन यानि साफ व गहरे रंग की फोटो से बनेगा. साथ ही बच्चों के गुम होने का कारण व परिस्थिति की जानकारी भी एकत्र की जायेगी. बच्चों की गुमशुदगी को लेकर तस्वीर भयावह है. कई परिवार आज भी अपने नौनिहालों के लौटने की बाट जोह रहे हैं. वह इनका इंतजार कर रहे हैं जो लौट कर अभी तक घर नहीं आये हैं. इस मामले में पुलिस का रवैया बेहद निराशाजनक रहा है. ऐसे अभियान की शुरुआत से साबित होता है कि पुलिस इस गंभीर मसले को कितने हल्के में ले रही थी. सूबे के मुखिया हरीश की सजगता से सरकारी तंत्र सजग हुआ है. सरकारी आंकड़े बताते हैं कि 75 प्रतिशत लड़कियां व 88 प्रतिशत लड़के अभी तक घर नहीं लौटे हैं. यह आंकड़ा सिर्फ 2014 का है. अगर बीते साल के आंकड़ों पर गौर करें तो यह संख्या काफी ज्यादा है. इस साल 24 लड़के व 25 लड़कियां गुमशुदा हुईं. इसमें लौटने वालों की संख्या क्रमश: 3 व 6 है.

खोये बच्चों की तलाश में जुटे पुलिस टीम को प्रथम चरण में ही दो बच्चे दिल्ली में मिले हैं. ऐसे कामों के लिये विशेष रूप से चलाये जा रहे ऑपरेशन स्माइल के तहत दोनों बच्चों को पुलिस ने दिल्ली से लाकर परिजनों के हवाले कर दिया. इधर, परिजनों ने पुलिस से बच्चों की पहचान गुप्त रखने का अनुरोध किया है. एक ही क्लास में पढ़ने वाले दोनों बच्चे घर में डांट के बाद फरार हो गये थे. स्थानीय पुलिस की टीम दिल्ली पहुंची और बच्चे को लेकर देहरादून आई. पूछताछ में बच्चों ने बताया कि इन्हें घर में डांट पड़ती थी, इसके चलते वे घर छोड़ कर भागे थे. एक जनवरी को वे देहरादून में ही घूमते रहे. इसके अगले दिन वे दिल्ली पहुंच गये. प्रदेश सरकार की इस योजना से मिसिंग चाइल्ड के अभिभावकों में एक आस जगी है.■

www.chauthiduniya.com
चौथी दुनिया

www.kamalmorarka.com

कमल मोरारका

छोटे उद्यमियों पर ध्यान देने की ज़रूरत है

भारत में कृषि पर ध्यान देने की आवश्यकता है. मुझे मालूम नहीं है कि इसके बारे में वित्त मंत्री की क्या सोच है लेकिन फसल बीमा और कृषि के लिए पहले से मौजूद समर्थन प्रणाली को सुचारू रूप से चलने के लिए वित्त मंत्री को कदम उठाना चाहिए. अगर कृषि क्षेत्र और गैर-कृषि सूक्ष्म और लघु उद्योगों को पर्याप्त मात्रा में वित्त मुहैया कराया जाता है तो रोजगार में काफी वृद्धि हो सकती है और लोगों के जीवन स्तर में भी सुधार आ सकता है.

अगले महीने बजट आने वाला है. मैं समझता हूं, ज्यादातर पर्यवेक्षकों का ध्यान इस पर केंद्रित है कि बजट में कोई बड़ी घोषणायें होती हैं या नहीं. पेट्रोलियम की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में गिरावट की वजह से सरकार के लिए थोड़ी आसानी हो गई है. एक, पेट्रोलियम की कीमतों की वजह से आयात के खर्चों में काफी कमी आएगी. दूसरा यह कि देश में खाद्यान भंडार भी संतोषजनक है. फिलहाल सरकार पर दबाव कम है. यदि वित्त मंत्री चाहें तो सरकार कुछ जोखिम उठा सकती है. फिलहाल राजकोषीय घाटा की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन मार्च से पहले यदि स्पेक्ट्रम की बिक्री से एक बड़ी राशि प्राप्त कर ली जाती है, तो राजकोषीय घाटे का आंकड़ा खतरनाक स्तर पर नहीं पहुंचेगा. कुल मिला कर अभी स्थिति नियंत्रण में है.

सरकार के लिए यह सही समय है कि वह विकास और रोजगार सृजन की दिशा में कुछ कदम उठाये. अगर हम चीन के आर्थिक विकास की कहानी को देखें तो आम धारणा यह है कि चीन का विकास प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की वजह से हुआ है. लेकिन हकीक़त यह है कि चीन में गरीबी उन्मूलन मुख्य रूप से वहां की टाउनशिप एंड विलेज एंटरप्राइजेज (टीवीई) के कारण हुआ. टीवीई हमारे देश के सूक्ष्म,लघु और मध्यम उद्योगों की तरह है.

भारत में गैर-कृषि उद्योगों से लोगों को बड़ी तादाद में रोजगार मिलता है. अब भारत की हालत देखते हैं. यहां 1991 में आर्थिक सुधार की शुरुआत हुई. लेकिन हैरानी की बात यह है कि भारत में पिछले 23 वर्षों में संगठित निजी क्षेत्र ने कुल 37 लाख और सार्वजानिक क्षेत्र ने कुल 50 लाख लोगों को रोज़गार दिया. इसका अर्थ यह हुआ कि पिछले 23 वर्षों में देश में रोज़गार के केवल 22 लाख नए अवसरों की बढ़ोतरी हुई. संगठित क्षेत्र में हजारों करोड़ की हेराफेरी होती है. देश में बड़ी मात्रा में एफडीआई आ रहा है. यह आंकड़े हमें अतिउत्साहित नहीं करते, कि हम बेरोजगारी दूर करने या लोगों को गरीबी से बाहर निकालने के लिए सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं. दरअसल इसके लिए हमें चीन के टीवीई की शैली पर काम करना होगा. भारत में सूक्ष्म और लघु उद्योंगों की प्रगति हो रही है. देश में कुल 5.8 करोड़ सूक्ष्म और लघु उद्योग हैं. क्या दुनिया में कोई ऐसा देश है जहां 5.8 करोड़ उद्यमी होंगे? एक व्यक्ति द्वारा चलाई जा रही दुकान एक उद्यम है या पांच लोगों द्वारा चलाई जा रही कोई छोटी इकाई. हमारे पास जो 5.8 करोड़ उद्यमी हैं उन्हें पूंजी कहां से मिलती है? स्थानीय साहूकार और अनौपचारिक मुद्रा बाजार उन्हें ऊंची व्याज दरों पर पूंजी उपलब्ध कराते हैं. तो फिर साहूकार कहां से पैसा लाते हैं? इसका जवाब है, कहीं से नहीं. वे अपने पैसों से बहुत अधिक पैसा कमा रहे हैं. हम साहूकारों को इनके बीच से हटा भी नहीं सकते, क्योंकि वे कर्जदारों को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं.

दुर्भाग्यवश हमारा सिस्टम इस तरह विकसित हुआ है जिसमें बैंक ऐसे व्यक्ति को क़र्ज़ नहीं देते जिन्हें वे जानते हैं, यह कंप्यूटर है जो पैसे का लेन-देन कर रहा है और उन्हें प्वाइंट्स दे रहा है. यह इतना अव्यक्तिगत हो गया है कि सूक्ष्म और लघु उद्योगों की किसी बड़े बैंक तक पहुंच हो ही नहीं सकती, और न ही बड़े बैंक कभी ऐसे वास्तविक उद्यमियों तक पहुंच सकते हैं. हमें एक संस्थागत ढ़ांचा तैयार करना होगा. हमारे पास लखनऊ स्थित भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) है, जिसे सरकार द्वारा फंड मुहैय्या किया जा सकता है या उसके बाद आखिरी कर्जदाता के रूप में गांव के

स्थानीय साहूकार और अनौपचारिक मुद्रा बाजार उन्हें ऊंची व्याज दरों पर पूंजी उपलब्ध कराते हैं. तो फिर साहूकार कहां से पैसा लाते हैं? इसका जवाब है, कहीं से नहीं. वे अपने पैसों से बहुत अधिक पैसा कमा रहे हैं. क्योंकि वे कर्जदारों को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं. दुर्भाग्यवश हमारा सिस्टम इस तरह विकसित हुआ है जिसमें बैंक ऐसे व्यक्ति को क़र्ज़ नहीं देते जिन्हें वे जानते हैं, यह कंप्यूटर है जो पैसे का लेन-देन कर रहा है और उन्हें प्वाइंट्स दे रहा है. यह इतना अव्यक्तिगत हो गया है कि सूक्ष्म और लघु उद्योगों की किसी बड़े बैंक तक पहुंच हो ही नहीं सकती.

साहूकार हैं. और इन दोनों के बीच एक बहुत बड़ा फासला है. हमें एक ऐसी प्रणाली विकसित करनी होगी जिसमें साहूकार का पुनर्वित्तीयन एक जिला स्तर की संस्था करे और इस संस्था की फंडिंग एक राज्य स्तर की संस्था द्वारा हो और इस संस्था की फंडिंग सिडबी द्वारा हो. इस तरह की प्रणाली विकसित की जा सकती है.

वित्त मंत्री अरुण जेटली के लिए ऐसी घोषणा करने का यह सुनहरा मौक़ा है जिससे कि कोई भी उद्यमी उचित ब्याज दर पर क़र्ज़ लेने से वंचित नहीं रहेगा. ऐसा करना बहुत मुश्किल भी नहीं है. क्योंकि इसमें जो पैसा लगेगा वह बुनियादी ढ़ांचे के विकास और ऐसी दूसरी परियोजनाओं पर लगने वाली राशि से बहुत कम होगा और इन परियोजनाओं की वजह से अनर्जक परिसंपत्तियों (एनपीए) के बारे में सबको पता है.

सूक्ष्म और लघु उद्योग की खूबी यह है कि इसमें क़र्ज़ की शत-प्रतिशत उगाही हो जाती है और इसमें कोई एनपीए भी नहीं बनता या इतना कम होता है कि सिस्टम पर इसका कोई खास प्रभाव नहीं पडता. श्री अरुण जेटली के लिए जो सुनहरा मौक़ा है वह है सूक्ष्म और लघु उद्यमों की एक प्रणाली विकसित करना ताकि रोज़गार सृजन को बढ़ावा मिल सके. चीन द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक उन्होंने 15.5 करोड़ लोगों को ग़रीबी रेखा से ऊपर उठाया है, जो एक बहुत बड़ी संख्या है. अगर हम सूक्ष्म और लघु उद्योग की सहायता कर दें तो कृषि के साथ-साथ इस क्षेत्र से भी भारत में गरीबी उन्मूलन के एक बड़े लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है.

भारत में कृषि पर ध्यान देने की आवश्यकता है. मुझे मालूम नहीं है कि इसके बारे में वित्त मंत्री की क्या सोच है लेकिन फसल बीमा और कृषि के लिए पहले से मौजूद समर्थन प्रणाली को सुचारू रूप से चलने के लिए वित्त मंत्री को कदम उठाना चाहिए. अगर कृषि क्षेत्र और गैर-कृषि सूक्ष्म और लघु उद्योगों को पर्याप्त मात्रा में वित्त मुहैया कराया जाता है तो रोजगार में काफी वृद्धि हो सकती है और लोगों के जीवन स्तर में भी सुधार आ सकता है.

जाहिर है कि बुनियादी ढांचे को विकसित करने वाली परियोजनाएं चलती रहनी चाहिए, बड़े उद्योग भी लगने चाहिए, पॉवर सेक्टर को नज़रंदाज़ नहीं किया जाना चाहिए. इसमें कोई विरोधाभास नहीं है. लेकिन इसमें बहुत बड़ी राशि लगी हुई है. मैं जो सुझाव दे रहा हूं उसे बहुत आसानी से, छोटी सी रकम से पूरा किया जा सकता है. हालांकि, इसके लिए नीतिगत फैसले करने होंगे, ऐसी मैकेनिज्म (तंत्र) विकसित करने की जरूरत है जिसे आसानी से बैंकर्स, वित्तीय जानकार या वित्त मंत्रालय के लोगों की कमेटी बना सकती है. इस काम में छह महीने लग सकते हैं. लेकिन इसकी घोषणा बजट में की जानी चाहिए, ताकि काम जारी रहे. ■

feedback@chauthiduniya.com

एक बूढ़े आदमी की वह युवा क्रांति...

आज पत्रकारिता के मायने बदल गए हैं, बदल रहे हैं अथवा बदल दिए गए हैं, नतीजतन, उन पत्रकारों के सामने भटकाव जैसी स्थिति आ गई है, जो पत्रकारिता को मनसा-वाचा-कर्मणा अपना धर्म-कर्तव्य और कमज़ोर-बेसहारा लोगों की आवाज़ उठाने का माध्यम मानकर इस क्षेत्र में आए और हमेशा मानते रहे. और, वे नवांकुर तो और भी ज़्यादा असमंजस में हैं, जो पत्रकारिता की दुनिया में सोचकर कुछ आए थे और देख कुछ और रहे हैं. ऐसे में, 2005 में प्रकाशित संतोष भारतीय की पुस्तक-पत्रकारिताः नया दौर, नए प्रतिमान हमारा मार्गदर्शन करती और बताती है कि हमारे समक्ष क्या चुनौतियां हैं और हमें उनका सामना किस तरह कर ना चाहिए. चार दशक से भी ज़्यादा समय हिंदी पत्रकारिता को समर्पित करने वाले संतोष भारतीय देश के उन पत्रकारों में शुमार किए जाते हैं, जो देश और समाज से जुड़े प्रत्येक मुद्दे पर निर्भीक, सटीक, निष्पक्ष टिप्पणी करते हैं.

जयप्रकाश जी का शरीर भी बीमारियों का घर था. उन्हें खुद से भी लड़ाई लड़नी पड़ रही थी कि पत्नी प्रभावती देवी के बारे में पता चला कि उन्हें कैंसर है. प्रभावती जी भी अद्भुत महिला थीं. उन्हें केवल एक चिंता थी कि उनकी मृत्यु के बाद जे.पी. को कौन देखेगा? वे कैसे रह पाएंगे. इन्हीं चिंताओं के साथ प्रभवाती जी सब कुछ छोड़कर चली गईं. जे.पी की बीमारियां सर उठाने लगी थीं. मन से भी काफी कमजोर हो गए थे जे.पी. अचानक उन्हें ध्यान आया कि उत्तर प्रदेश में 1975 में चुनाव होने वाले हैं. मैं सहरसा में था कि जे.पी. की चिट्ठी मिली. मिलने के लिए. जब मिला तो इस तरह से सम्मान देते हुए बात की कि मुझे लगा कि वह सामान्य व्यक्ति को भी कम महत्वपूर्ण नहीं मानते. होली में सहरसा से लौट रहा था. कुछ दिनों के लिए मुजफ्फरपुर रूका तो वहां निर्दलीय युवकों के आंदोलन ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि अचानक शासन ने मुझे, प्रशान्त, सुरेन्द्र, कन्हैयाशरण तथा सुरेश वात्स्यायन को गिरफ्तार कर लिया तथा पहली बार मीसा का प्रयोग किया. जैसे ही जे.पी. को इसका पता चला उन्होंने लगातार अखबारों में वक्तव्य देना शुरू किया. इसी बीच पटना में छात्रों के विधानसभा घेराव के समय आगजनी व गोलीबारी की घटना हो चुकी थी. जे.पी ने कहा कि जिन लड़को को शान्ति व्यवस्था भंग होने की आशंका में पकड़ा गया है वे खुद इस सरकार को शान्ति व्यवस्था का पाठ सिखा सकते हैं. हम लोगों को जे.पी भूल जाते तो भी कोई बात नहीं थी, लेकिन उन्होंने हमें याद रखा. यह उनकी सबसे बड़ी महानता थी. बीस दिनों के बाद जब सरकार ने मीसा वापस लिया, तो हम सब जे.पी से मिलने गए. उनका गला रूंधा था तथा आवाज कांप रही थी.

बिहार सरकार ने दमन तेज कर दिया था. जे.पी. ने 8 अप्रैल को मौन जुलूस निकालने की घोषणा कर दी. उस समय कोई नहीं जानता था कि क्या होगा, जे.पी. शान्त थे. दो दिन पहले उनकी पौरुष ग्रन्थि में सूजन आ गई थी, जिसकी वजह से कैथेटर लगा था. 8 अप्रैल को डॉक्टरों की सलाह के विपरीत जे.पी. जीप में बैठकर निकले. उनके पीछे था पक्तिंबद्ध विशाल जुलूस, जिसके आगे बड़े-बड़े अक्षरों में लिखा था, क्षुब्ध हृदय है बन्द जबान. प्रत्येक के मुंह पर पट्टी थी तथा हाथ पीछे की ओर बंधे थे. क्या संयोग था कि जे.पी. ने मौन जुलूस ठीक श्रीकृष्ण मैमोरियल के सामने रुकवाया. वे जीप से उतरे. लगभग पचास गज पीछे चले. जीप के ठीक बाद महिलाओं की कतार थी. मैं जीप के ठीक आगे चल रहा था. जे.पी. ने अपना मौन तोड़ा और मुझे बुलाया तथा कहा कि इन महिलाओं से पूछो कि प्यास तो नहीं लगी है? मेरे पूछने पर महिलाओं ने इनकार में सिर हिला दिया. जे.पी. ने एक बार उचक कर दूर पीछे तक फैली कतारों को देखने की कोशिश की. लौटे और जीप में बैठे. जुलूस का अभूतपूर्व स्वागत हुआ था उस दिन. सारा आतंक जे.पी. के एक जुलूस ने तोड़ दिया तथा वहीं से प्रारंभ हुआ आंदोलन का सिलसिला. जे.पी. आंदोलन में क्या लगे, उनकी बीमारी नियन्त्रित होने लगी. चौहत्तर साल का वृद्ध देश का दौरा करने लगा. युवकों ने अपना निर्विवाद नेता उन्हें मान लिया था. उन दिनों की एक-एक घटना आज इतिहास का अंग बन चुकी हैं. इसी दौर की घटना है 5 जून की एतिहासिक रैली, उस पर गोली वर्षा और उसके बावजूद शांति. जे.पी. अपने परीक्षण में सफल हो गए कि युवकों को क्रान्ति युद्ध में लगाया जा सकता है. उन्होंने घोषणा कर दी-यह क्रांति है मित्रों. सम्पूर्ण क्रांति.

जे.पी. बहुत कुछ ऐसा करते थे, जो तर्क की कसौटी पर कसा ही नहीं जा सकता था. स्वर्गीय ओमप्रकाश दीपक ने एक बार ऐसी ही बहस में हम लोगों से कहा था, जे.पी सबसे अलग हैं. उनके कहे पर चलो, पहले नहीं लगेगा कि काम तार्किक है, लेकिन उसके पूरा होने पर अपने आप तार्किक आधार स्पष्ट हो जाएगा. दीपक जी की बात 3, 4 और 5 अक्टूबर, 1974 के बिहार बंद के दौरान सही निकली. इस बिहार बंद का दीपक जी को छोड़कर सबने विरोध किया था. लेकिन जे.पी. ने जिद पकड़ ली थी. वह बिहार बंद अद्भुत था. न पान, न चाय, न बस, न रेल. तीन दिनों तक सब कुछ बंद था. जे.पी जनता की नब्ज सबसे सही पहचानते थे. मैं खुद अनेक घटनाओं का साक्षी हूं और ऐसी घटनाएं जे.पी. की जिन्दगी में बेशुमार हैं. 4 नवंबर 1974 को सुबह आठ बजे का समय रहा होगा. जे.पी. खुली जीप में अपने घर से निकले हैं. कुल-तीस चालीस आदमी साथ थे. जीप नाला रोड चौराहे को जब पार करती है तो संख्या पांच सौ के आसपास पहुंच जाती है. पुलिस ने हलकी छेड़छाड़ की. अशोक राजपथ से गांधी मैदान की ओर जब जीप चली, तो

लगभग एक हजार लोग रहें होगे. अशोक राजपथ की समाप्ति पर पुलिस ने पहला मोर्चा बना रखा था. उनकी साजिश थी कि केवल जे.पी. की जीप निकल जाए तो बाकी लोगों को तितर-बितर कर दें. जे.पी. की जीप तथा लड़-झगड़ कर सौ लोग निकले होंगे कि पुलिस ने लाठी चलाते हुए, कुछ को मारते हुए जुलूस को पीछे खदेड़ा. लड़के चप्पल जूता छोड़कर भागे. जे.पी. तत्काल नीचे उतर आए तथा वहां मौजूद जिलाधीश के पास जाकर उसे झकझोर दिया तथा सामान्य से काफी तेज आवाज में बोले-क्यों लाठी चार्ज किया, बोलिए क्यों किया. क्या कर रहे थे लड़के? जिलाधिकारी श्री दुबे सर नीचा किए खड़े थे. जे.पी हिकारत भरी निगाहों से उसे देखते हुए धीरे-धीरे कुछ पीछे गए तथा चप्पलों को उठाने लगे. तब तक हम लोग दौड़े. कुछ लड़कों से जे.पी. ने कहा कि इन सबको जीप में रखो-जिनकी होंगी बाद में ले जाएंगे. जे.पी. पैदल ही आगे बढ़े. धीरे से गांधी मैदान में घुसे. आसमान में एक हेलीकॉप्टर घूम-घूमकर नजर रखे हुए था. गांधी मैदान बिल्कुल खाली था और अब जे.पी. के साथ सौ के लगभग आदमी थे. पांच मिनट बीतते-बीतते, जैसे बांध का अवरोध टूटने पर पानी फैलने लगता है, आदमियों का समूह उमड़ पड़ा तथा पूरा गांधी मैदान आदमियों से इंच-इंच भर गया. जे.पी. स्टेट बैंक के छोर पर थे, तो अशोक राजपथ की ओर देखने पर आदमी-ही-आदमी दिखाई देते थे. पुलिस ने धीरे-धीरे घेरा डालना शुरू किया. जे.पी. थक चुके थे तथा बैठना चाहते थे. वे स्टेट बैंक की अहाते की तरफ बढ़े, लेकिन बैंक अधिकारियों ने दरवाजा बंद करवा दिया था. वह लगभग साढ़े छह फुट उंची चाहरदीवारी थी, जिस पर जे.पी. ने पैर रखा तथा दीवाल के दूसरी ओर कूद गए. उतनी बीमारी में उन्हें इस तरह का साहस करते देख लोगों ने मुंह में अंगुली दबा ली. पुलिस ने आंसू गैस का गोला छोड़ना शुरू किया, तो जेपी बाहर आए. तब तक दरवाजा खोल दिया गया था. ■

feedback@chauthiduniya.com

जब तोप मुक़ाबिल हो

संतोष भारतीय

असहमति की जगह बचनी चाहिए

कामनाएं की गई थीं कि पिछली शताब्दी में जितने ख़ून-ख़राबे हुए, जितनी असहिष्णुता हुई, वह अगली शताब्दी में नहीं होगी. नई शताब्दी आई, लेकिन लोगों की शुभकामनायें काम नहीं आईं. विश्व के लगभग हर देश में किसी न किसी प्रकार के सशस्त्र संघर्ष चल रहे हैं. असहमति के लिए कोई जगह बचेगी या नहीं, इस पर संशय पैदा हो गया है. ताजा घटना पेरिस की है जहां कार्टून छापने वाली एक पत्रिका के दफ्तर में तीन लोगों ने घुसकर अंधाधुंध गोली-बारी की और संपादक सहित कुल 10 पत्रकारों की हत्या कर दी. घटना में दो पुलिस वाले भी मारे गए.

यह असहमति का दौर इतना जबरदस्त है कि आप कहीं पर भी अपनी राय अगर निश्चिंततापूर्वक रखना चाहें तो उसके विरोध में तर्क नहीं आते, बल्कि गोली आने की संभावना बढ़ जाती है. हालांकि, इसमें कोई दो राय नहीं कि वो गोली सांसे तो बंद करती है पर विचार नहीं, और यही पेरिस में भी हुआ. दुनिया के करोड़ों लोग इस पत्रिका की मुहिम से जुड़ गए. हो सकता है जिन लोगों ने पत्रकारों को मारने के लिए हत्यारों को भेजा हो वो अपने छिपने के स्थान पर मुस्करा रहे हों कि खूब सबक सिखाया, अब कोई असहमति की बात नहीं करेगा. लेकिन सारी दुनिया ने असहमति के पक्ष में अपने हाथ खड़े किये हैं.

भारत में सबसे पहले जी न्यूज ने यह हिम्मत दिखाई और उसने उन कार्टूनों को प्रमुखता के साथ पूरे दिन और शाम को प्राइम टाइम प्रोगाम डीएनए टेस्ट में दिखाया. जिन कार्टूनों की वजह से इन पत्रकारों की हत्या की गई. इतना ही नहीं जी न्यूज के सुधीर चौधरी और रोहित सरदाना ने बार-बार यह कहा कि हम इसे पत्रकारों की हत्या के विरोध स्वरूप दिखा भी रहे हैं और सबसे अपील कर रहे हैं कि वे भी इन कार्टूनों को दिखाएं और असहमति एवं अभिव्यक्ति को समर्थन देने वाली मुहिम में शामिल हों.

मुझे जी न्यूज के मालिक डॉ सुभाष चंद्रा गोयल की प्रशंसा करने में कोई हिचक नहीं हो रही है. क्योंकि बिना मालिक की हिम्मत दिखाए आज के जमाने में इस स्टैंड को लेना मुश्किल है. दौर होते हैं, जिस दौर में सवाल खड़े होते हैं, आलोचनाएं भी होती हैं. लेकिन जब वैचारिक संकट का समय आए उस समय स्टैंड लेना बहादुरी की बात मानी जाती है. जिसके लिए जी न्यूज के मालिक डॉ सुभाष चंद्रा गोयल को और उनकी पूरी टीम को, विशेषकर पत्रकारों सुधीर चौधरी और रोहित सरदाना को (जिन्होंने स्क्रीन पर आकर हिम्मत दिखाई) बधाई देनी चाहिए.

हिन्दुस्तान दुनिया के उन मुल्कों में है, जहां बड़े पैमाने पर आतंकवादी गतिविधियां नहीं चल रही हैं. लेकिन हमारे यहां एक बड़ा वर्ग ऐसा है, जिनके वैचारिक खोखलेपन की वजह से हमारे देश में भी वैमनस्य अपनी

पराकाष्ठा पर जाकर हथियार उठा सकता है. हमारे पड़ोस में जो देश हैं, उन देशों में धर्म को लेकर, ईश्वर को लेकर, पूजा की पद्धति को लेकर बहस की कोई गुंजाइश नहीं है. वहां के समाज में यह माना जाता है कि अगर आप ईश्वर, धर्म या धर्म-ग्रंथ के ऊपर कोई सवाल उठाते हैं या किसी शंका का समाधान चाहते हैं तो आप मृत्यु को आमंत्रित करते हैं. लेकिन हिन्दुस्तान में धर्म और ईश्वर न केवल सहिष्णु है, व्यापक है और सबको समाहित करने वाला भी है. भारत में हिन्दू कट्टर धर्म नहीं है. एक जीवन शैली है. हमारे यहां 33 करोड़ देवी-देवता हैं, जिसमें जानवर, पक्षी, पेड़, पौधे, नदी, वायु, जल, अग्नि इन सबकी पूजा का प्रावधान है. हमारे यहां साकार ब्रह्म भी हैं और निराकार ब्रह्म भी हैं. हमारे यहां हम चाहें तो सबकी पूजा करें, चाहें तो किसी की पूजा न करें.

हमारे यहां यह माना जाता है और खासकर ईश्वर को मानने वाले भी यह कहते हैं कि हम ईश्वर को इसलिए मानते हैं क्योंकि ईश्वर हमें यह अधिकार देता है कि हम अगर उसको नहीं मानें तो भी वह हमें सजा नहीं देगा. इसीलिए हमारे यहां नास्तिक लोगों की बड़ी संख्या है. पूजा पद्धत्तियां भिन्न-भिन्न हैं. एक ही धर्म को मानने वाले लोगों में सैकड़ों प्रकार की पूजा पद्धत्तियां हैं. कोई किसी के ऊपर दबाव नहीं डालता.

इस विशाल, सहिष्णु धर्म को मानने वालों में से ही कुछ ने एक नई प्रक्रिया शुरू कर दी है. उनका यह कहना है कि हम अपने घर से बाहर जाने वालों की वापसी कर रहे हैं. उनका यह कहना है कि सबको एक तरह की पूजा करनी चाहिए. उनका यह भी कहना है कि जो हमारी बात नहीं मानता उसका विरोध करना हमारा धर्म है और इतना ही नहीं, वो धर्म के द्वारा देश को गरीबी के दलदल में ले जाना चाहते हैं.

इस विशाल, सहिष्णु, सबको समाहित करने वाले, सबको विकसित होने का मौका देने वाले, धर्म को मानने वालों में से ही कुछ ने एक नई प्रक्रिया शुरू कर दी है. उनका यह कहना है कि हम अपने घर से बाहर जाने वालों की वापसी कर रहे हैं. उनका यह कहना है कि सबको एक तरह की पूजा करनी चाहिए. उनका यह भी कहना है कि जो हमारी बात नहीं मानता उसका विरोध करना हमारा धर्म है और इतना ही नहीं, वो धर्म के द्वारा देश को गरीबी के दलदल में ले जाना चाहते हैं. बजाय इसके कि हिन्दू धर्म के नाम पर शामिल विभिन्न वर्गों को गरीबी के दलदल से बाहर निकालें, वो उसे उसी दलदल में फंसा देना चाहते हैं. अब यह बयान हिन्दू धर्म का नेतृत्व करने वाले एक संगठन की तरफ से आया है कि हिन्दुओं को बहुत सारे बच्चे पैदा करने चाहिए. बच्चे पैदा करने का अर्थ क्या होता है, यह वह खुद जानते हैं. लेकिन वह देश में गरीबों की एक बड़ी संख्या और पैदा करना चाहते हैं.

ये मुद्दे हैं, जिन मुद्दों के ऊपर भारत में रहने वाले सभी विचारधाराओं को मानने वाले, सोचने समझने वाले लोगों के सामने यह सवाल खड़ा हो गया है. सवाल यह है कि क्या हम अपने देश को उन देशों की तरह बनाना चाहते हैं जहां धर्म पर, धर्मग्रंथों पर, ईश्वर के ऊपर कोई भी सफाई नहीं मांगी जा सकती है? क्या हम इस देश में एक धार्मिक कठमुल्लापन पैदा कर एक धर्म संसद जैसी संस्था बनाकर सब लोगों को जबरदस्ती उसका अनुयायी बनाना चाहते हैं. अगर ऐसा होगा तो इसका परिणाम क्या होगा?

क्या इसका परिणाम वैसा ही नहीं होगा, जैसा हमारे पड़ोसी मुल्कों में है या दुनिया के बहुत सारे देशों में है. जहां पर एक ही ईश्वर, एक ही धर्म, एक ही धर्मग्रंथ को मानने वाले हाथों में बंदूकें लेकर एक दूसरे की हत्या कर रहे हैं. क्योंकि उनका मानना है कि हमारे धर्म की परिभाषा सही है, हमारे धर्मग्रंथ की परिभाषा सही है, और हमारे ही मुल्क में रहने वाले बाकी लोगों की धर्मग्रंथों की परिभाषा या बाकी लोगों द्वारा की गई ईश्वर की परिभाषा गलत है और ऐसे लोग मौत की सजा के हकदार हैं.

अगर हमारे देश में भी यही परंपरा डालने की कोशिश उन लोगों के द्वारा हुई, जो धर्म को नहीं समझते हैं, जो ईश्वर को नहीं समझते हैं, जो 33 करोड़ देवी-देवताओं के अभ्युदय का मतलब नहीं जानते हैं. ऐसे लोग इस देश को, इस देश की संस्कृति को, इस देश के मानस को तबाह करने की योजना बनाने की शुरूआत कर चुके हैं.

जरूरत इस बात की है कि इस संपूर्ण कोशिश के ऊपर विराम लगे और यह विराम उस तरीके से नहीं लग सकता जिस तरीके से हमारे पड़ोसी मुल्कों में लगता है. इस देश में उन लोगों को खड़ा होना पड़ेगा जो लोग इस देश की पांच हजार साल पुरानी संस्कृति को या सैकड़ो साल पुराने भाईचारे को बरकरार रखना चाहते हैं. पर इसमें यह सावधानी रखने की जरूरत है कि हम अपनी कथाओं में खासकर पौराणिक कथाओं में वर्णित बातों को इतिहास का सत्य न बना दें. इतिहास और पौराणिक कथाओं में भेद होता है. बहुत सारे देशों में ऐसा होता है. लेकिन हिन्दुस्तान में आज तक ऐसा नहीं हुआ. अब एक नई कोशिश हुई है कि हम उन किवदंतियों को, पौराणिक कथाओं को, उनमें वर्णित बातों को इतिहास का सत्य बनाने और विज्ञान का सत्य बनाने पर तुले हुए हैं.

यह शताब्दी सपनों की शताब्दी हो, यह शताब्दी भाइचारे की शताब्दी हो, यह शताब्दी विकास की शताब्दी हो और यह शताब्दी गरीबी से लड़ने की शताब्दी हो, यह शताब्दी जाहिलियत से मुक्ति पाने की शताब्दी हो, यह कामना करनी चाहिए. इस कामना को याद करते हुए अपने पड़ोसी से उस कामना में शामिल होने का आग्रह करना चाहिए. मुस्कराहट बहुत अमूल्य चीज है. मुस्कराहट को बनाए रखना बहुत बड़ा धर्म है. इसी धर्म की पूजा हमें करनी चाहिए. ■

editor@chauthiduniya.com

उनके समर्पित शिष्यों ने उनका साथ छोड़ दिया

मेघनाद देसाई

ब्रिटिश राज की समाप्ति के बाद कांग्रेस राज ने सत्ता पर अपना क़ब्ज़ा जमा लिया. शासन व्यवस्था में कोई मूलभूत परिवर्तन नहीं आया, केवल सत्ता पर विराजमान लोगों की चमड़ी का रंग बदल गया. अंत में उनके समर्पित शिष्यों ने उनका साथ छोड़ दिया और विभाजन स्वीकार कर लिया. बाद में उन शिष्यों ने जिन्ना और ब्रिटेन पर विभाजन की सारी ज़िम्मेदारी डालकर खुद को दोषमुक्त कर लिया.

आज से सौ साल पहले एक जनवरी को मोहनदास करमचंद गांधी इंग्लैंड से भारत वापस आए थे. 19 वर्ष की आयु में बैरिस्टरी की पढ़ाई करने के लिए उन्होंने पहली बार अपना वतन छोड़ा था और बैरिस्टर बनने के बाद वह वहां एक दिन भी नहीं रुके थे. वह खुद को इंग्लिश बैरिस्टर कहा करते थे और पढ़ाई पूरी करने के बाद वह घर वापस नहीं आए. इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका में बिताई गई कुल 26 वर्षों की अवधि ने पोरबंदर के एक अनुभवहीन नौजवान को महात्मा बना दिया. आधुनिक इतिहास में महात्मा गांधी उन गिने-चुने लोगों में से हैं, जिन्हें वास्तव में वैश्विक व्यक्ति कहा जा सकता है. जब वह लंदन होते हुए हमेशा के लिए भारत आ रहे थे, तो लंदन में उन्होंने उस समय छिड़ी लड़ाई में भाग लेने के लिए एंबुलेंस कॉर्प में जवानों की भर्ती की. उस समय उनकी उम्र 45 वर्ष थी. प्रमुख व्यक्तियों की जीवनी में दिलचस्पी रखने वाले लोगों ने उसी समय से उन पर लिखना शुरू कर दिया था. अपने जीवन के अगले 33 वर्षों के दौरान उन्होंने दुनिया को कभी भी भूलने नहीं दिया कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम साम्राज्यवाद के विरुद्ध एक अंतरराष्ट्रीय आंदोलन का हिस्सा था.

हिंदुओं और मुसलमानों को मिलाकर ख़िलाफ़त आंदोलन शुरू करना 1200 साल पुरानी ख़िलाफ़त के ख़ात्मे के बाद के गंभीर नतीजों से निपटने का उनका अपना खास तरीका था. यह आंदोलन असफल हो गया था. ख़िलाफ़त की कमी को पूरा करने का प्रयास आज तक जारी है, आईएसआईएस इसकी एक मिसाल है. गांधी ने ख़िलाफ़त के बदले जो हासिल किया, वह था ब्रिटिश साम्राज्य की शांतिपूर्ण समाप्ति. अगर आज राष्ट्रमंडल देश हैं और ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एवं कनाडा में भारतीयों का एक संपन्न

हिंदुओं और मुसलमानों को मिलाकर ख़िलाफ़त आंदोलन शुरू करना 1200 साल पुरानी ख़िलाफ़त के ख़ात्मे के बाद के गंभीर नतीजों से निपटने का उनका अपना खास तरीका था. यह आंदोलन असफल हो गया था. ख़िलाफ़त की कमी को पूरा करने का प्रयास आज तक जारी है, आईएसआईएस इसकी एक मिसाल है. गांधी ने ख़िलाफ़त के बदले जो हासिल किया, वह था ब्रिटिश साम्राज्य की शांतिपूर्ण समाप्ति.

डायस्पोरा है, तो वह इसलिए है, क्योंकि अपने समय के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य को क्रांतिकारी अहिंसक तरीके से झुकने पर मजबूर किया गया था. गांधी ने अपने लोगों के जीवन में सुधार के लिए हरसंभव प्रयास किया. वह एक कठिन टास्क मास्टर थे, विशेष रूप से अपने नज़दीकी लोगों के लिए, जैसा कि उनके बेटे हीरालाल के संबंध में था. उन्होंने लोगों में स्वच्छता और श्रम की गरिमा की भावना पैदा करने के साथ-साथ उनमें सरल जीवन के गुण और वंचितों के कल्याण के लिए समर्पण की भावना को भी उजागर किया. उन्होंने अपने धर्म से रीति-रिवाज ख़त्म करके उसे आसान बनाने की कोशिश की और बड़े मंदिरों में जाने की बजाय सभी

धर्मों को एक साथ लाने की कोशिश की. उन्होंने इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका में अपने ईसाई और यहूदी मित्रों से उनके धर्म की अच्छी बातें अपनाईं. उन्होंने जैन दर्शन के अच्छे विचार अपना कर अपने धर्म की समझ का विस्तार किया, इस्लाम की भावना शामिल करके दो समुदायों के बीच की दूरी मिटाने की कोशिश की. उन्होंने अपने सनातन धर्म का धर्मांतरण के लिए प्रचार नहीं किया. वह मानते थे कि उनका जीवन ही उनके धर्म के संदेश को फैलाने के लिए काफी है. साम्राज्यवाद पर उनकी विजय लगातार अहिंसक लड़ाई की वजह से संभव हो पाई थी. अपनी बड़ी-बड़ी जनसभाओं में मौजूद सुरक्षाकर्मियों से वह कहा करते थे कि उनकी लड़ाई उनसे नहीं, बल्कि साम्राज्य से है. उन्होंने लंकाशायर के कपड़ा मज़दूरों को यह विश्वास दिलाया कि विदेशी कपड़ों का उनका बहिष्कार उनकी वजह से नहीं है, बल्कि उस व्यवस्था की वजह से है, जो उनके देशवासियों का दमन करती है और खुद अपने लोगों का भी.

इसके बावजूद वह अपने ही लोगों में असफल रहे. वह सोचते थे कि छुआछूत शांतिपूर्ण तरीके से ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. वर्ण व्यवस्था समाप्त नहीं हुई. केवल मुट्ठी भर लोगों ने ही उनके साधारण जीवन का विचार अपनाया. उन्होंने 30 वर्षों तक जिस पार्टी का नेतृत्व किया, उसी ने उनके अहिंसा के सिद्धांत पर ज़ुबानी जमा खर्च के अलावा कुछ नहीं किया. उनका यह आग्रह भी नज़रअंदाज़ कर दिया गया, जिसमें वह आज़ादी के बाद कांग्रेस को एक राजनीतिक दल की बजाय एक समाज सुधार आंदोलन में तब्दील करना चाहते थे. दरअसल, ब्रिटिश राज की समाप्ति के बाद कांग्रेस राज ने सत्ता पर अपना क़ब्ज़ा जमा लिया. शासन व्यवस्था में कोई मूलभूत परिवर्तन नहीं आया, केवल सत्ता पर विराजमान लोगों की चमड़ी का रंग बदल गया. अंत में उनके समर्पित शिष्यों ने उनका साथ छोड़ दिया और विभाजन स्वीकार कर लिया. बाद में उन शिष्यों ने जिन्ना और ब्रिटेन पर विभाजन की सारी ज़िम्मेदारी डालकर खुद को दोषमुक्त कर लिया. दरअसल, उन्होंने गांधी को भरोसे में लिए बिना ही विभाजन को अपनी स्वीकृति दे दी थी. उसके बाद गांधी ने वही किया, जिसमें वह दक्ष थे. उन्होंने विभाजन की नाइंसाफियां सुधारने के क्रम में अपने प्राणों की आहुति दे दी. पाकिस्तान के हक़ की लड़ाई लड़ने की वजह से आज तक उन्हीं के लोगों ने उन्हें माफ़ नहीं किया है. इसी वजह से उनकी हत्या हुई और इसी वजह से उनके हत्यारे की पूजा होती है. ■

feedback@chauthiduniya.com

सर्दियों में रखें अपने स्वास्थ्य का ख्याल

सर्दी का मौसम दमा रोगियों के लिए खास तकलीफदायक होता हैं क्योंकि सर्दी-जुकाम व गले में सूजन पैदा करने वाले बैक्टीरिया व वायरस इस रोग को बढ़ा देते हैं. सांस लेने में परेशानी होना, दम घुटना, सांस लेते समय आवाज होना, सांस फूलना, छाती में कुछ जमा हुआ सा या भरा हुआ सा महसूस होना, बहुत खांसने पर चिकना-चिकना कफ आना, मेहनत वाले काम करते समय सांस फूलना आदि दमे के लक्षण होते हैं. ठंडी हवायें दमा के लक्षणों को गंभीर बना सकती हैं इसलिए दमा के मरीजों को मौसम के अचानक बदलाव से सावधान रहना चाहिए खास तौर पर सुबह के वक्त गर्म बिस्तर से उठकर एकदम खुली हवा में नहीं जाना चाहिए , बल्कि थोड़ा इंतजार करें.

मोनिशा भटनागर

सर्दियों का मौसम अपने साथ सेहत से जुड़ी कई समस्याएं भी लेकर आता है. इस दौरान नाक बहना, लगातार छींकें आना, गले में खराश, सीने में जकड़न जैसी तकलीफें होना आम है. इसलिए इस मौसम में अपनी सेहत को लेकर थोड़ा सजग रहने की जरूरत होती है. सर्दियों में स्वस्थ रहने के लिए अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाना बेहद अहम है. जिन लोगों की प्रतिरक्षा प्रणाली ठीक होती है, उन्हें सर्दी-जुकाम आदि जैसी समस्याएं आसानी से नहीं होती. इसके लिए अपना खान-पान ठीक रखें, खाने में पपीता, कद्दू, गाजर, टमाटर, पालक, अमरूद जैसी मौसमी सब्जियों और फलों को जरूर शामिल करें, जिससे आपके शरीर का तापमान मौसम के मुताबिक गर्म रहे, पूरी नींद लें और थोड़ा व्यायाम भी करें.आइये सर्दियों में होने वाली विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं पर नज़र डालते हैं.

जुकाम, खांसी और गले में खराश

सर्दी के मौसम में हमारे शरीर के तापमान में गिरावट आ जाती है, जिससे श्वसन संक्रमण होने की आशंका बढ़ जाती है. इस मौसम में ठंडी और शुष्क हवा के कारण जुकाम-खांसी के विषाणु ज़्यादा फैलते हैं. इसी वजह से सर्दियों के

मौसम में अकसर लोगों को खांसी की समस्या रहती है. ऐसे में ठंडी चीज़ें जैसे कि कोल्ड ड्रिंक आइसक्रीम आदि खाने से तकलीफ में इज़ाफा हो सकता है. अगर आपको साइनस की समस्या है तो धूल- मिट्टी और कोहरे से अपना बचाव करें. ठंड में बाहर जाते समय सिर और गला हमेशा ढक कर रखें. यदि गले में खराश हो जाए तो तकलीफ दूर करने के लिए गुनगुने पानी में नमक डालकर गरारे(गार्गल) करें.

दमा या अस्थमा

दमा सांस का रोग है, इसमें सांस की नलियों में विशेष संवेदी तत्वों के संपर्क में आते ही सिकुड़न आ जाती है. दमा को आनुवांशिक और पर्यावरणीय कारकों का संयोजन माना जाता है. सर्दी का मौसम दमा रोगियों के लिए खास तकलीफदायक होता है क्योंकि सर्दी-जुकाम व गले में सूजन पैदा करने वाले बैक्टीरिया व वायरस इस रोग को बढ़ा देते हैं. सांस लेने में परेशानी होना, दम घुटना, सांस लेते समय आवाज होना, सांस फूलना, छाती में कुछ जमा हुआ सा या भरा हुआ सा महसूस होना, बहुत खांसने पर चिकना-चिकना कफ आना, मेहनत वाले काम करते समय सांस फूलना आदि दमे के लक्षण होते हैं. ठंडी हवायें दमा के लक्षणों को गंभीर बना सकती हैं इसलिए दमा के मरीजों को मौसम के अचानक बदलाव से सावधान रहना चाहिए खास तौर पर सुबह के वक्त गर्म बिस्तर से उठकर एकदम खुली हवा में नहीं जाना चाहिए , बल्कि थोड़ा इंतजार करें. सर्दियों का मौसम शुरू होते ही, सर्दी और फ्लू की समस्या भी शुरू हो जाती है और एक साधारण सर्दी का वायरस भी घातक अस्थमा के दौरे को ट्रिगर कर सकता है. ऐसा इसलिए क्योंकि अस्थमा में फेफड़े पहले से ही अतिसंवेदनशील और अधिक प्रतिक्रियाशील होतें हैं. इसलिए किसी भी वायरस में जो फेफड़ों को प्रभावित करता है उसकी तेजी और आसानी से अस्थमा के दौरे ट्रिगर करने की प्रवृत्ति होती है. दमा रोगियों को डॉक्टर की सलाह के मुताबिक इनहेलर और नैजल स्प्रे आदि नियमित रूप से इस्तेमाल करना चाहिए. साथ ही उन्हें हमेशा अपने पास रखना चाहिए क्योकि ठंड के दिनों में सबसे ज्यादा परेशानी दमा के मरीजों को होती है. चिकित्सकों का कहना है कि दमा को बढ़ाने वाले एलर्जी के तत्व ठंडे मौसम में ज्यादा होने की वजह से दमा के मरीजों को ज्यादा तकलीफ होती है, ऐसे में दमा रोगियों को कोहरे से विशेष रूप से बचना चाहिए. उन्हें जल्दी-जल्दी गर्म और सर्द वातावरण में भी नहीं जाना चाहिए.

ब्रोंकाइटिस

ब्रोंकाइटिस एक श्वांस रोग है जो फेफड़ों में स्थित सबसे छोटे वायु मार्ग को प्रभावित करता है. यह हर उम्र के लोगों में पाया जाता है लेकिन अधिकांशत: यह बच्चों में दिखाई देता है. यह ज्यादातर सर्दियों में होता है, विशेष रूप से फ्लू के प्रकोप के दौरान. खांसी और सांस में घरघराहट इसके सबसे प्रमुख लक्षण हैं. ऐसे में मरीज़ को सांस लेने में तकलीफ, सीने में दर्द के साथ कई हफ्तों तक खांसी रहती है. ब्रोंकाइटिस के मरीज़ निमोनिया यानि फेफड़ों के एक गंभीर बैक्टीरियल संक्रमण को विकसित करने के लिए अतिसंवेदनशील होते हैं. डॉक्टरों द्वारा बताये गए ईलाज़ के साथ-साथ मरीज़ के लिए ठंड से बचना बहुत जरूरी है.

गठिया या हड्डियों में दर्द

सर्दी में ठंड से बचाव न करने पर हडडियों का दर्द बढ़ जाता है. जिन लोगों को गठिया होता है, उन्हें सर्द वाता-वरण में अधिक परेशानी होती है. सीढ़ियां चढ़ने या उठने-बैठने में परेशानी होना, कुछ देर के लिए एक ही मुद्रा में रहने पर मांसपेशियों में अकड़न या दर्द होना या थोड़ा-सा भी अधिक दबाव पड़ने पर जोड़ों के हिस्सों में सूजन आना, जोड़ों से आवाज आना आर्थराइटिस के कुछ आम लक्षण हैं. सर्दियों का मौसम शुरू होते ही गठिया से पीड़ित मरीजों को जोड़ों में दर्द महसूस होने लगता है, इसके अलावा तापमान कम होने के कारण शरीर की मांसपेशियां भी अन्य दिनों के मुकाबले तंग हो जाती हैं. इस कारण कमर, गर्दन, कंधों व

शरीर के अन्य हिस्सों में दर्द की शिकायत बढ़ जाती हैं. ऐसे में अपने शरीर को गरम रखें, गरम कपड़े पहनें, शरीर के जिस हिस्से में दर्द हैं उसकी गरम पानी की बोतल से करें व हल्की-फुल्की एक्सरसाइज करते रहें.

हृदय संबंधित रोग

सर्दियों में ब्लड प्रेशर बढ़ जाने के कारण हृदयाघात या हार्ट अटैक होने की संभावना बढ़ जाती है. सर्दियों में रक्त वाहिनीयों के सिकुड़ जाने और ब्लड प्रेशर के बढ़ जाने से जरूरत के मुताबिक खून की आपूर्ति बनाए रखने के लिए दिल को कई गुना ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जिससे हृदय पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है और हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है. डायबिटीज या हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों को इस मौसम में खास ध्यान रखने की जरूरत होती है क्योकि सर्दियों के दौरान डायबिटीज के मरीजों में दिल और मस्तिष्क आघात का खतरा बढ़ जाता है. कड़ाके की ठंड में अचानक बाहर निकलना दिल के मरीजों के लिए खतरनाक हो सकता है इसलिए जरूरी है कि वे पर्याप्त गर्म कपड़े पहनकर ही निकलें. इसके अलावा अपने खान-पान का भी खास ख्याल रखना आवश्यक है जिससे ब्लड प्रेशर और डायबिटीज नियंत्रण में रखी जा सके.■

हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों को इस मौसम में खास ध्यान रखने की जरूरत होती है .

feedback@chauthiduniya.com

पाकिस्तानी महिला जासूस

हुस्न के जाल में फंसा भारतीय जवान

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

कहते हैं कि जब हुस्न अपना जलवा दिखाता है तो अच्छे से अच्छा आदमी उसके सामने घुटने टेक देता है क्या राजा क्या रंक. इसी तरह एक पाकिस्तानी हसीना के जाल में एक भारतीय सैनिक भी फंस गया और लंबे समय तक उस महिला को सेना के राज बताता रहा. यह वाकया हाल ही में सामने आया है.

40 वर्षीय पाटन कुमार पोद्दार भारतीय सेना में सूबेदार के पद पर कार्यरत था. उसकी पोस्टिंग आंध्रप्रदेश के सिंकदराबाद छावनी की 151 एमसी/एमएफ डिटैचमेंट में थी. सिकंदराबाद में रहते हुए फेसबुक में अनुष्का अग्रवाल नाम की एक लड़की से उसकी दोस्ती हुई. लड़की से उसकी बातचीत का दौर शुरू हुआ. इसी दौरान दोनों ने अपनी निजी जानकारियां साझा करना शुरू की. सूबेदार पोद्दार ने बताया कि वह सेना में काम करता है और पश्चिम बंगाल के माल्दा का रहने वाला है. उस पाकिस्तानी जासूस ने अपना संबंध उत्तर प्रदेश के झांसी से बताया. उसने यह भी बताया कि उसके पिता इंडियन एयर फोर्स के रिटायर्ड कमांडर हैं और फिलहाल झांसी में संयुक्त राष्ट्र की एक एनजीओ चलाते हैं. जिसमें वह भी अपने पिता का सहयोग करती है. धीरे-धीरे उनकी बातचीत का सिलसिला और बढ़ता गया. कुछ समय बाद अनुष्का ने सूबेदार को बताया कि वह उसे पसंद करती है और उससे मोहब्बत करने लगी है. पोद्दार को इस बात पर यकीन नहीं हुआ. प्यार-मोहब्बत के बीच एक दिन

उस लड़की ने पोद्दार को अपने पिता की एनजीओ के लिए काम करने का प्रस्ताव दिया और उसे भारतीय सेना का ऑनलाइन सर्वे करने के एवज में 10 हज़ार रुपये देने का वादा भी किया. पोद्दार घर बैठे हो रही कमाई के लालच में उस काम करने की हामी भर दी. पोद्दार ने महिला के इशारे पर एक ऑनलाइन फार्म भरा, जिसमें पेशा और निजी ब्योरे जैसी जानकारियां देनी थी. ताकि पोद्दार को इस बात का कतई शक न हो कि कोई उसकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके उसे देशद्रोह के रास्ते पर बढ़ा रहा है. इसके बाद पोद्दार ने अनुष्का को अपनी जानकारियां ई-मेल कर दीं.

धीरे-धीरे सर्वे के नाम पर वह उस लड़की को सिंकदराबाद छावनी की सेना से जुड़े राज और जानकारियां उपलब्ध कराता रहा और वह उसके खाते में इसके एवज में पैसे जमा करती रही. धीरे-धीरे उसे काम में बांधे रखने के लिए उस महिला जासूस ने जवान को अपनी नग्न तस्वीर भेजनी शुरू कीं. पोद्दार दिन-ब-दिन उसके जाल में फंसता जा रहा था. उसे इस बात की भनक भी नहीं लगी कि उसने सेना से जुड़ी कौन-कौन सी अहम जानकारियां उस लड़की तक पहुंचा दीं. इसके बाद उसने अपने नग्न वीडियो भेजने शुरू कर दिए. और उसके मालदा के एक बैंक खाते में पैसे जमा करवाती रहीं. जवान को एक तरफ दो पैसे मिल रहे थे दूसरी तरफ उसे हुस्न की नुमाइश भी देखने को मिल रही थी. इससे बेहतर उसके लिए क्या हो सकता था. वह उस महिला के हुस्न के जाल में फंसता जा रहा था. वह उस लड़की के प्यार नें अंधा हो गया था. इसी बीच अनुष्का ने पोद्दार को उसके मोबाइल फोन पर कॉल करना शुरू किया. उनके बीच धंटों लंबी बातें होने लगीं. अनुष्का समय-समय पर पोद्दार के खाते में पैसे जमा करवाती रही और लगातार सेना से जुड़ी अहम जानकारियां हासिल करती रही. उस पाकिस्तानी जासूस ने पोद्दार को लंदन घुमाने का वादा भी किया. उस हसीना ने इतनी सफाई से अपने काम को अंजाम दिया कि पोद्दार को कभी उसपर शक नहीं हुआ. लेकिन भारतीय सेना को पोद्दार पर शक हो गया और उस पर नज़र रखनी शुरू की. जब सेना को उसकी जासूसी पर यकीन हो गया तो उसे गिरफ्तार कर लिया गया. जांच के दौरान सेना पुलिस ने भारतीय सेना से जुड़ी बहुत सी संदिग्ध जानकारियां पोद्दार के कंप्यूटर से बरामद की. सेना उससे पूछताछ कर रही है और जांच जारी है. ■

चौथी दुनिया
CHAUTHI DUNIYA

चौथी दुनिया की हर खबर अब आपके Android फोन पर भी उपलब्ध,
Play Store से Download करें | CHAUTHI DUNIYA APP |

ख़ास ख़बरें

इमरान की शादी पर विवाद

पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर और पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ के प्रमुख इमरान ने दोबारा निकाह किया है. उनकी दूसरी शादी पर विवाद पैदा हो गया है. इमरान ख़ान ने जैसे ही यह स्वीकार किया कि वह अब एक शादीशुदा आदमी हैं, उसके फौरन बाद ही इस पर उनके देशवासियों की फेसबुक और ट्विटर जैसी सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर मिली–जुली प्रतिक्रियाएं सामने आईं. इमरान ने डॉन न्यूज़ पर एक शो होस्ट करने वाली रेहम ख़ान से निकाह किया है. वह पहले बीबीसी से जुड़ी थीं. पाकिस्तान में कुछ लोगों ने उन्हें बधाई दी है तो कुछ ने इमरान की पूर्व पत्नी जेमाइमा ख़ान के साथ सहानुभूति भी जताई है. लोग इमरान की नई पत्नी रेहम पर भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर भी टिप्पणियां कर रहे हैं. जेमाइमा ने पाकिस्तान से आ रहे ट्विट्स का जवाब भी दिया. वह लोगों को समर्थन के लिए शुक्रिया कह रही हैं. जेमाइमा के समर्थकों ने लिखा है कि जेमाइमा ख़ान, आप एक बेटी, बहन और मां के तौर पर लाखों पाकिस्तानियों के लिए सम्मानजनक रहेंगी. वैसे रेहम ने निकाह की ख़बर आने के कहा कि वह ख़ुद को हमेशा पाकिस्तान की मानद नागरिक मानती रहेंगी. साथ ही उन्होंने इमरान के लिए ख़ुशियों की भी कामना की हैं. उन्होंने लिखा कि मैं हमेशा पाकिस्तान से मोहब्बत करती रहूंगी.■

भारत-पाक दोस्ती बस सिर्फ वाघा बॉर्डर तक

नई दिल्ली और लाहौर के बीच चलने वाली सदा-ए-सरहद बस सेवा को वाघा सीमा तक ही सीमित कर दिया गया है. पाकिस्तान की ओर से कहा गया है कि आतंकी खतरे की वजह से यह फैसला लिया गया है. नई दिल्ली से आ रहे यात्रियों और भारत जाने वाले यात्रियों को वाघा सीमा पर उतर कर दूसरी बस पकड़ने के लिए कहा गया है. वाघा सीमा भारतीय राज्य पंजाब के अमृतसर शहर और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित लाहौर के बीच स्थित है. दोनों देशों के बीच यह बस सेवा नागरिकों के संपर्क को मजबूत बनाने के लिए 16 मार्च 1999 को शुरू की गई थी. इस बस में बैठकर भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी लाहौर गए थे. कई बार इस बस सेवा को रोका गया है इसके बाद कई बार बहाल किया गया है. भारत–पाकिस्तान के बीच रिश्तों में तल्खी का असर इस बस सेवा पर सीधे तौर पर दिखाई देता है.■

शार्ली एब्दो पर हमले में दस पत्रकार मारे गए

पैगंबर मोहम्मद और आईएसआईएस के मुखिया अबु बक्र अल बगदादी का कार्टून छापने वाली सटायर(व्यंग्य) मैगजीन शार्ली एब्दो के कार्यलाय पर आतंकवादी हमला हुआ. इस आतंकवादी हमले में 12 लोगों की मौत हो गई. हमले में दो पुलिस कर्मियों सहित दस पत्रकारों की मौत हो गई. मैगजीन के एडिटर इन चीफ स्टीफन शार्बोनियर और पैगंबर का कार्टून बनाने वाले कार्टूनिस्ट भी शामिल हैं. स्टीफन खुद भी एक कार्टूनिस्ट थे. उन्हें पहले भी कई बार धमकियां मिल चुकी थीं. स्टीफन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक थे. उन्होंने कई धारदार कार्टून बनाए. डेनमार्क की मैगजीन में छपे पैगंबर मोहम्मद के विवादित कार्टून को एब्दो में दोबारा छापने का फैसला भी स्टीफन का ही था. हमलावर ने मैग्जीन के कार्यालय पर गोलियां चलाने के बाद कहा कि हमने पैगंबर के अपमान का बदला ले लिया है.■

बांग्लादेश

लोकतंत्र ख़तरे में

वसीम अहमद

साल 1971 का भूत बांग्लादेश का पीछा नहीं छोड़ रहा है. यह भूत किसी न किसी शक्ल में अपने ख़ूनी पंजे से बांग्लादेश को लहुलुहान कर रहा है. बांग्लादेश उन देशों में शामिल है, जहां समस्याएं अधिक हैं और संसाधन कम. बांग्लादेश का नाम दुनिया के ग़रीब देशों में शुमार होता है. बांग्लादेश की स्थापना के समय जो सपना देखा गया था, वह आज तक पूरा नहीं हो सका. न तो देश में शांति स्थापित हो सकी और न ही ग़रीबी दूर करने के लिए कोई ठोस पहल की गई. हालांकि निजि स्तर पर नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस ने बहुत काम किए, लेकिन सरकार उसका लाभ भी नहीं उठा सकी. आज़ादी के बाद से अब तक यहां की सरकारें अपने हित के लिए क़ानूनों का प्रयोग करती आ रही हैं और जनता का शोषण होता रहा है, लेकिन वर्ष 1996 के बाद से देश के जो हालात हैं वे बेहद दुर्भाग्यपूर्ण हैं.

1996 में शेख हसीना ने बांग्लादेश जमात–ए–इस्लामी के समर्थन से चुनाव लड़ा और सरकार बनाई. इस दौरान बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को मज़बूत करने के लिए कोई ठोस काम नहीं हुआ. जनता में नाराज़गी बढ़ती गई, इसका नतीजा यह हुआ कि 2001 के चुनावों में 40 प्रतिशत वोट प्राप्त करने के बावजूद उनकी पार्टी सरकार नहीं बना सकी. पूर्व सहयोगी जमात–ए–इस्लामी ने हसीना की पार्टी का साथ छोड़कर बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी(बीपीएन) के साथ हो गई और उनकी सरकार बनाने में मदद की. इसके बाद ख़ालिदा जिया ने देश की कमान संभाली. बस यहीं से जमाते इस्लामी और शेख़ हसीना के बीच दुश्मनी की बुनियाद पड़ी. इस दुश्मनी का बदला साल 2009 के आम चुनावों के बाद लिया गया. इस चुनाव में हसीना एक बार फिर सफल हुईं. सरकार बनाते ही उन्होंने जमात–ए–इस्लामी एवं बीएनपी से राजनीतिक प्रतिशोध लेने के लिए इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल स्थापित किया. उनके इस फैसले का पूरी दुनिया में विरोध किया गया, लेकिन सभी विरोधों को नज़र अंदाज़ करके जमात–ए–इस्लामी और बीएनपी के कई महत्वपूर्ण नेताओं पर मुक़दमे चलाये गये. ये वही नेता थे, जिन्होंने बांग्लादेश की स्थापना के समय बांग्लादेश को अलग मुल्क बनाने का विरोध किया था. इसी वजह से पार्टी पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, लेकिन 1975 में जमात–ए–इस्लामी पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए गये. इसके बाद इस पार्टी ने चुनावों में हिस्सा लिया और कई बार सरकार बनाने वाली पार्टी को समर्थन दिया, लेकिन इन सभी बिंदुओं को नज़रअंदाज़ करके 2009 में इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्युनल स्थापित किया गया और बांग्लादेश के कई नेताओं को अपराधी घोषित किया गया. इनमें अब्दुल क़ादिर मुल्ला और मुतीउर रहमान जैसे कद्दावर नेता भी शामिल थे. इन नेताओं को फांसी की सज़ा देने के बाद देश में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए और नतीजे में सैंकड़ों लोग मारे गए, लेकिन सरकार ने इन विरोध प्रदर्शनों और हिंसा पर कोई ध्यान नहीं दिया. मुक़दमों का सिलसिला बदस्तूर जारी रहा. इसके बाद 5 जनवरी, 2014 को देश में एक बार फिर आम चुनाव हुए. इन चुनावों का विपक्षी पार्टियों ने बहिष्कार किया. विपक्ष की मांग थी कि सत्ताधारी शेख हसीना संविधान के अनुसार सरकार से अलग हो जाएं और अंतरिम सरकार की निगरानी में स्वतंत्र चुनाव संपन्न कराये जाएं, लेकिन हसीना सत्ता छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुईं, नतीजतन विपक्षी दलों ने आम चुनाव में हिस्सा नहीं लिया. विपक्ष के बहिष्कार का फ़ायदा सत्तापक्ष को हुआ और हसीना वाजिद की पार्टी को एक बार फिर बहुमत हासिल करने में सफल हुई और अपनी सरकार बनाई. सरकार के गठन के विरोध में विपक्ष ने बहुत आवाज़ उठाई लेकिन उनकी आवाज़ दब कर रह गई. इस बार हसीना की प्रताड़ना का शिकार जमात–ए–इस्लामी ही नहीं, अन्य विपक्षी पार्टियां भी थीं.

चुनावों के बहिष्कार का आहवान करने के कारण मतदान से एक सप्ताह पहले ही विपक्ष नेता ख़ालिदा जिया को 27 दिसंबर 2013 को उनके निवास में नज़रबंद कर दिया गया था, जब वह विपक्षी दलों की सभाओं की अध्यक्षता कर रही थीं. इनकी नज़रबंदी के बाद सरकार विरोध में प्रदर्शन तेज़ हो गये और देश भर में हुई झड़पों और दंगों में तकरीबन 100 से अधिक लोगों की मौत हुई थी. हजारों की संख्या में लोग घायल हुए थे. विपक्षी दलों की ओर से चुनावों का बहिष्कार शेख हसीना वाजिद और उनकी पार्टी के लिए तथाकथित चुनावों में कारगर साबित हुआ और उन्हें खुला मैदान मिल गया. इस वजह से उन्होंने अपनी मर्जी से चुनाव कराकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और अपनी सरकार बना ली. खाालिदा जिया और उनके सहयोगी दल लगातार इन चुनावों को ख़ारिज करने और दोबारा पारदर्शी तरीके से चुनाव कराने की मांग करती रहीं, लेकिन सरकार पर उनकी मांग का कोई असर नहीं हुआ. अब वह अपनी मांग के पक्ष में जनसमर्थन जुटाकर सरकार पर दबाव बनाना चाहती थीं. इसके लिए वह ढाका से लॉन्ग मार्च करना चाहती थीं. लेकिन इस बार भी शेख हसीना ने ताक़त का प्रयोग करते हुए ख़ालिदा को उनके ऑफिस में नज़रबंद कर उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की. वहां के अखबारों में छपी खबरों के अनुसार वह लॉन्ग मार्च की पूरी तैयारी कर चुकी थीं. ठीक एक दिन पहले वह अपने ऑफिस में थीं और उन्हें वहां से अपने किसी संबंधी का हालचाल जानने जाना था. जैसे ही वह ऑफिस से बाहर निकलीं आफिस के परिसर में उपस्थित सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें यह कहकर बाहर जाने से रोक दिया कि उनके बाहर जाने से शांति भंग होने का ख़तरा है. यही नहीं, किसी और को भी उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा था, तब उन्हें मालूम हुआ कि उन्हें नज़रबंद कर दिया गया है. हालांकि सरकार नज़रबंदी की बात से लगातार इंकार करती रही, लेकिन बांग्लादेश में इस घटना के बाद जो प्रदर्शन हुए. इस विरोध–प्रदर्शन में कई लोगों की जानें गईं, इससे अंदाज़ा हो जाता है कि ख़ालिदा को सुरक्षा देने के नाम पर उनके ऑफिस में नज़रबंद कर दिया गया. इस तरह शेख़ हसीना वाजिद सरकार ने बांग्लादेश में विपक्ष के खिलाफ़ कार्रवाई करके लोकतंत्र का गला घोटने की कोशिश कर रही हैं. वह लोकतंत्र जिसे बांग्लादेश की स्थापना के समय उनके पिता एवं बंगपिता शेख़ मुजीबुर रहमान ने अपनाया था. शेख़ मुजीबुर रहमान के बाद देश में फौजी शासन कई बार लगा, लेकिन लोकतंत्र की वापसी होती रही और यह सिलसिला बिगड़ कर भी किसी न किसी तरह बरक़रार है.■

feedback@chauthiduniya.com

पाकिस्तान में सैन्य अदालत के गठन का विरोध

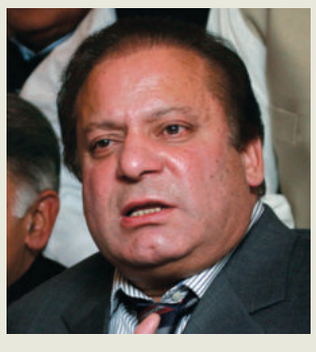

पेशावर के आर्मी स्कूल में बच्चों के क़त्लेआम के बाद चरमपंथियों के मामलों की सुनवाई के लिए पाकिस्तान में सैन्य अदालतों के गठन पर विचार किया जा रहा है. सरकार के इस क़दम पर नागरिक संगठन आपत्ति जता रहे हैं. प्रमुख मानवाधिकार कार्यकर्ता और बौद्धिक चिंतक इस क़दम का यह कह कर विरोध कर रहे हैं कि सैन्य अदालतों में पर्याप्त पारदर्शिता मुश्किल होगी. लेकिन नवाज़ शरीफ़ सरकार ने कहा है कि इन अदालतों में सब कुछ व्यवस्था के अनुरूप होगा. पाकिस्तान इन दिनों आंतरिक हिंसा का सामना कर रहा है. साउथ एशिया टूरिज्म पोर्टल के मुताबिक़ बीते एक दशक में चरमपंथी हिंसा में 56 हज़ार लोगों की मौत हुई है. पेशावर आर्मी स्कूल की दर्दनाक घटना के बाद सेना ने चरमपंथियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी. प्रधानमंत्री नवाज़ शरीफ़ ने आठ साल से मृत्युदंड पर लगी पाबंदी भी हटा ली है. इसके बाद मानवाधिकार समूहों की अपील के बावजूद कई लोगों को फांसी दी गई. माना जा रहा है कि पाकिस्तानी संसद दो सालों के लिए सैन्य अदालत को मंज़ूरी दे सकती है.■

बेअंत सिंह का हत्यारा पकड़ा गया

पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के हत्यारे गुरमीत सिंह उर्फ जगतार सिंह तारा को थाइलैंड में गिरफ्तार कर लिया गया है. भारतीय खुफिया एजेंसियों से तारा की लोकेशन के बारे में मिली खुफिया सूचनाओं के आधार पर थाइलैंड पुलिस ने उसे एक घर से गिरफ्तार किया. जानकारी के मुताबिक, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने वहां उसके ठहरने की व्यवस्था की थी. उसे भारत प्रत्यर्पित करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है. भारत सरकार जगतार सिंह तारा को पकड़ने के लिए थाइलैंड के अधिकारियों के लगातार संपर्क में थी. गुरमीत थाइलैंड में दूसरी पहचान से महीनों से छिपा हुआ था. थाइ नैशनल पुलिस के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल प्रावुत थावोरनसरी ने बताया कि गुरमीत सिंह पिछले साल अक्टूबर में थाइलैंड पहुंचा था और उसे कल पूर्वी प्रांत चोन बूरी में गिरफ्तार कर लिया गया. चोन बूरी प्रांतीय पुलिस और सैनिकों की एक टीम ने बांग लामुंग जिला स्थित नोंग फ्रेउ में एक मकान पर छापा मारा और सिंह को गिरफ्तार कर लिया.■

चौथी दुनिया ब्यूरो

feedback@chauthiduniya.com

किसान ने एक और लड्डू मुंह में उठाकर रखा और कहा, ऐसे. तीनों मन मार कर रह गए और बाद में किसान से बदला लेने का निश्चय किया. परदेश में धन कमाकर लौटने से पहले तीनों ने किसान से रात को खीर बनवाई और कहा, जिसे सबसे अच्छा सपना आएगा, वही इस खीर को सुबह खाएगा. चतुर किसान ने उनके सोने के बाद सारी खीर खा ली. सुबह तीनों भाइयों ने सपने सुनाने शुरू किए.

भवसागर से पार उतारेंगे साई

बाबा किस प्रकार भोजन तैयार कराकर वितरण किया करते थे उसका जिक्र नीचे कथा में है. हम सभी जानते हैं कि बाबा अल्पाहारी थे और वे थोड़ा बहुत जो कुछ भी खाते थे, वह उन्हें केवल दो गृहों से ही भिक्षा में उपलब्ध हो जाया करता था. लेकिन जब उनके मन में सभी भक्तों को भोजन कराने की इच्छा होती तो प्रारम्भ से लेकर अन्त तक संपूर्ण व्यवस्था वे स्वयं किया करते थे.

चौथी दुनिया ब्यूरो

सदगुरु साई बाबा धन्य हैं. उन्होंने विश्व को सुख शान्ति प्रदान की और भक्तों का कल्याम किया. जो भक्त बाबा के चरण–कमलों में अपने आप को समर्पित कर देते हैं, साई सदगुरु उनकी सदैव रक्षा करते हैं और उद्धार करते हैं.

मानव धर्म–शास्त्र में अलग–अलग युगों के लिये अलग–अलग साधनाओं का उन्नेख किया गया है. सतयुग में तप, त्रेता में ज्ञान, द्वापर में यज्ञ और कलियुग में दान का विशेष महत्व है . सर्व प्रकार के दानों में अन्नदान सबसे श्रेष्ठ है. जब दोपहर के समय हमें भोजन प्राप्त नहीं होता, तब हम विचलित हो जाते है . ऐसी ही स्थिति अन्य प्राणियों की अनुभव कर जो किसी भिक्षुक या भूखे को भोजन देता है, वही श्रेष्ठ दानी है. जब कोई अतिथि दोपहर के समय अपने घर आता है तो हमारा कर्तव्य हो जाता है कि हम उसका अभिन्नदन कर उसे भोजन करावें. अन्य दान जैसे–धन, भूमि और वस्त्र इत्यादि देने में तो पात्रता का विचार करना पड़ता है, लेकिन अन्न के लिये विशेष सोच विचार की आवश्यकता नहीं है. दोपहर के समय कोई भी अपने द्वार पर आवे, उसे भोजन कराना हमारा परम कर्तव्य है. अन्नदान के बिना अन्य सब प्रकार के दान वैसे ही अपूर्ण है, जैसे कि चन्द्रमा बिना तारे, पदक बिना हार, भक्तिरहित भजन, सिन्दूररहित सुहागिन, मधुर स्वरविहीन गायन, नमक बिना पकवान. जिस प्रकार अन्य भोज्य पदार्थों में दाल उत्तम समझी जाती है, उसी प्रकार समस्त दानों में अन्नदान श्रेष्ठ है.

बाबा किस प्रकार भोजन तैयार कराकर वितरण किया करते थे उसका जिक्र नीचे कथा में है. हम सभी जानते हैं कि बाबा अल्पाहारी थे और वे थोड़ा बहुत जो कुछ भी खाते थे, वह उन्हें केवल दो गृहों से ही भिक्षा में उपलब्ध हो जाया करता था. लेकिन जब उनके मन में सभी भक्तों को भोजन कराने की इच्छा होती तो प्रारम्भ से लेकर अन्त तक संपूर्ण व्यवस्था वे स्वयं किया करते थे. वे किसी पर निर्भर नहीं रहते थे और न ही किसी को इस संबंध में कष्ट ही दिया करते थे. पहले वे स्वयं बाजार जाकर सब वस्तुएं–अनाज, आटा, नमक, मिर्ची, जीरा और अन्य मसाले आदि वस्तुएं नगद दाम देकर खरीद लाया करते थे. यहां तक कि पीसने का कार्य भी वे स्वयं ही किया करते थे. मस्जिद के आंगन में ही एक भट्टी बनाकर उसमें अग्नि प्रज्वलित करके हंडी के ठीक नाप से पानी भर देते थे. हंडी दो प्रकार की थी–एक छोटी और दूसरी बड़ी. एक में सौ और दूसरी में पांच सौ व्यक्तियों का भोजन तैयार हो सकता था. कभी वे मीठे चावल बनाते और कभी पुलाव बनाते थे. कभी–कभी दाल और मुटकुले भी बना लेते थे. पत्थर की सिल पर महीन मसाला पीस कर हंडी में डाल देते थे. भोजन रुचिकर बने, इसका वे भरसक प्रयत्न किया करते थे. ज्वार के आटे को पानी में उबाल कर उसमें छांछ मिलाकर आमटी बनाते और भोजन के साथ सब भक्तों को समान मात्रा में बांट देते थे. भोजन ठीक बन रहा है या नहीं, यह जानने के लिये वे अपनी कफनी की बांहें ऊपर चढ़ाकर निर्भय हो उबलती हंडी में हाथ डाल देते और उसे चारों ओर घुमाया करते थे. ऐसा करने पर भी उनके हाथ पर न कोई जलन का चिन्ह और न चेहरे पर ही कोई व्यथा की रेखा प्रतीत हुआ करती थी. जब पूर्ण भोजन तैयार हो जाता, तब वे मस्जिद से बर्तन मंगाकर मौलवी से फातिहा पढ़ने को कहते थे, फिर वे म्हालसापति तथा तात्या पाटील के प्रसाद का भाग अलग रखकर शेष भोजन गरीब और अनाथ लोगों को खिलाकर उन्हें तृप्त करते थे. सचमुच वे लोग धन्य थे. कितने भाग्यशाली थे वे, जिन्हें बाबा के हाथ का बना और परोसा हुआ भोजन खाने को प्राप्त हुआ. बाबा के बालाजी परम भक्त थे. वे बाबा की निष्काम सेवा किया करते थे. दिन में जिन रास्तों से बाबा निकलते थे, उन्हें वे प्रातःकाल ही उठकर झाड़ू लगाकर पूर्ण स्वच्छ रखते थे. उनके बाद यह कार्य बाबा की एक परमभक्त महिला राधाकृष्ण माई ने किया और फिर अब्दुल ने. बालाजी जब अपनी फसल काटकर लाते तो वे सब अनाज उन्हें भेंट कर दिया करते थे. उसमें से जो कुछ बाबा उन्हें लौटा देते, उसी से वे अपने कुटुम्ब का भरणपोषण किया करते थे, यह क्रम अनेक वर्षों तक चला और उनकी मृत्यु के बाद भी उनके पुत्र ने इसे जारी रखा.

साई बाबा की चरण वंदना करनी चाहिए, वे विश्व के आधार हैं. यदि कोई अपनी इच्छा पूर्ण होने की धारणा लेकर बाबा की पूजा करता है, तो उसकी समस्त इच्छाएं शीघ्र पूरी हो जाती हैं. इसलिये भक्तों को किंचितमात्र भी भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है. हमारे सदगुरु तो जहाज है और वे हमें कुशलतापूर्वक इस भयानक भवसागर से पार उतार देंगे. ■

feedback@chauthiduniya.com

साई के ग्यारह वचन

1. जो शिरडी आएगा, आपद दूर भगाएगा.
2. चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुःख की पीढ़ी पर.
3. त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा.
4. मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस.
5. मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो.
6. मेरी शरण आ खाली जाए, हो कोई तो मुझे बताए.
7. जैसा भाव रहा जिस मन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का.
8. भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा.
9. आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वही नहीं है दूर.
10. मुझमें लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया.
11. धन्य-धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य.

साई भक्तों!

आप भी चौथी दुनिया को साई से जुड़ा लेख या संस्मरण भेज सकते हैं. मसलन, साई से आप कब और कैसे जुड़े. साई की कृपा आपको कब से मिलनी शुरू हुई. आप साई को क्यों पूजते हैं. कैसे बने आप साई भक्त. साई बाबा का जीवन और चरित्र आपको किस तरह से प्रेरित करता है. साई बाबा के बारे में अनेक किंवदंतियां हैं, क्या आपके पास भी कुछ कहने के लिए है? अगर हां, तो केवल 500 शब्दों में अपनी बात कहने की कोशिश करें और नीचे दिए गए पते पर भेजें.

चौथी दुनिया
एफ–2, सेक्टर–11, नोएडा (गौतमबुद्ध नगर), उत्तर प्रदेश, पिन–201301
ई–मेल feedback@chauthiduniya.com

पाठकों की दुनिया

धोनी का टेस्ट मैच से सन्यास

भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान महेन्द्र सिंह धोनी ने मेलबर्न टेस्ट के तुरंत बाद टेस्ट मैच से सन्यास की घोषणा कर दुनिया को चौंका दिया और अपने भारतीय क्रिकेट प्रेमियों को भी मायूस कर दिया. भारतीय क्रिकेट को आकाश की ऊंचाइयों पर ले जाने का श्रेय धोनी को ही जाता है, धोनी ने भारतीय क्रिकेट को एक नई ऊंचाई दी. उनके जुझारूपन को दुनिया सलाम करती है. मेलबर्न टेस्ट धोनी के दम पर ही ड्रा हुआ. वह जब तक क्रीज पर होते थे, जीत की उम्मीद बनी रहती थी और विपक्षी दल के हौसले पस्त रहते थे. धोनी के इस निर्णय के पीछे बी.सी.सी.आई की दबाव की राजनीति के संकेत भी साफ दिखाई दे रहे हैं, क्योकि पूर्व कप्तानों सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़ व सचिन तेंदुलकर के साथ भी अंतिम समय में बी.सी.सी.आई का व्यवहार अच्छा नहीं रहा था. कुछ भी हो, धोनी का यह निर्णय असामयिक व दुखद है. भारतीय टीम को और अधिक ऊचाइयों तक ले जाने के लिए धोनी की जरूरत है और उनके प्रशंसक भी चाहते हैं कि धोनी खेलते रहें. धोनी को अपने निर्णय पर पुनर्विचार करना चाहिए.

–राजेन्द्र शुक्ल, कानपुर, उत्तर प्रदेश.

आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं

कवर स्टोरी–पेशावर में मर गई इंसानियत(29 दिसंबर 2014–04 जनवरी 2015) पढ़ा. बहुत अच्छा आलेख है. मनीष कुमार ने बिल्कुल सही कहा है कि पेशावर में इंसानियत मर गई. पेशावर में आतंकवाद का सबसे घिनौना चेहरा हमें देखने को मिला. बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, अल्लाह का रूप होते हैं. तहरीके–ए–तालिबान के आतंकवादियों ने पेशावर के सैनिक स्कूल में हमला कर 100 से अधिक बच्चों को मौत के घाट उतार दिया. इससे साफ हो जाता है कि उनका कोई धर्म नहीं है और वह किसी धर्म और भगवान को नहीं मानते, किसी अल्लाह को नहीं मानते. उनके अंदर कोई इंसानियत नहीं है और वह इंसान नहीं केवल हत्यारे हैं. आतंकी किसी का नहीं हो सकते उनका केवल दहशत फैलाना और मासूमों की हत्या करना मकसद है. इसलिए पाकिस्तान को समझ जाना चाहिए और आतंकावद के खिलाफ लड़ाई में उसे भारत और पूरी दुनिया का साथ देना चाहिए. पूरी दुनिया को मिलकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़नी होगी और उसे खत्म करना होगा.

–कमलेश सिंह, बक्सर, बिहार.

असहाय के लिए ही जीना है

चौथी दुनिया समाचार पत्र (29 दिसंबर 2014–04 जनवरी 2015)पढ़ा. इस अंक में प्रकाशित सभी खबरें और आलेख तथ्यपरक हैं. पेज–4 पर प्रकाशित आलेख आम आदमी के खास काम पढ़कर बहुत अच्छा लगा और दूसरे लोगों को उनसे प्रेरणा मिलती है. आलेख में जिन लोगों के बारे में जानकारी दी गई है, वह सही मायने में बड़ा काम कर रहे हैं. इन लोगों के बारे में कम ही लोग जानते होंगे. यह बिल्कुल सही है कि आम लोग खास काम कर रहे हैं. वे सभी लोग असहाय लोगों और समाज के लिए कार्य करने लिए बधाई के पात्र हैं. हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मदद की जरूरत है. इसलिए समाज के हर नागरिक को इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और गरीब, असहाय व निचले तबके के लोगों के लिए कार्य करना चाहिए.

–अगुराग दीक्षित, कृष्णा नगर, दिल्ली.

कितने तैयार हैं हम

कमल मोरारका का आलेख आम आमदी की सुरक्षा के लिए हम कितने तैयार हैं (29 दिसंबर 2014–04 जनवरी 2015) पढ़ा. काफी विचारोत्तेजक है. मोरारका जी ने बिल्कुल सही कहा है कि हम कहां खड़ें हैं इस पर विचार करना चाहिए और एक बात उन्होंने कही कि आम आदमी के मन में विश्वास पैदा करना होगा कि हम असुरक्षित नहीं है. ऐसे में देश के गृहमंत्री राजनाथ सिंह को चाहिए कि पूरे देश में सुरक्षा का माहौल पैदा करें, जिससे लोगों के मन में अपनी सुरक्षा को लेकर कोई भय न हो. यह बात चौकाने वाली है कि देश के बड़े शहरों में आईएसआई और इंडियन मुजाहिदीन के स्लीपर सेल मौजूद हैं और अपना आपरेशन चला रहे है. एक बात यह कि मुंबई की पुलिस खुद इस स्लीपर सेल बारे में कह चुकी है, लेकिन वह पालिटिकल क्लियरेंस न मिलने की वजह से कुछ नहीं कर पा रही है यह बात समझ में नहीं आती. इस पर गृहमंत्री खुद संज्ञान लें और पुलिस को एक्शन लेने के लिए कहे. जांच एजेंसियों व पुलिस को ऐसे लोगों के खिलाफ जांच करनी चाहिए और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए.

–रेखा भारद्वाज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश.

संसद में सांसदों का व्यवहार

चौथी दुनिया समाचार पत्र (29 दिसंबर 2014–04 जनवरी 2015) पढ़ा. इस अंक में प्रकाशित सभी आलेख तथ्यपरक हैं. कवर स्टोरी के साथ संपादकीय पेज पर प्रकाशित सभी आलेख तथ्यों पर आधारित हैं और नई–नई जानकारी देने वाले हैं. जब तोप मुकाबिल हो पढ़ा. संतोष भारतीय का संपादकीय हमारे सांसद देशद्रोही हैं ने बहुत प्रभावित किया. इतना अच्छा और जानकारी परक संपादकीय पढ़कर बहुत खुशी हुई और गर्व हुआ कि आज भी कोई संपादक है जो इतनी हिम्मत के साथ लिख सकता है. संतोष भारतीय ने सांसदो के व्यवहार का विश्लेषण करते हुए जो लिखा है वह बिल्कुल सही है कि जब तक देश की जनता सांसदों के बारे में बात नहीं करेगी, तब तक इन सांसदों को अपना बुनियादी कर्तव्य भी याद नहीं आएगा. सांसदो को उनका कर्तव्य याद दिलाना होगा, क्योंकि सांसद अपने कर्तव्य को भूल चुके हैं, वह लोकसभा और राज्यसभा में अपने कर्तव्यों निर्वहन नहीं कर रहे हैं.

–इन्द्रजीत कुमार, समस्तीपुर, बिहार.

कहानी

हमेशा अच्छा व्यवहार करना चहिए

एक बार किसी गांव से तीन भाई धन कमाने के लिए परदेश रवाना हुए. रास्ते में उन्हें उन्हीं की तरह यात्रा पर निकला किसान मिला, जिसके पास कुछ धन था. सभी भाइयों के मन में किसान को ठगने का विचार आया. उन्होंने उसे यात्रा में साथ ले लिया. रात को वे एक मंदिर में रुके तो तीनों भाइयों ने किसान को खाना लेने भेजा. जब वह खाना लेकर आया तो उसे किसी काम में उलझाकर अधिकांश खाना तीनों ने खा लिया. किसान बेचारा अधपेटा ही रह गया. वह आगे के लिए सावधान हो गया. अगले दिन जब किसान को उन्होंने लड्डू लाने के लिए भेजा तो किसान ने अपना हिस्सा पहले ही खा लिया. कम लड्डू देखकर तीनों ने कहा, तुमने हमारे बिना लड्डू कैसे खा लिए? किसान ने एक और लड्डू मुंह में उठाकर रखा और कहा, ऐसे. तीनों मन मार कर रह गए और बाद में किसान से बदला लेने का निश्चय किया. परदेश में धन कमाकर लौटने से पहले तीनों ने किसान से रात को खीर बनवाई और कहा, जिसे सबसे अच्छा सपना आएगा, वही इस खीर को सुबह खाएगा. चतुर किसान ने उनके सोने के बाद सारी खीर खा ली. सुबह तीनों भाइयों ने सपने सुनाने शुरू किए. एक ने कहा, मैंने जयपुर नरेश को सपने में मेरा सत्कार करते देखा. दूसरा बोला, मैं ओरछा दरबार में राजा के साथ नर्तकियों का नृत्य देख रहा था.

तीसरे ने कहा, मैं तो सपने में मक्का पहुंच गया. इसके बाद किसान बोला, सपने में मुझे एक बलिष्ठ आदमी ने खूब मारा और सारी खीर खाने को बाध्य कर दिया. यह सुनते ही तीनों चिल्लाए, तूने हमें जगाया क्यों नहीं? हम तुझे बचा लेते. किसान बोला, कैसे जगाता? तुम तीनों तो तीन अलग शहरों में थे. जो दूसरों के बारे में बुरा सोचता है उसका भी बुरा होता है. इसलिए सदव्यहार पाने के लिए खुद भी सदाचरण करना चाहिए. ■

शिक्षा– दूसरों के लिए बुरा सोचने वाले का भी बुरा ही होता है.

पाठक पूरा नाम, पता व फोन नंबर के साथ अपने स्वतंत्र विचार व प्रतिक्रियाएं इस पते पर भेजें :
चौथी दुनिया, एफ.2, सेक्टर–11, नोएडा (उत्तर प्रदेश) पिन–201301

> हमारे संयुक्त पारिवारिक जीवन का महत्वपूर्ण अंग बना तेतर अपनी उपस्थिति और उपयोगिता से सभी को सराबोर रखता था. एक केस में गवाही न देने के लिए एक दबंग व्यक्ति द्वारा बार–बार धमकी देने के बावजूद तेतर ने कोर्ट में वह गवाही दी कि हमारा केस फतह हो गया. विरोधी पक्ष के बड़े वकील ने जिरह में यह साबित करने की बहुत कोशिश की कि तेतर हम लोगों का खासमखास आदमी है.

विवादित नहीं हुए पुरस्कार

अनंत विजय

एक अनुमान के मुताबिक, हिंदी में कहानी, कविता एवं उपन्यास आदि को मिलाकर तक़रीबन पचास छोटे–बड़े पुरस्कार दिए जाते हैं. इसके अलावा अनेक राज्य सरकारें भी थोक भाव से पुरस्कार बांटती हैं. इस साल भी हिंदी में काफी पुरस्कार दिए गए, लेकिन अपेक्षाकृत कम पुरस्कार विवादित हुए. साहित्य के क्षेत्र में सबसे बड़ा नोबेल पुरस्कार इस बार फ्रांस के लेखक पैट्रिक मोदियानो को दिया गया. भारत के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक ज्ञानपीठ पुरस्कार कवि केदारनाथ सिंह को दिया गया. हालांकि, यह 2013 का पुरस्कार था, लेकिन ऐलान 2014 में किया गया. केदारनाथ सिंह को पुरस्कार देने वाली छह सदस्यीय समिति के अध्यक्ष मशहूर ओडिया कवि सीताकांत महापात्र थे. इस साल का साहित्य अकादमी पुरस्कार भोपाल के लेखक रमेश चंद्र शाह को उनके उपन्यास–विनायक के लिए दिया गया. मशहूर शायर मुनव्वर राणा को उर्दू में लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, जबकि पंजाबी भाषा के जसविंदर को साहित्य अकादमी पुरस्कार देने का ऐलान किया गया. धन के लिहाज से समृद्ध श्रीलाल शुक्ल इफ्को सम्मान कथाकार मिथिलेश्वर को दिया गया.

इस बार का सरस्वती सम्मान बुजुर्ग लेखक गोविंद मिश्र को उनके उपन्यास–धूल पौधों पर के लिए दिया गया, जबकि प्रतिष्ठित मूर्ति देवी सम्मान मशहूर ओडिया लेखक हरप्रसाद दास को दिया गया. नवलेखन के लिए भारतीय ज्ञानपीठ का पुरस्कार योगिता यादव को उसकी कहानी–क्लीन चिट और कविता के लिए अरुणाभ सौरभ को दिया गया. इस बार साहित्य अकादमी का युवा पुरस्कार कुमार अनुपम के खाते में गया. लखनऊ से शैलेंद्र सागर कथाक्रम सम्मान देते हैं, जो इस बार वरिष्ठ लेखिका नासिरा शर्मा को समारोहपूर्वक दिया गया. कविता के लिए शमशेर सम्मान वरिष्ठ कवि ऋतुराज को, जबकि सृजनात्मक लेखन के लिए यह पुरस्कार सुधीर विद्यार्थी को दिया गया. कविता

के लिए ही प्रतिष्ठित भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार आस्तिक वाजपेयी को देने का फ़ैसला हुआ. महाकवि निराला के नाम पर स्थापित पहला निराला स्मृति सम्मान राजेश जोशी को दिया गया. मुंबई से दिया जाने वाला विजय वर्मा कथा सम्मान हिंदी अकादमी दिल्ली के सचिव हरिसुमन बिष्ट को उनकी कृति–बसेरा के लिए दिया गया, जबकि कविता के लिए हेमंत स्मृति कविता पुरस्कार नवोदित कवयित्री अर्चना राजहंस मधुकर को उनके काव्य संग्रह–भीगा हुआ सच के लिए देने का ऐलान किया गया. इन दोनों पुरस्कारों के निर्णायक वरिष्ठ आलोचक भारत भारद्वाज थे.

हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के लिए काम करने वाली संस्था कलमकार फाउंडेशन की अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता के विजेताओं को भी पुरस्कृत किया गया. 21 हज़ार रुपये का पहला पुरस्कार भोपाल की कथाकार इंदिरा दांगी को उनकी कहानी–शहर की सुबह के लिए दिया गया, जबकि 11 हज़ार रुपये के दो पुरस्कार जम्मू की लेखिका योगिता यादव और लखनऊ की कथाकार रजनी गुप्त को दिया गया. इसके अलावा कमल, प्रदीप जिलवाने और सुषमा मुनींद्र को तृतीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया. इस साल का रमाकांत स्मृति सम्मान और वागेश्वरी सम्मान भी इंदिरा दांगी को ही दिया गया. इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार ने भी कई साहित्यकारों को सम्मानित और पुरस्कृत किया, जिनमें उपन्यासकार ममता कालिया, विभूति नारायण राय, रजनी गुप्त, सूर्यनाथ सिंह के अलावा तक़रीबन दो दर्जन साहित्यकार एवं लेखक शामिल हैं. ■

> हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के लिए काम करने वाली संस्था कलमकार फाउंडेशन की अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता के विजेताओं को भी पुरस्कृत किया गया. 21 हज़ार रुपये का पहला पुरस्कार भोपाल की कथाकार इंदिरा दांगी को उनकी कहानी–शहर की सुबह के लिए दिया गया, जबकि 11 हज़ार रुपये के दो पुरस्कार जम्मू की लेखिका योगिता यादव और लखनऊ की कथाकार रजनी गुप्त को दिया गया. इसके अलावा कमल, प्रदीप जिलवाने और सुषमा मुनींद्र को तृतीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया.

(लेखक IBN7 से जुड़े हैं)
anant.ibn@gmail.com

कहानी

तेतर दास

प्रभाष चंद्र तिवारी

तेतर दास को मैं बचपन से ही देख रहा था. कभी नदी के किनारे की गाछी (बाग) में आम तोड़ते हुए, तो कभी बारह बजिया ट्रेन से किसी मुसाफिर का सामान लेकर पैदल कोसों कोस जाते हुए. उन दिनों बहुत गांव ऐसे थे, जहां कोई सवारी नहीं जा पाती थी. देखने में दुबला–पतला, कृशकाय, रंग पक्का, मझोला कद, पर ताकत इतनी कि ढाई मन चावल का बोरा पीठ पर लादकर खुदरा बिक्री के लिए बाज़ार से पैदल बिना कहीं रखे–रुके पेठिया पहुंचा दे.

गोरखपुर वाली मइया के दस कठवा खेत का बंटईदार था वह. घर के पीछे कभी अलुआ उखाड़ते, तो कभी तंबाकू का बिचड़ा रोपते, कभी सरसों की निकौनी करते, तो कभी भीषण गर्मी में कोवारी (कुदाल) से रहड़ी (अरहर) तामते (कोड़ते) हुए अक्सर देखा करता था उसे. तेतर जाति का ततमा था. कहते हैं कि उसके पूर्वज तांत से कपड़ों की बुनाई करते थे, लेकिन अंग्रेजों के मशीनी कपड़ों से वे मुकाबला नहीं कर पाए और खेती–बाड़ी में आ गए. ठीक अस्पताल के बगल में हाईस्कूल मैदान के सामने सड़क पर पटोरी जैसे शांत कस्बे में उन सबकी मड़ैया (झोंपड़ियां) थीं. 8–10 घर ततमा, 3–4 घर दुसाध, 2–3 घर तेली हम लोगों की ज़मीन में बसाए गए असामी कहे जाते थे. तीन बहनों के बाद जन्म लेने के कारण उसका नामकरण तेतर कर दिया गया था. उन दिनों बच्चे को मरने से बचाने के लिए अजीब–अजीब नाम रख दिए जाते थे–फेकन, गोबरा आदि.

तेतर का व्यक्तित्व बहुआयामी था. गांव में जीने के लिए सारे स्थानीय कौशलों से सुसज्जित तेतर टाटी बनाने, खपरैल छाने, लकड़ी चीरने, फसल काटने जैसे सभी कामों में समान रूप से निपुण था. वह चंद्रभवन के अमरूद, आम, फालसा, बेर, केला इत्यादि सारे अतिरिक्त फलों को सस्ते में खरीद कर बगल के पेठिया में बेचा भी करता था, जिसमें उसकी मां तेतरा माय उसका सहयोग करती थी, लेकिन उसने अपनी पत्नी को कभी दुकानदार नहीं बनाया. कारण जो भी हो. मौक़ा मिलने पर कभी–कभी हम लोगों के बेल या केले के घौद पर भी हाथ साफ़ कर लिया करता था. लोग जानकर भी अनजान थे.

एक रात आम के मौसम में प्रहलाद भइया ने छत से किसी को पेड़ से अंधेरे में आम तोड़ते देखा. दबे पांव चुपके से पेड़ के नीचे पहुंच कर ऊपर टॉर्च मारी, तो तेतर दास. अब तो तेतर की हालत पतली. बहुत कहने पर 2–4 डाल नीचे उतरा, फिर मारी छलांग और ले लत्ता–चल कलकत्ता. भइया फुटबॉलर थे, लेकिन उसकी रफ्तार! सेकंड में अंधेरे में विलीन हो गया. एक हफ्ते बाद नमूदार हुआ. पूरा बदन कटा–छिला. भागने के क्रम में वह आगे राधे खटोड़ के कंटीले तारों का शिकार हो गया था. फिर अपनी तीसरी बीवी के मायके धमौन पहुंच कर उसने इलाज कराया, हिम्मत जुटाई और वापस यहां ड्यूटी में लग गया. हमारे यहां छोटी–मोटी चोरी को तेतर अपना जन्मसिद्ध अधिकार ही समझता था. किशोरावस्था में हम 3–4 मित्रों, प्रहलाद भइया और फेकन ने नदी किनारे उसके साथ मित्र भाव से उठा–पटक करने की कोशिश की थी, लेकिन तेतर हम सब पर भारी पड़ गया था.

तेतर हाईस्कूल मैदान के किनारे रहने के कारण फुटबॉल भी खेलता था. खेलते समय सिर ज़मीन में गाड़कर खेलने के कारण लोगों ने उसका उपनाम भुईंतक्का बैक (ज़मीन को देखने वाला खिलाड़ी जो बैक की पोजीशन पर खेलता हो) भी रख दिया था. उसके जैसे खाली पांव के ज़्यादातर खिलाड़ी रेलवे लाइन पर इंजन द्वारा त्यागे कोयले भी चुनते थे, इसलिए उनकी टीम का नाम था, कोयला टीम. शाहपुर पटोरी भाप इंजन के लिए वाटरिंग स्टेशन था.

> एक रात आम के मौसम में प्रहलाद भइया ने छत से किसी को पेड़ से अंधेरे में आम तोड़ते देखा. दबे पांव चुपके से पेड़ के नीचे पहुंच कर ऊपर टॉर्च मारी, तो तेतर दास. अब तो तेतर की हालत पतली. बहुत कहने पर 2–4 डाल नीचे उतरा, फिर मारी छलांग और ले लत्ता–चल कलकत्ता. भइया फुटबॉलर थे, लेकिन उसकी रफ्तार! सेकंड में अंधेरे में विलीन हो गया. एक हफ्ते बाद नमूदार हुआ. पूरा बदन कटा–छिला. भागने के क्रम में वह आगे राधे खटोड़ के कंटीले तारों का शिकार हो गया था. फिर अपनी तीसरी बीवी के मायके धमौन पहुंच कर उसने इलाज कराया, हिम्मत जुटाई और वापस यहां ड्यूटी में लग गया.

हर ट्रेन 10–15 मिनट तो रुकती ही थी. एक बार गरइड़ा रेलवे की फुटबॉल टीम उधर से गुज़र रही थी. स्टेशन से बाहर खिलाड़ीगण चाय पीने आ गए. दुकानदार नंदू सिंह भी खिलाड़ी ही थे. बातों–बातों में चैलेंजा–चैलेंजी हो गई और रेलवे टीम को शाम के मैच के लिए रोक लिया गया. उस दिन पटोरी की मुख्य टीम राइजिंग स्टार क्लब मुंगेर मैच खेलने गई थी. कहते हैं कि तेतर की कोयला टीम ने खाली पांव ही रेलवे की प्रतिष्ठित टीम को ड्रॉ पर रोक दिया और लोगों ने तेतर को गोद में उठाकर पैसों से उसकी जेब और चॉकलेट से उसका मुंह भर दिया.

अशिक्षित होते हुए भी तेतर को कभी भी किसी से लड़ते झगड़ते नहीं देखा–सुना गया. शालीनता एवं मर्यादा तो उसके कण–कण में बसी थी. बात का इतना पक्का कि अगर उसने गछ लिया (वादा कर दिया), तो कुछ भी हो जाए, ट्रेन पकड़ाने के समय तेतर हाज़िर नाज़िर होता. पेठिया (हाट) के वसूले तरकारी (सब्ज़ी) के बोरे को पटना लक्ष्मी फुआ या बेबी दीदी के यहां पहुंचाने के लिए उसे ट्रेन, पहलेजा से महेंद्रू घाट तक पानी के जहाज और रिक्शा आदि का भाड़ा जोड़कर मिलता था, लेकिन तेतर पैसा बचाने के लिए देसरी स्टेशन उतर कर 10 मील गर्म बालू का दियारा पैदल लांघकर पाल वाली नाव पकड़ता था और पटना गाय घाट उतर जाता था. उसके तलवे ही उसकी चप्पल थे. सुबह से शाम तक विभिन्न कामों में व्यस्त तेतर को मैंने कभी–कभी ही अपनी मड़ैया के सामने चुक्कू–मुक्कू बैठे सुस्ताते पाया.

जाड़े के दिन थे. रात में खाना खाकर अक्सर हम कुटियारी में घूरे के इर्द–गिर्द ईंट लेकर जम जाते थे. खेलावन महतो के छोटे भाई हजारी महतो उन दिनों आसाम से पैसे कमाकर महीनों में लौटे थे. वह आसामी ढोलक पर ताल देकर मस्ती में भुइयां बाबा के गीत गा रहे थे और हम उन द्वारा प्रदत्त छलिया कसेली का रसास्वादन कर रहे थे. इसी बीच तेतर दास जी हाथ में लाठी लिए प्रकट हुए और अन्य दिनों की तरह बीती रात कैसे उनके मकई की रखवाली वाले मचान पर भूत चढ़ आया और उनके सीने पर सवार होकर कहानी सुनाने लगा बताने लगे. फिर आग तापकर तेतर दास जैसे ही पिछवाड़े वाले खेत की रखवाली के लिए बढ़े कि पूर्व नियोजित कार्यक्रमानुसार फेकन जोर जोर से चीखते–चिल्लाते बचाओ–बचाओ करता हुआ उसके मचान पर चढ़ आया. मैं भी अजीब–सी भुतहा आवाज़ निकालता हुआ उसके पीछे खेत में घुस गया और छिपकर मकई के पौधे को कभी यहां, तो कभी वहां हिलाने लगा. तेतर बहादुर फेकन से चिपट कर डर के मारे कांपने लगे. फिर फेकन मचान से कूदकर अपने घर की ओर भागा और मैं भी उसे खदेड़ता हुआ वापस आ गया. दूसरे दिन हल्ला हो गया कि मकई के खेत में कल रात ब्रह्म पिशाच आया था, जो फुलवारी के करौंदा पर रहता है. आज भी उस करौंदे के पास कोई नहीं फटकता, क्योंकि पिशाच उसकी चौकीदारी करता है.

हमारे संयुक्त पारिवारिक जीवन का महत्वपूर्ण अंग बना तेतर अपनी उपस्थिति और उपयोगिता से सभी को सराबोर रखता था. एक केस में गवाही न देने के लिए एक दबंग व्यक्ति द्वारा बार–बार धमकी देने के बावजूद तेतर ने कोर्ट में वह गवाही दी कि हमारा केस फतह हो गया. विरोधी पक्ष के बड़े वकील ने जिरह में यह साबित करने की बहुत कोशिश की कि तेतर हम लोगों का खासमखास आदमी है, लेकिन सब व्यर्थ. छोटकी मामा के साथ तेतर चारों धाम यात्रा और कई वर्ष प्रयाग संगम की रेत पर एक–एक महीने का कल्पवास भी कर चुका था. तीन वर्ष पहले अपने घर पटोरी गया, तो सूचना मिली कि जोखन बाउजी के कुत्ते को शाम के समय घुमाने के क्रम में अचानक झटके से तेतर गिर पड़ा और उसकी हड्डी टूट गई. उसका तुरंत उपचार कराया गया और अभी वह घर पर है. मैं पहली बार उसकी मड़ैया में घुसा. उसकी आंखों में आंसू थे. वह काफी भावुक हो गया था. मैंने उसे सांत्वना दी. स्थानीय डॉक्टर को वहां कॉल पर बुलाया गया और दवा बढ़ाई गई, लेकिन तेतर फिर बिस्तर से उठ नहीं सका. एक लड़के को उसकी तीमारदारी का ज़िम्मा देकर मुझे वापस दिल्ली आना पड़ा.

तेतर ने एक दिन लड़के से पूछा कि बउआ जी हैं न? उसने सच बता दिया कि वह दिल्ली गए. उसी दिन तेतर ने प्राण त्याग दिए. वैसे तो दुनिया का हर व्यक्ति अनोखा है, लेकिन तेतर हमारे जीवन में सदा ही प्राणवंत रहेगा. ईश्वर उसकी आत्मा को चिर शांति दे और हमें उसकी कर्मठता, कर्तव्यपरायणता एवं समर्पण से प्रेरित करे. ■

feedback@chauthiduniya.com

कविता

अटल जी मेरी दृष्टि में

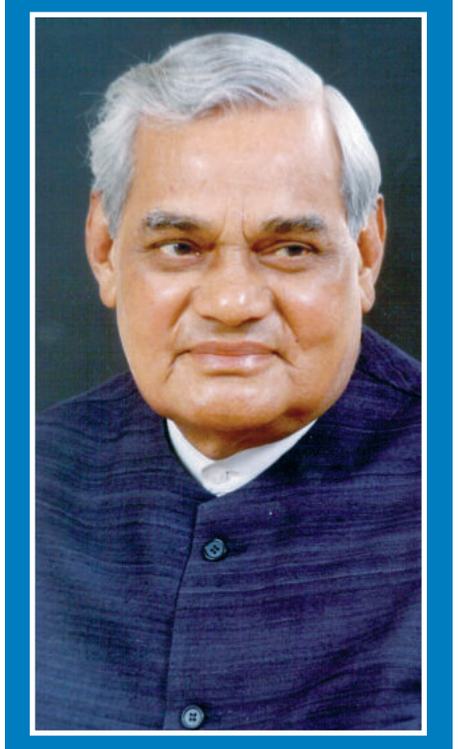

मैंने तुमको ऐसे पाया
हिमगिरि के उत्तुंग शिखर–सा,
सागर की गहराई जैसा,
उषा किरण की लाली जैसी,
गोधूली के स्पंदन जैसा.
मैंने तुमको ऐसे पाया
बचपन है केसर, पराग–सा,
विद्यार्थी विप्लव विनीत–सा,
आंचल ग्रंथि जनहित की दुल्हन,
जीवन सार अमिय पीयूष–सा.
मैंने तुमको ऐसे पाया
जीभ सुधा बरसाने वाली,
परनिंदा कवि कोविद कल्लोल कलामय,
शब्द–शब्द किसलय–किसलय है,
सागर मंथन के अमृत–सा.
मैंने तुमको ऐसे पाया
है नहीं आसान इतना,
इंद्रधनुषी सरकार चलाना,
हर–पल रूठे, हर–पल मनाना,
आंख मिचौली गोकुल जैसा.
मैंने तुमको ऐसे पाया.

(यह कविता आज से बीस वर्ष पूर्व लिखी गई थी.)

एलडी तिवारी ललित

> जियोमी का यह फोन केवल सस्ता ही नहीं है बल्कि इसका प्रोसेसर भी दमदार है. इसकी स्क्रीन 4.7 इंच की है. यह फोन 1.2 गीगाहर्ट्ज क्वॉडकोर क्वॉलकॉम स्नैपड्रैगन 64 बिट प्रोसेसर से लैस है. इस फोन में 1 जीबी रैम है और यह फोन एंड्रॉयड 4.4 किटकैट पर आधारित है. इसकी इंटरनल मेमोरी 8 जीबी की है.

महिलाओं की सुरक्षा करेगा हिम्मत

श्याम सुंदर प्रसाद

देश की राजधानी दिल्ली में 16 दिसंबर, 2012 में हुये निर्भया रेप कांड और 5 दिसंबर 2014 को दिल्ली के इंद्रलोक इलाके में एक महिला कंपनी एग्जीक्यूटिव के साथ कैब ड्राइवर द्वारा रेप करने की घटना ने पूरे देश को दहला कर रख दिया. रेप की कुछ ही घटनायें ही मीडिया की सुर्खियां बन पाती हैं और लोगों के सामने आ पाती हैं, लेकिन ऐसा कोई दिन नहीं गुजरता है, जब किसी महिला के साथ रेप होने की खबर न आए. इस मामले में सरकार और पुलिस की मदद के बिना खुद को रेप जैसी घटनाओं से बचाने के लिए एहतियाती कदम उठाने जरूरी हैं. अगर इसमें तकनीक की मदद ली जाती है, तो ये कदम कारगर साबित हो सकते हैं. इस बात को ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस ने महिलाओं को नये साल साल के तोहफे के रूप में एक सौगात दी है. दिल्ली पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए हिम्मत नाम का एक मोबाइल ऐप्प लॉन्च किया है. देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने 01 जनवरी 2015 को दिल्ली के विज्ञान भवन में दिल्ली पुलिस के इस एप्प को लॉन्च किया. इस मौके पर दिल्ली पुलिस कमिश्नर बीएस बस्सी ने कहा कि यह ऐप्प महिलाओं की सुरक्षा के लिए बना सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त ऐप्प है.

दिल्ली पुलिस के अनुसार हिम्मत एप्लीकेशन की खासियत इसकी तेजी है. इसके जरिए शिकायतकर्ता और पुलिस कंट्रोल रूम चंद सेकंड में एक–दूसरे से जुड़ जायेंगे. फिर लोकेशन ट्रैक करके पुलिस अलर्ट हो जाएगी, मोबाइल यूजर्स इससे 30 सेकंड में ऑडियो–वीडियों रिकॉर्डिंग भी कर सकेंगे.

कैसे करें इस ऐप्प का इस्तेमाल

नए यूजर को इसके लिए सबसे पहले दिल्ली पुलिस की वेबसाइट http://www.delhipolice.nic.in/ पर खुद को रजिस्टर करना होगा इसके लिए उसे अपना, पता, फोन नंबर और अपने कम से कम दो और अधिकतम पांच दोस्तों या रिश्तेदारों के नाम व मोबाइल नंबर देने होंगे. रजिस्ट्रेशन पूरा होने पर यूजर को रजिस्ट्रेशन के दौरान दिए गए मोबाइल नंबर पर एसएमएस आएगा इसमें ऐप्प का डाउनलोड लिंक और यूनिक रजिस्ट्रेशन कोड होगा फिर आप गूगल प्ले स्टोर से या दिल्ली पुलिस की वेबसाइट http://www.delhipolice.nic.in/ से हिम्मत नाम के ऐप्प को डाउनलोड कर सकते हैं. इसके बाद उसे अपने एंड्रॉयड मोबाइल फोन में इनस्टॉल करें और मोबाइल पर आए यूनिक कोड का इस्तेमाल यूजर ऐप्प के रजिस्ट्रेशन विंडो में करें यह प्रक्रिया बस एक बार करनी होती है.

इमरजेंसी के दौरान इस ऐप्प के जरिए शिकायतकर्ता पुलिस कंट्रोल रूम से कुछ ही सेकेंड में जुड़ जाएगा. इस ऐप्प को कई प्रकार से प्रयोग में लाया जा सकता है, पहले आपको इसमें दिए गए एसओएस (sos) आइकॉन पर क्लिक करना होगा. दूसरा आप अपने स्मार्टफोन को जोर से हिलाकर (शेक) या तीसरा अपने फोन के पावर बटन को पांच से छह बार तक दबाना (प्रेस करना) होगा. इसके बाद यह ऐप्प अपना काम खुद करेगा. आपके ऐसा करते ही एप्प पुलिस कंट्रोल रूम पोर्टल, पुलिस कंट्रोल रूम एसएमएस नंबर, आपकी उपस्थिति वाले क्षेत्र के सबसे नजदीकी पुलिस स्टेशन के एसएचओ(लोकल स्टेशन हाउस ऑफिस)के मोबाइल पर और आपके द्वारा रजिस्ट्रेशन के समय दर्ज किए गए रजिस्टर्ड दोस्तों, रिश्तेदारों के नंबर पर अपने आप एसएमएस चला जाएगा. एसएमएस मिलते ही दिल्ली पुलिस लोकेशन ट्रैक करके अलर्ट हो जाएगी. साइबर हाइवे के जरिए स्थानीय पीसीआर वैन और थाने को अलर्ट करेगा और शिकायतकर्ता को वापस कॉल बैक कर उसके लोकेशन तक पहुंचने की कोशिश करेगा. इस तरह से न केवल पुलिस, बल्कि पीड़ित (मोबाइल यूजर) के सगे–संबंधी भी उसकी सहायता के लिए घटना स्थल पर पहुंच सकते हैं.

इस ऐप्प में एक बटन दिया गया है जिससे आप इमरजेंसी के दौरान या छेड़छाड़ के दौरान तुरंत 30 सेकंड का वीडियो एवं ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, ऐप्प अपने आप रिकॉर्ड वीडियो को पुलिस कंट्रोल रूम को भेज देगा इस दौरान की गई रिकॉर्डिंग अहम सबूत साबित हो सकती है. इस ऐप्प में कुछ खास सुविधाएं हैं जिससे आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं. अगर इसे आप अपने फेसबुक और टिवट्र अकाउंट से कनेक्ट करते हैं तो इमरजेंसी बटन के दबाते ही आपके वाल पर एक मैसेज अपने आप पोस्ट हो जाएगा जिससे आपके नजदीकी लोग तत्काल आपकी मदद कर सकते हैं. मोबाइल ऐप्प में हेल्प सेक्शन दिया गया है. इसमें बताया गया है कि ऐप्प के हर सेक्शन का इस्तेमाल किस तरह करना है और इमरजेंसी के दौरान क्या–क्या करना चाहिए. सभी के द्वारा इसे जरूर पढ़ा जाना चाहिए.

इस एप्प का दुरुपयोग न हो उसके लिए भी कुछ प्रावधान किए गए हैं. तीन फर्जी एसओएस (SOS) अलर्ट या अलार्म भेजने पर यह रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा. अगर रजिस्ट्रेशन कैंसल हो जाए तो फिर से इसको एक्टिव करने के लिए आपको 011–23490378 पर कॉल या ई–मेल के द्वारा कारण बता कर इसे फिर से एक्टिव कराया जा सकता है. दिल्ली पुलिस ने लोगों से आग्रह किया है कि इसका दुरुपयोग न करें, क्योंकि हर अलर्ट को गंभीर रूप से लिया जायेगा और इस पर तुरंत कार्रवाई की जायेगी, इस ऐप्प का प्रयोग आप इमरजेंसी के दौरान ही करें सरकार ने छेड़छाड़ और किसी अन्य परेशानियों से निपटने के लिए 1064 हेल्प लाइन नंबर और 9910641064 नंबर पर वाट्स ऐप्प की भी सुविधा शुरू की है जिसपे आप अपनी शिकायत का ऑडियो या वीडियो भेज सकते हैं

कुछ त्रुटि भी हैं

ऐप्प अभी केवल एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए ही उपलब्ध है ये सुविधा किसी दूसरे मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए उपलब्ध नहीं है, लेकिन सरकार ने कहा है कि इसकी सुविधा आईओएस और अन्य ऑपरेटिंग सिस्टम पर जल्द ही उपलब्ध होगी. इस ऐप्प का इस्तेमाल तभी किया जा सकता है जब आपकी मोबाइल का डाटा पैक (इंटरनेट) ऑन हो बिना इसके ये ऐप्प काम नहीं करेगा. अगर आपका मोबाइल आउट ऑफ कवरेज एरिया (नेटवर्क में नहीं) है तो यह ऐप्प काम नहीं करेगा. यह ऐप्प का दिल्ली के बाहर इस्तेमाल करने पर काम नहीं करेगा. हेल्पलाइन नंबर का महिलाओं के द्वारा इस्तेमाल दिल्ली पुलिस के अनुसार वर्ष 2014 में 11000 महिलाओं ने हेल्पलाइन नंबर 100 की सुविधा का इस्तेमाल किया. वहीं 49710 महिलाओं ने एंटी स्टोकिंग के लिए बने हेल्पलाइन नंबर 1096 का इस्तेमाल किया और 1410 महिलाओं ने 1091 महिला हेल्प लाइन नंबर का इस्तेमाल किया. पहले से बने कुछ मिलते जुलते सिक्योरिटी ऐंड्रॉयड, आईओएस, विंडोज और ब्लैकबेरी ऐप्प जिसका आप केवल दिल्ली मे नहीं बल्कि पूरे देश में इस्तेमाल कर सकते हैं.

दिल्ली के बाहर इस्तेमाल किए जा सकने वाले एप्प

Damini, Circle of 6, bSafe, Scream alarm, Safeti Pin, Smart Shehar Woman Safety Shield Protection, Vith U: V Gumrah Initiative, Suspects Registry - FOR WOMEN, Pukar Personal Safety app, Women Safety Help Totem SOS, Raksha–Women Safety alert, i-Go Safely- Personal Safety app, Smart 24x7-Personal Safety app, Women Safety Secured, Women's Safety app ये पहले से बने कुछ ऐसे ही मिलते–जुलते एंड्रॉइड ऐप्प हैं जो हिम्मत की तरह ही काम करते हैं इनका इस्तेमाल करने पर 100 नंबर पर कॉल, एसएमएस या ईमेल चला जाता है. इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो कि सभी मोबाइल आपरेटिंग सिस्टम जैसे कि एंड्रॉयड, आईओएस, विंडोज और ब्लैकबेरी को भी सपोर्ट करते हैं. ■

feedback@chauthiduniya.com

जियोमी का सस्ता 4जी स्मार्टफोन लॉन्च

जियोमी ने 4जी स्मार्टफोन रेडमी2 लॉन्च किया है. जियोमी का यह फोन केवल सस्ता ही नहीं है बल्कि इसका प्रोसेसर भी दमदार है. इसकी स्क्रीन 4.7 इंच की है. यह फोन 1.2 गीगाहर्ट्ज क्वॉडकोर क्वॉलकॉम स्नैपड्रैगन 64 बिट प्रोसेसर से लैस है. इस फोन में 1 जीबी रैम है और यह फोन एंड्रॉयड 4.4 किटकैट पर आधारित है. इसकी इंटरनल मेमोरी 8 जीबी की है. इसमें लेड फ्लैश के साथ 8मेगापिक्सल का रियर कैमरा और 2 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है. इसमें 2200 एमएएच की बैटरी है. इसकी कीमत 7,120 रुपये है. ■

चीयर्स ने लॉन्च किया स्मार्टफोन सी–21

चीनी कंपनी चीयर्स ने बिल्ट–इन–ऐप्स के साथ स्मार्टफोन सी–21 बाजार में उतारा है. इसकी कीमत मात्र 1,999 रुपये है. सी–21 देश के सभी बड़े रीटेल स्टोर्स पर उपलब्ध है. कंपनी इस फोन को उन को लोगों को ध्यान में रखर बनाया सस्ते बजट स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं. यह एक ड्यूल स्मार्टफोन है. स्मार्टफोन सी–21 आइस क्रीम सैंडविच 4.0 पर चलता है. इसमें 2 एमपी का रियर कैमरा है और 1.3 एमपी का फ्रंट कैमरा है. मेमोरी 256 एमबी की है और इसे एसडी कार्ड के जरिए 32 जीबी तक बढ़ाया जा सकता है. इस फोन की बैटरी 1400 एमएएच की है, जो 8 घंटे का टॉकटाइम प्रदान करती है. यह फोन गुलाबी, काले, सफेद और नीले रंग में उपलब्ध है. ■

32 लाख रुपये की कावासाकी की बाइक

जापानी ऑटो कंपनी कावासाकी ने स्ट्रीट–लीगल वर्जन सुपरबाइक निंजा एच2 पेश किया है. इसक बाइक कि बुकिंग शुरू हो चुकी है, 10 लाख रुपये में निंजा एच2 की बुकिंग की जा रही है. इस बाइक का लुक निंजा एच2आर से मिलता–जुलता है. निंजा एच2 सुपरचार्जड 998सीसी, लिक्वड कूल्ड, इनलाइन–4 इंजन के साथ दौड़ती है. यह 197एचपी का पावर देने में सक्षम है. कावासाकी निंजा एच2 में एडवांस टेक्नोलॉजी जैसे लॉन्च कंट्रोल, ट्रेक्शनन कंट्रोल, इंजन ब्रेक कंट्रोल, एंटी–लॉक ब्रेक्स और इलेक्ट्रॉनिक स्ट्येरिंग डंपर का इस्तेमाल किया गया है. कावासाकी निंजा एच2 का वजन 239 किग्रा है जो बाजार में अन्य सुपरस्पोर्ट बाइक के मुकाबले थोड़ा अधिक है. इसकी कीमत 32 लाख रुपये है. ■

इस बाइक का लुक निंजा एच2आर से मिलता–जुलता है. निंजा एच2 सुपरचार्जड 998सीसी, लिक्वड कूल्ड, इनलाइन–4 इंजन के साथ दौड़ती है. यह 197एचपी का पावर देने में सक्षम है.

दुनिया का सबसे हल्का लैपटॉप

लेनोवो ने अल्ट्रा पोर्टेबल LaVie HZ550 लैपटॉप लॉन्च किया है. यह लैपटॉप थिंकपैट योगा सीरिज की तरह यह फ्लिप स्क्रीन लैपटॉप 360 डिग्री तक घूम सकता है.

कंपनी के अनुसार इसका वजन 0.78 किलो है. इसकी स्क्रीन 13.3 इंच की है, जो 2560 गुणा 1440 मेगा पिक्सल रेजोल्यूशन देती है. इसकी बॉडी 16 एमएम पतली है और इसमें इंटेल फिफ्थ जनरेशन का कोर आई5 प्रोसेसर लगा हुआ है. बेसिक मॉडल एचजेड500 में टच स्क्रीन की सुविधा नहीं है, लेकिन कंपनी ने एक कनवर्टिबल मॉडल एचजेड 750 भी पेश किया है. कंपनी के अनुसार इस लैपटॉप की बैटरी 5.9 घंटों का टॉकटाइम देती है और कनवर्टिबल मोड पर ये 9 घंटों का टॉकटाइम देती है. ■

कंपनी के अनुसार इसका वजन 0.78 किलो है. इसकी स्क्रीन 13.3 इंच की है, जो 2560 गुणा 1440 मेगा पिक्सल रोजोल्यूशन देती है.

विज्ञापन हेतु संपर्क करें : email : advt@chauthiduniya.com

आईसीसी विश्वकप-2015 कार्यक्रम

ग्रुप ए

- न्यूजीलैंड
- ऑस्ट्रेलिया
- श्रीलंका
- अफगानिस्तान
- इंग्लैंड
- स्कॉटलैंड
- बांग्लादेश

ग्रुप बी

- द. अफ्रीका
- जिंबाब्वे
- भारत
- पाकिस्तान
- वेस्टइंडीज
- आयरलैंड
- यूएई

क्रमांक	दिनांक	ग्रुप	मैच	वेन्यू	भारतीय समय	परिणाम	अंक
1	14 फरवरी	ए	न्यूजीलैंड बनाम श्रीलंका	क्राइस्टचर्च	03:30 सुबह		
2	14 फरवरी	ए	ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड	मेलबर्न	09:00 सुबह		
3	15 फरवरी	बी	द. अफ्रीका बनाम जिंबाब्वे	हैमिलटन	06:30 सुबह		
4	15 फरवरी	बी	भारत बनाम पाकिस्तान	एडिलेड	09:00 सुबह		
5	16 फरवरी	बी	आयरलैंड बनाम वेस्टइंडीज	नेल्सन	03:30 सुबह		
6	17 फरवरी	ए	न्यूजीलैंड बनाम स्कॉटलैंड	ड्यूनडिन	03:30 सुबह		
7	18 फरवरी	ए	अफगानिस्तान बनाम बांग्लादेश	कैनबरा	09:00 सुबह		
8	19 फरवरी	बी	यूएई बनाम जिंबाब्वे	नेल्सन	03:30 सुबह		
9	20 फरवरी	ए	न्यूजीलैंड बनाम इंग्लैंड	वेलिंग्टन	06:30 सुबह		
10	21 फरवरी	बी	पाकिस्तान बनाम वेस्टइंडीज	क्राइस्टचर्च	03:30 सुबह		
11	21 फरवरी	ए	ऑस्ट्रेलिया बनाम बांग्लादेश	ब्रिस्बेन	09:00 सुबह		
12	22 फरवरी	ए	अफगानिस्तान बनाम श्रीलंका	ड्यूनडिन	03:30 सुबह		
13	22 फरवरी	बी	भारत बनाम द. अफ्रीका	मेलबर्न	09:00 सुबह		
14	23 फरवरी	ए	इंग्लैंड बनाम स्कॉटलैंड	क्राइस्टचर्च	03:30 सुबह		
15	24 फरवरी	बी	वेस्टइंडीज बनाम जिंबाब्वे	कैनबरा	09:00 सुबह		
16	25 फरवरी	बी	आयरलैंड बनाम यूएई	ब्रिस्बेन	09:00 सुबह		
17	26 फरवरी	ए	अफगानिस्तान बनाम स्कॉटलैंड	ड्यूनडिन	03:30 सुबह		
18	26 फरवरी	ए	बांग्लादेश बनाम श्रीलंका	मेलबर्न	09:00 सुबह		
19	27 फरवरी	बी	द. अफ्रीका बनाम वेस्टइंडीज	सिडनी	09:00 सुबह		
20	28 फरवरी	ए	न्यूजीलैंड बनाम ऑस्ट्रेलिया	ऑक्लैंड	06:30 सुबह		
21	28 फरवरी	बी	भारत बनाम यूएई	पर्थ	12:00 दोपहर		
22	01 मार्च	ए	इंग्लैंड बनाम श्रीलंका	वेलिंग्टन	03:30 सुबह		
23	01 मार्च	बी	पाकिस्तान बनाम जिंबाब्वे	ब्रिस्बेन	09:00 सुबह		
24	03 मार्च	बी	आयरलैंड बनाम द. अफ्रीका	कैनबरा	09:00 सुबह		
25	04 मार्च	बी	पाकिस्तान बनाम यूएई	नेपियर	06:30 सुबह		
26	04 मार्च	ए	ऑस्ट्रेलिया बनाम अफगानिस्तान	पर्थ	12:00 दोपहर		
27	05 मार्च	ए	बांग्लादेश बनाम स्कॉटलैंड	नेल्सन	03:30 सुबह		
28	06 मार्च	बी	भारत बनाम वेस्टइंडीज	पर्थ	12:00 पर्थ		
29	07 मार्च	बी	पाकिस्तान बनाम द. अफ्रीका	ऑकलैंड	06:30 सुबह		
30	07 मार्च	बी	आयरलैंड बनाम जिंबाब्वे	होबार्ट	09:00 सुबह		
31	08 मार्च	ए	न्यूजीलैंड बनाम अफगानिस्तान	नेपियर	03:30 सुबह		
32	08 मार्च	ए	ऑस्ट्रेलिया बनाम श्रीलंका	सिडनी	09:00 सुबह		
33	09 मार्च	ए	इंग्लैंड बनाम बांग्लादेश	एडिलेड	09:00 सुबह		
34	10 मार्च	बी	भारत बनाम आयरलैंड	हैमिलटन	06:30 सुबह		
35	11 मार्च	ए	स्कॉटलैंड बनाम श्रीलंका	होबार्ट	09:00 सुबह		
36	12 मार्च	बी	द. अफ्रीका बनाम यूएई	वेलिंग्टन	06:30 सुबह		
37	13 मार्च	ए	न्यूजीलैंड बनाम बांग्लादेश	हैमिलटन	06:30 सुबह		
38	13 मार्च	ए	अफगानिस्तान बनाम इंग्लैंड	सिडनी	09:00 सुबह		
39	14 मार्च	बी	भारत बनाम जिंबाब्वे	ऑक्लैंड	06:30 सुबह		
40	14 मार्च	ए	ऑस्ट्रेलिया बनाम स्कॉटलैंड	होबार्ट	09:00 सुबह		
41	15 मार्च	बी	यूएई बनाम वेस्टइंडीज	नेपियर	03:30 सुबह		
42	15 मार्च	बी	आयरलैंड बनाम पाकिस्तान	एडिलेड	09:00 सुबह		

क्वार्टर फाइनल

18 मार्च	ग्रुप ए 1	ग्रुप बी 4	सिडनी	09:00 सुबह
	................बनाम			
19 मार्च	ग्रुप ए 2	ग्रुप बी 3	मेलबर्न	09:00 सुबह
	................बनाम			
20 मार्च	ग्रुप ए 3	ग्रुप बी 2	एडिलेड	09:00 सुबह
	................बनाम			
21 मार्च	ग्रुप ए 4	ग्रुप बी 1	वेलिंग्टन	06:30 सुबह
	................बनाम			

सेमी फाइनल

24 मार्च	ऑक्लैंड	06:30 सुबह
.... बनाम		
26 मार्च	सिडनी	06:30 सुबह
.... बनाम		

फाइनल

29 मार्च	मेलबर्न	09:00 सुबह
.................बनाम		

आमिर के साथ काम करना चाहती हैं जैकलीन

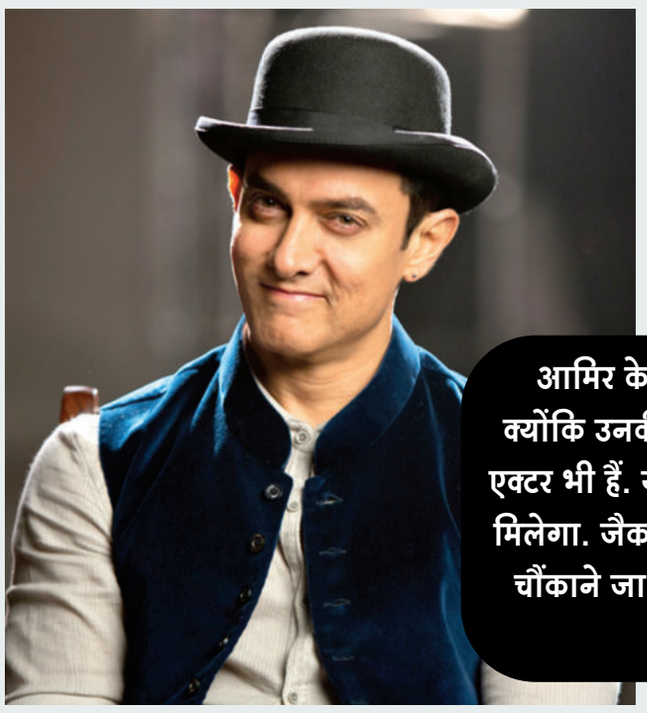

आमिर के साथ काम करना यकीनन हर किसी का अरमान होता है, क्योंकि उनकी फिल्मों का कंटेंट स्ट्रॉन्ग होता है. साथ ही वो एक बेहतरीन एक्टर भी हैं. यकीनन आमिर के साथ काम करके मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. जैकलीन अपनी आने वाली फिल्मों रॉय और ब्रदर्स से दर्शकों को चौंकाने जा रही हैं. उनका कहना है कि ये फिल्में उन्हें पिछली फिल्मों से अलग रूप में दर्शकों के सामने पेश करेंगी.

श्रीलंकाई बाला और बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज आमिर खान के साथ काम करना चाहती हैं. फिल्म किक में बॉलीवुड के मोस्ट एलिजिबल बैचलर सलमान खान से रोमांस करने के बाद अब जैकलीन ने मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान के साथ मूवी करने की इच्छा जताई है. जैकलीन अब तक बॉलीवुड के कई बेहतरीन अभिनेताओं के साथ काम कर चुकी हैं. अब जैकलीन का कहना है कि मैं ज्यादा से ज्यादा बेहतरीन एक्टर्स के साथ काम करना चाहती हूं, क्योंकि ऐसा करके ही मुझे बतौर एक्ट्रेस आगे बढ़ने में मदद मिलेगी.

आमिर के साथ काम करना यकीनन हर कलाकार का अरमान होता है, क्योंकि उनकी फिल्मों का कंटेंट स्ट्रॉन्ग होता है. साथ ही वो एक बेहतरीन एक्टर भी हैं. यकीनन आमिर के साथ काम करके मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा.

जैकलीन अपनी आने वाली फिल्मों रॉय और ब्रदर्स से दर्शकों को चौंकाने जा रही हैं. उनका कहना है कि ये फिल्में उन्हें पिछली फिल्मों से अलग रूप में दर्शकों के सामने पेश करेंगी. करण मल्होत्रा द्वारा निर्देशित फिल्म ब्रदर्स 2010 में प्रदर्शित हॉलीवुड फिल्म वॉरियर्स का रीमेक है. रॉय के बाद रिलीज होने वाली मेरी अगली फिल्म ब्रदर्स होगी और वह भी काफी मजेदार होगी क्योंकि ब्रदर्स में मैं बहुत ही अलग अवतार में नजर आऊंगी. रॉय में उनके साथ रणबीर कपूर और अर्जुन रामपाल हैं. जबकि ब्रदर्स में उन्हें बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार, सिद्धार्थ मलहोत्रा और जैकी श्रॉफ के साथ काम करने का मौका मिला है. जैकलीन ने कहा कि अगर आप सोचते हैं कि मेरे लिए रॉय बहुत अलग है तो ब्रदर्स भी एक ऐसी फिल्म है जिसकी मुझसे किसी ने उम्मीद नहीं की होगी. मैं दर्शकों की प्रतिक्रिया देखने के लिए उत्साहित हूं. ब्रदर्स 31 जुलाई को रिलीज होगी.■

विद्या ने बदन पर कपड़ों की जगह अखबार लपेटा

बॉलीवुड की डर्टी गर्ल विद्या बालन ने एक बार फिर बोल्डनेस की सारी हदें पार कर दी हैं और उन्होंने एक हॉट फोटोशूट करवाया है. डब्बू रत्नानी के कैलेंडर 2015 पर विद्या की जो फोटो दिखाई देगी, वह उनकी अब तक की सबसे हॉट फोटो होगी. दरअसल, विद्या ने कैलेंडर के लिए जो फोटोशूट कराया है वह उसमें काफी बोल्ड लुक में नज़र आ रही हैं. इस फोटोशूट के लिए उन्होंने कंपलीट मेकओवर किया है. फोटो में विद्या एक हाथ में न्यूजपेपर और दूसरे में कॉफी मग पकड़े हुए हैं. आमतौर पर एक्ट्रेसेस अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए बोल्ड फोटोशूट करवाती हैं, लेकिन विद्या की फिलहाल कोई फिल्म रिलीज नहीं हो रही है. ऐसे में डब्बू ने विद्या को फोटोशूट के लिए राजी किया. डब्बू ने बताया, कि जब मैंने शूट का कॉन्सेप्ट विद्या को बताया तो उन्होंने जवाब में तुम पर भरोसा है डब्बू कहा. विद्या पूरी तरह कॉन्फिडेंट थीं कि यह बहुत अच्छा होगा. इसके बाद बांद्रा के एक कैफे में यह शूट किया गया. कैलेंडर में विद्या के अलावा बिपाशा बसु,श्रद्धा कपूर,जैकलीन फर्नांडिस ,आलिया भट्ट और प्रियंका चोपड़ा भी नज़र आएंगी. ■

षमिताभ का ट्रेलर जारी हुआ

सुपर स्टार अमिताभ बच्चन की आने वाली फिल्म षमिताभ का ट्रेलर मुंबई के एक सिंगल स्क्रीन थिएटर में रिलीज़ किया गया. इस मौके पर फिल्म की पूरी टीम मौजूद थी. फिल्म में अमिताभ बच्चन के साथ दक्षिण भारत के स्टार धनुष मुख्य भूमिका में हैं. साथ ही कमल हसन की बेटी अक्षरा हसन इस फ़िल्म से बॉलीवुड में कदम रखने जा रही हैं. इस फिल्म का एक गीत अमिताभ ने भी गाया है. पिंडली गीत पहले ही सोशल नेटवर्किंग साईट्स पर रिलीज़ किया जा चुका है. यह गीत लोगों को पसंद भी आ रहा है. इसके लिए अमिताभ ने सभी का शुक्रिया अदा किया और कहा कि, दर्शकों की सकारात्मक प्रतिक्रिया पाकर काफी अच्छा लग रहा है, आर.बालकी ने मुझे बाथरूम सिंगर बना दिया है.

षमिताभ का निर्देशन आर बालकी ने किया है अमिताभ पहले भी इनके साथ चीनी कम और पा जैसी हिट फिल्मों में काम कर चुके हैं. अमिताभ को भरोसा है कि आर.बालकी ने इस बार भी कुछ अलग किस्म की फिल्म बनाई है. फिल्म के ट्रेलर के रिलीज के मौके पर फिल्म के दूसरे कलाकार भी काफी खुश नज़र आए. क्योंकि अक्षरा के लिए पहली ही फिल्म में अमिताभ बच्चन और आर. बालकी जैसी हस्तियों के साथ काम करना, एक सपने के पूरा होने जैसा है. वहीं धनुष के लिए ये बॉलीवुड में रांझणा के बाद किया गया एक और एक्सपेरिमेंट है. इस फिल्म में रोहित शेट्टी, करण जौहर, महेश भट्ट, अनुराग बासु, राकेश ओमप्रकाश मेहरा, राजकुमार हिरानी, गौरी शिंदे, जावेद अख्तर, बोनी कपूर और एकता कपूर जैसी दस हस्तियां मेहमान कलाकार के रूप में नज़र आएंगी. यह फिल्म 6 फरवरी को रिलीज होगी.■

ईशा बेबी में लगाएंगी आइटम का तड़का

ईशा गुप्ता पर एक आयटम नंबर बेपरवाह फिल्माया गया है. यह फिल्म पहले बिना किसी गाने के रिलीज होने वाली थी लेकिन रिलीज से कुछ ही दिन पहले इस गाने को फिल्म में प्रमोशन के लिए डाला गया है.

नवोदित अभिनेत्री ईशा गुप्ता फिल्म बेबी में आइटम नंबर करती नज़र आएंगी. अक्षय कुमार की फिल्म बेबी 23 जनवरी को प्रदर्शित होने जा रही है. ईशा गुप्ता पर एक आयटम नंबर बेपरवाह फिल्माया गया है. यह फिल्म पहले बिना किसी गाने के रिलीज होने वाली थी लेकिन रिलीज से कुछ ही दिन पहले इस गाने को फिल्म में प्रमोशन के लिए डाला गया है. मीत बद्रर्स के संगीत निर्देशन में अपेक्षा डाडेकर इस गाने को अपनी आवाज दी है. अभिश्री सेन ने कोरियोग्राफ की है. गौरतलब है कि सस्पेंस, थ्रिलर और एक्शन से भरपूर फिल्म बेबी में अक्षय कुमार, तापसी पन्नू, राना डुग्गाबत्ती, अनुपम खेर और डैनी ने काम किया है. फिल्म का निर्देशन ए वेडनेस-डे और स्पेशल 26 फेम नीरज पांडे ने किया है. ■

अंकिता और सुशांत बंधेंगे पवित्र रिश्ते में

टी वी शो पवित्र रिश्ता से एक्टिंग करियर की शुरूआत करने वाले सुशांत सिंह राजपूत अपनी प्रेमिका अंकिता लोखंडे के साथ विवाह बंधन में बंधने जा रहे हैं. दोनों के बीच पवित्र रिश्ता में काम करते वक्त करीबी बढ़ी थी. दोनों ने दुबई में न्यू ईयर एक-साथ सेलिब्रेट किया. उसी दौरान सुशांत ने अंकिता को शादी के लिए प्रपोज़ किया और अंकिता ने हां कर दी. दोनों जून या जुलाई के महीने में शादी कर सकते हैं. बताया जा रहा है कि सुशांत अपनी अगली तीन फिल्मों की शूटिंग से पहले शादी कर लेना चाहते हैं ताकि वह एमएस धोनी, पानी जैसी फिल्मों पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकें. गौरतलब है कि सुशांत शुद्ध देसी रोमांस, काई पो चे और पीके जैसी सफल फिल्मों में अभिनय कर चुके हैं.■

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

बिहार झारखंड

19 जनवरी–25 जनवरी 2015

Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2015-17, RNI No. DELHIN/2009/30467

मोदी ही बनेंगे भाजपा के मांझी

भाजपा के लिए फीलगुड व मोदी-शाह के ग्रह-गोचर के अत्यधिक मददगार होने के बावजूद बिहार उनके लिए कठिन प्रदेश है. ऐसा पटना से लेकर दिल्ली तक का पार्टी नेतृत्व भी मानता है, लेकिन बंद कमरे में. नीतीश कुमार और लालू प्रसाद की एकता-जनता परिवार के मिलन अभियान- को बिहार के संदर्भ में भाजपा नेतृत्व सार्वजनिक तौर पर भले मज़ाक में ले, पर अपने चुनावी गणित के हिसाब से वह इसे अनुकूल नहीं पाता है. यह सही है कि लालू-नीतीश मिलन से नीतीश कुमार का समर्थक सामाजिक आधार में छीजन हुआ है, पर यह भी सही है कि भाजपा-विरोधी मतों की गोलबंदी भी तगड़ी हुई है.

विधानसभा चुनावों में भाजपा को अधिकांश सीटों पर अपने विरोधियों से सीधी टक्कर का सामना करना पड़ेगा जो संसदीय चुनावों के विपरीत है. ऐसी स्थिति में कोई सौ सीटों पर भाजपा-व्यापक तौर पर एनडीए-को कांटे की लड़ाई लड़नी होगी. फिर, लालू-नीतीश की राजनीति में एक नया तत्व जुड़ गया हैः जीतनराम मांझी. अनेक अतिपिछड़े सामाजिक समूहों के साथ-साथ महादलित समाज के बड़े तबके के वह प्रिय राजनेता बनते जा रहे हैं. हालांकि मांझी दल या गठबंधन से अधिक खुद की राजनीति कर रहे हैं और अपना सिक्का जमाने में ज्यादा मनोयोग से लगे हैं.

सुकान्त

भारतीय जनता पार्टी की चुनावी रणनीति में बिहार में कोई बदलाव नहीं होने जा रहा है, पार्टी अपने पुराने हथियार के सहारे ही यहां सत्ता पर काबिज होने की तैयारी में है. राज्य के विधानसभा चुनावों में नरेन्द्र मोदी को ही मंझधार पार लगाने की पतवार बनाया जाएगा. हालांकि ऐसा पहले से ही माना जा रहा था, पर भाजपा की प्रादेशिक इकाई की दो दिवसीय बैठक के बाद यह बात स्फटिक की तरह साफ हो गई. बिहार में भी भाजपा के चुनाव पश्चात-नेता को लेकर फिलहाल कोई संकेत नहीं दिया जाएगा. यह भी संकेत नहीं मिल सकेगा कि मुख्यमंत्री पद का पार्टी का भावी दावेदार किस सामाजिक समूह का होगा. यह भी साफ हो गया है कि चुनाव-काल के प्रवासी नेताओं-दल बदल कर आनेवालों- को लेकर पार्टी ने अब तक कोई सकारात्मक राय नहीं बनाई है. प्रवासी नेताओं को टिकट देने में उदार नीति के झारखंड में विफल रहने से शायद ऐसा हुआ. विधानसभा चुनावों के संदर्भ में सहयोगी दलों-लोक जनशक्ति पार्टी और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी की भूमिका पर भी नज़र डाली गई. बैठक का अंत आते-आते पार्टी के बिहार प्रभारी व सांसद भूपेन्द्र यादव ने नारा दिया, जिसकी केन्द्र में सरकार उसकी प्रदेश में सरकार और चलो चलें मोदी के साथ, तभी होगा बिहार का विकास. उधर, प्रदेश भाजपा के सबसे कद्दावर नेता सुशील कुमार मोदी का नारा था जय-जय बिहार, भाजपा सरकार. बैठक का समापन सुशील कुमार मोदी के इस संदेश के साथ हुआ कि भाजपा नहीं बदली, पर नीतीश कुमार बदल गए और जंगलराज के पैरोकार लालू प्रसाद के साथ मिल गए.

इस बैठक में साफ तो कई बातें हुई और कई बातों पर गहरी चिंता व्यक्त की गई. साफ यह भी हुआ कि विधानसभा चुनावों के मद्देनज़र राज्य के अतिपिछड़े और दलित-महादलित सामाजिक समूह पार्टी के निशाने पर हैं. उन्हें पार्टी के दायरे में लाने को सबसे बड़ी राजनीतिक जरूरत माना जा रहा है. इस ख्याल से कई कार्यक्रमों को आरंभ किया जा रहा है और इनमें पार्टी के शिखर नेता-अमित शाह और नरेन्द्र मोदी क्रमशः- भाग लेंगे. गत संसदीय चुनावों में अतिपिछड़ों के कुछ समूहों में पार्टी ने सेंधमारी की थी. ऐसा माना गया कि इस सेंधमारी के पीछे मोदी की सामाजिक पृष्ठभूमि रही थी. पार्टी विगत कई वर्षों से अतिपिछड़ों में पैठ बनाने के लिए कर्पूरी ठाकुर की जयंती मना रही है, पर इस वर्ष इसे अभियान की तरह आयोजित किया जा रहा है. राज्य के विभिन्न जिलों में 11 से 22 जनवरी तक कर्पूरी जयंती के नाम पर सम्मेलन किया जाएगा, जिनमें मुख्यतः अतिपिछड़ों को ही गोलबंद किया जाना है. इसे अति महत्वपूर्ण बनाने

के ख्याल से समापन समारोह पटना में किया जाना है. इस आयोजन में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह मौजूद रहेंगे. इसी तरह, दलित-महादलितों को पार्टी के साथ गोलबंद करने के लिए विशेष अभियान शुरू किया जा रहा है. इस अभियान की शुरुआत चार फरवरी को रविदास जयंती के आयोजन के साथ होगी. इसका समापन 14 अप्रैल को आंबेडकर जयंती के दिन पटना में आयोजित होने वाली नरेन्द्र मोदी की रैली में होगा. वस्तुतः इस रैली के साथ ही बिहार में भाजपा के चुनावी अभियान की शुरुआत होगी. लेकिन अब भी यह अनुमान लगाने में पार्टी नेतृत्व खुद को सक्षम नहीं पा रहा है कि इनसे कितना लाभ होगा. बिहार में भाजपा की सामाजिक संरचना और इन समुदायों से प्रभावशील नेतृत्व का अभाव कई चुनौती पेश कर रहे हैं. प्रदेश कार्यसमिति की बैठक के दौरान भी किसी दलित-महादलित या अतिपिछड़े समुदाय के नेताओं की उल्लेखनीय भागीदारी का सवाल भाजपा को असहज कर देता है. भले, मंच पर इन समुदायों के सांसद-विधायक मौजूद रहे हों, पर पार्टी के भीतर ऐसा कोई नेता अब तक नहीं उभर सका जिसकी ताकत उसके विरोधियों के समानान्तर हो. यह सही है कि अतिपिछड़े और दलित समुदायों के कुछ समूहों का रुझान भाजपा की तरफ पिछले दिनों बढ़ा है, पर ऐसा भाजपा की रीति नीति से अधिक इसके विरोधियों से इन समूहों में बढ़ती नाराजगी के कारण हुआ है. यह स्थिति भाजपा के नेतृत्व को असहज कर देती है.

असहज तो सांगठनिक स्तर पर भी भाजपा हो रही है. सूबे में पार्टी के पचहत्तर लाख सदस्य बनाने के अभियान की स्थिति पर बैठक में परोक्षतः गहरी नाराजगी जाहिर की गई. यहां ऑनलाइन सदस्यता अभियान की प्रगति अच्छी नहीं रही है. हरियाणा जैसे छोटे राज्य में अब तक चौदह लाख सदस्य बनाए जा चुके हैं जबकि बिहार में बमुश्किल ग्यारह लाख लोगों को पार्टी से जोड़ा गया है. हालांकि प्रचार तो काफी हुआ, पर मोबाइल के जरिए भाजपा से लोगों को जोड़ने में अब तक कोई खास सफलता नहीं मिली है. इस फ्रंट पर संगठन को जिस तरह की मुस्तैदी दिखानी चाहिए, वैसा कुछ दिख नहीं रहा है. ऐसा क्यों हुआ? इस प्रश्न का उत्तर खोजने से पार्टी हर स्तर पर कतरा रही है- राष्ट्रीय स्तर पर भी. चुनाव की धमक काफी तेज हो गई है और ऐसे में पार्टी के भीतर गुटबाजी को नियंत्रित कर इसे रास्ते पर लाने की कोशिश कई जोखिमों को न्योता दे सकती है. पार्टी का नेतृत्व- मुख्यतः राष्ट्रीय नेतृत्व- ऐसा जोखिम मोल नहीं लेना चाहता है. वस्तुतः भाजपा के लिए हो या नहीं, नरेन्द्र मोदी और अमित शाह के लिए यह फीलगुड का दौर है. और नेतृत्व की सारी कोशिश इस दौर को बनाए रखने की है. ताज़ा हवा के तेज झोंके की तरह सब कुछ दिखाया और परोसा जा रहा है. चुनावी अभिय़ान को भी ऐसा ही माहौल बना कर रखना इस रणनीति की जरूरत है. पार्टी के भीतर वर्चस्व के खुले या छाया-युद्ध और बिहार के सामाजिक समूहों के द्वंद्व भी नेतृत्व को किसी जोखिम भरे कदम से रोकते हैं.

भाजपा के लिए फीलगुड व मोदी-शाह के ग्रह-गोचर के अत्यधिक मददगार होने के बावजूद बिहार उनके लिए कठिन प्रदेश है. ऐसा पटना से लेकर दिल्ली तक का पार्टी नेतृत्व भी मानता है, लेकिन बंद कमरे में. नीतीश कुमार और लालू प्रसाद की एकता-जनता परिवार के मिलन अभियान- को बिहार के संदर्भ में भाजपा नेतृत्व सार्वजनिक तौर पर भले मज़ाक में ले, पर अपने चुनावी गणित के हिसाब से वह इसे अनुकूल नहीं पाता है. यह सही है कि लालू-नीतीश मिलन से नीतीश कुमार का समर्थक सामाजिक आधार में छीजन हुआ है, पर यह भी सही है कि भाजपा-विरोधी मतों की गोलबंदी भी तगड़ी हुई है. विधानसभा चुनावों में भाजपा को अधिकांश सीटों पर अपने विरोधियों से सीधी टक्कर का सामना करना पड़ेगा जो संसदीय चुनावों के विपरीत है. ऐसी स्थिति में कोई सौ सीटों पर भाजपा-व्यापक तौर पर एनडीए-को कांटे की लड़ाई लड़नी होगी. फिर, लालू-नीतीश की राजनीति में एक नया तत्व जुड़ गया हैः जीतनराम मांझी. अनेक अतिपिछड़े सामाजिक समूहों के साथ-साथ महादलित समाज के बड़े तबके के वह प्रिय राजनेता बनते जा रहे हैं. हालांकि मांझी दल या गठबंधन से अधिक खुद की राजनीति कर रहे हैं और अपना सिक्का जमाने में ज्यादा मनोयोग से लगे हैं. पर, जब तक वह जदयू, और इस नाते गठबंधन या जनता परिवार के अंग हैं, तब तक उनके होने का लाभ तो भाजपा विरोधी राजनीति को ही मिलना है. यह भाजपा के लिए परेशानी का नया सबब है.

कई चुनावों से भाजपा को कुछ सामाजिक समूहों का आक्रामक समर्थन मिलता रहा है. इनमें सबसे बड़ा और दबंग समूह अगड़ी जातियों का है. यह सही है कि ये जातियां किसी भी कीमत पर लालू प्रसाद या उनके साथ खड़े किसी राजनीतिक दल या समूह को स्वीकार करने को कतई तैयार नहीं हैं. इन समूहों की यह राजनीतिक हालत अब भी ऐसी ही है. फिर, वैश्य समुदाय का व्यापक समर्थन भाजपा को है. इसके साथ ही, लालू-नीतीश से नाराज़ कुछ पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियां व दलितों का एक समूह भाजपा से जुड़ गया है.

– शेष पृष्ठ संख्या 19 पर

एक नज़र

पोशाक व साइकिल राशि का वितरण

पूर्वी चंपारण जिले के चकिया प्रखंड क्षेत्र के राजकीयकृत बाबूलाल साह बालिका प्लस टू उच्च विद्यालय में शिविर लगाकर स्थानीय विधायक सह निबंधन उत्पाद एवं मद्य निषेध मंत्री अवधेश प्रसाद कुशवाहा के द्वारा छात्रवृत्ति, पोशाक व साइकिल की राशि का वितरण किया. नवम वर्ग की 1240 छात्राओं को राशि का वितरण किया गया. प्रत्येक छात्रा को 5300 रुपये दिये गये. वही दसवीं वर्ग की 881 छात्राओं के बीच प्रति छात्रा के हिसाब से 2800 रुपये का वितरण किया गया. विद्यालय के प्रधानाध्यापक ने बताया कि वर्ग नवम की छात्राओं के लिए 65,72,000 दशम वर्ग की छात्राओं के लिए 24,66,800 रुपये एवं ग्यारहवीं व बारहवीं की छात्राओं के लिए के बीच 1,81,000 रुपये यानि कुल 92,19,800 रुपये का आवंटन हुआ है. मंच का संचालन शिक्षक श्रवण मोदी ने किया जबकि मौके पर शत्रुघ्न प्रसाद, ओम प्रकाश गुप्ता, संजय मोदी, परवेज आलम, सुनील यादव, सत्यनारायण प्रसाद, नयन प्रसाद, प्रभुनारायण सिंह, टुन्ना पाठक, मुन्ना शर्मा, कुंदन गुप्ता, केदार प्रसाद सहित अन्य लोग मौजूद थे.

क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन

पूर्वी चंपारण जिले के ढाका उच्च विद्यालय के मैदान में विजयी क्रिकेट क्लब ढाका द्वारा स्वर्गीय बृजबिहारी प्रसाद क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया. इस कार्यक्रम का उद्घाटन शिवहर सांसद रमा देवी व स्थानीय विधायक पवन जायसवाल ने संयुक्त रूप से फीता काट कर किया. खेल की शुरुआत स्वयं शिवहर सासंद रमा देवी ने बल्लेबाजी कर की व विधायक पवन द्वारा गेंदबाजी की गई. उद्घाटन मैच बलिया और सोनपुर की टीमों के बीच खेला गया. टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी के लिए उतरी सोनपुर की टीम ने खराब शुरुआत करते हुए 89 रन पर ही सिमट गई. सबसे ज्यादा 28 रन रिंकी राज ने बनाए. सोनपुर टीम को सस्ते में सिमटने पर बलिया के कप्तान दीपक पांडेय की अहम भूमिका रही. मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दीपक कुमार को प्रखंड विकास पदाधिकारी सह सीओ संजीव कुमार ने दिया. मौके पर चिरैया विधान सभा से भाजपा के पूर्व प्रत्याशी लालबाबू गुप्ता, ओमप्रकाश आर्य, जिला पार्षद सुरेन्द्र प्रसाद, इन्तेखाबुल हक, ऐजाज आलम, जाकरुल खान, रिजवान आलम, अरुण पांडेय, मुन्ना अंसारी, आजम, शाहिद, रमेश्वर ठाकुर सहित हजारों की संख्या में दर्शक मौजूद थे. वही अम्पायर की भूमिका में प्रदीप कुमार मुन्ना, टीपू सिंह रहे तो कमेंटेटर की भूमिका में अब्दुल रहमान रहे.

किसान गोष्ठी आयोजित

पूर्वी चंपारण जिले के अरेराज प्रखंड की नवादा पंचायत में किसान गोष्ठी आयोजित की गयी. गोष्ठी को संबोधित करते हुए भारत सरकार के कृषि मंत्री राधामोहन सिंह ने किसानों के हित के लिए सरकार द्वारा चलायी जा रही योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की और इसका लाभ उठाने का आह्वान किया. उन्होंने मछली पालकों को भी अनेक सुझाव दिये और कहा कि मछली पालकों को प्रोत्साहित करने के लिए केन्द्र की मोदी सरकार संकल्पित है.इस दौरान कृषि वैज्ञानिकों ने नवादा पंचायत के किसानों को टमाटर, मशरूम बागवानी, मछली पालन पर जानकारी दी. तीसी अनुसंधान केन्द्र के वैज्ञानिक राजेश कुमार, पीपरा अनुसंधान केन्द्र के केके झा आत्मा के परियोजना निदेशक लक्ष्मण प्रसाद, जिला मत्स्य पदाधिकारी विनय कुमार, सहायक उद्यान निदेशक विपिन पोद्दार ने भी अपने-अपने विचार व्यक्त किये. मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष सुनिल मणि तिवारी, पूर्व जिलाध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता, भाजपा प्रवक्ता संजीव दुबे, भाजपा नेता अनिल राय, शम्भु सिंह, सतेन्द्र मिश्र, प्रखंड अध्यक्ष भाजपा विवेकानन्द पाण्डेय आदि उपस्थित थे.

– इंतेखाबुल हक़

Enjoy with Nature
MOULDED FURNITURE
NATURE
Contact : 9386595926, 9334115955

सुबह की धूप जरूरी
ariskon Pharma Pvt.Ltd.
An ISO 9001 : 2008 Certified Co.
डॉ.ए.के.मानव
URSLIV Tab. Ursodeoxycholic Acid 300 mg
Carbo-XT Ferrous Ascorbate with Folic Acid Tab.
Levokon-AZ Levofloxacin 250 mg + Azithromycin 250 mg Tab
Siliplex
NOKSIRA Pharma Pvt.Ltd.
OFFLOGYL-OS
A Division of Ariskon Pharma

सीतामढ़ी

अमन की जमीन पर हो रहा अपराध का विस्तार

देश में बदलते राजनीतिक माहौल के आग़ाज़ से लोगों को लगा कि सचमुच अच्छे दिन की शुरुआत होने वाली है. सुशासन के साथ विकास का कदम जनभावना के अनुरूप होगा. परंतु राजनीतिक उथल-पुथल के बाद सीतामढ़ी जिले में लोगों को नित्य नये झंझावातों से रू-ब-रू होने की विवशता बनती जा रही है. मां जानकी की पावन जन्म स्थली लगातार कोहराम का केंद्र बन रही है. शासन की कमान ढीली होती जा रही है. जनप्रतिनिधि भी सुशासन के मामले में नकारा साबित होते जा रहे हैं. ऋषि-मुनियों की पावन तपोस्थली रहे सीतामढ़ी जिले में अमन की बजाय लगातार अपराध का विस्तार हो रहा है. औसतन प्रतिमाह एक व्यक्ति की निर्मम हत्या आम बात हो गयी है..

वाल्मीकि कुमार

भारत-नेपाल सीमा पर स्थित सीतामढ़ी जिले का धार्मिक, ऐतिहासिक व सांस्कृतिक महत्व रहा है. मां सीता की पावन जन्म स्थली होने के कारण इस जिले को धार्मिक स्थल के रूप में जाना जाता है. विविधताओं में एकता का संदेश के साथ अमन व भाईचारे की मिसाल कायम करने वाले इस जिले में पग-पग पर धार्मिक व ऐतिहासिक महत्व के स्थल मौजूद हैं. सामाजिक सौहार्द के प्रतीक मंदिर का भजन एवं मस्जिद की अज़ान हमेशा जिले को गौरवान्वित करता रहे हैं. तकरीबन डेढ़ दशक पूर्व जब जिले में पहली बार नक्सलियों ने दस्तक दी थी तब लोगों को लगा था कि अब सामाजिक एकता को खंडित होने से कोई बचा नहीं सकता. हालात ऐसे बने की कुछ सालों तक जिले में नक्सली घटनाएं लोगों का चैन उड़ाते रहीं. परंतु बाद में शासन तंत्र की सजगता के कारण बहुत हद तक इस पर विराम भी लगा. लेकिन विध्वंस की तालीम ले चुके तत्व अपनी करनी से बाज़ आने की बजाय आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने में लग गये. बम विस्फोट, लूट, अपहरण व फिरौती दिनचर्या बनने लगी. इस दौर में जिले के कई चिकित्सकों व नर्सिंग होम तो कई व्यवसायियों के प्रतिष्ठान अपराधियों के निशाने पर रहे. लगातार बढ़ते अपराध का आलम रहा कि कई लोगों को असमय ही काल के गाल में समाना पड़ा.

बीते दिनों का अगर जिक्र किया जाये तो शहर के चंद्रिका स्टोर्स, मिथिला साइकिल स्टोर्स, सारवगी फैंसी स्टोर्स, शंभू जेनरल स्टोर्स, गणेश पेट्रोल पंप, बजाज शो रूम समेत कई स्थानों को अपराधियों ने बम से निशाना बनाया. जबकि दीपक स्टोर्स गली में एक युवा पप्पू सिंह के अलावा जूता व्यवसायी पप्पू, कपड़ा व्यवसायी अनिल कुमार, शराब व्यवसायी संजय कुमार, मुखिया कारी प्रसाद, बेलसंड नगर पंचायत अध्यक्ष रामचंद्र सहनी, राजद नेता हरि शंकर साह, बाजपट्टी प्रखंड जदयू अध्यक्ष राम प्रकाश महतो, विकास योजनाओं के कार्यान्वयन में लगी निर्माण एजेंसी के पदाधिकारी व कर्मी समेत अन्य की अपराधियों ने हत्या गोली मार कर दी थी. उक्त तमाम घटनाओं को लेकर नगर समेत अन्य थाना में अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज भी करायी गयी. कुछ मामलों में पुलिस की सक्रियता से अपराधी पकड़े गये तो कई मामलों में पुलिस गुत्थी सुलझाने में नाकाम भी रही. तकरीबन हर घटना के बाद जिले में आंदोलन ने जोर पकड़ा और किसी न किसी पुलिस पदाधिकारी अथवा कर्मी को लाइन हाज़िर से लेकर स्थानांतरण तक का सामना करना पड़ा. इस बीच ऐसे भी दौर को लोगों ने देखा है जब कुछ नामचीन अपराधियों की लाश का भी पोस्टमार्टम कराने का मौका जिला पुलिस को मिला है.

अब हाल के सालों में बढ़ी आपराधिक घटनाओं पर भी नज़र डालना आवश्यक है. जब अपराधियों के बढ़ते मनोबल ने आम लोगों से लेकर प्रशासनिक महकमे तक को परेशानी में डालने का काम किया है. साल 2014 के जनवरी माह में नानपुर थाना के चकौती पंचायत के सरैया गांव में डकैती के दौरान राम नंदन महतो एवं डुमरा थाना के कुम्हर विष्णुपुर गांव निवासी सुनील मंडल की हत्या कर दी गयी. फरवरी माह में रीगा थाना क्षेत्र के स्वर्ण व्यवसायी मुकेश कुमार साह का अपहरण कर लिया गया. मार्च माह में पुनौरा थाना के आजमगढ़ चौक स्थित होटल व्यवसायी किशोर कुशवाहा की हत्या कर दी गयी. जून महीने में सुप्पी प्रखंड के ननकार सिमरदह गांव में किशोरी सिंह की हत्या कर दी गयी. जुलाई में परिहार के मुसहरनिया निवासी भाजपा नेता राम स्नेही ठाकुर की हत्या कर दी गयी. सितंबर में शहर के गुदड़ी रोड निवासी पटना उच्च न्यायालय के अधिवक्ता रणधीर कुमार की हत्या कर दी गयी. अक्टूबर में बैरगनिया नगर पंचायत के दुबरावा में व्यवसायी राजेश जायसवाल के घर से डकैती में लाखों की संपत्ति लूट कर गृहस्वामी का पुत्र राजा जायसवाल को चाकू मार घायल कर दिया. नवंबर में बेलसंड थाना के कंसार गांव में मुखिया आशा देवी का पति आमोद कुमार सिंह की हत्या कर दी गयी. जबकि इसी माह में रीगा थाना क्षेत्र में दो महिलाओं की हत्या रास्ता में कर दी गयी. दिसंबर माह में पवन सिंह कुशवाहा व व्यवसायी मुनींद्र पाठक की हत्या अलग-अलग स्थानों पर अपराधियों ने कर दी. इससे पूर्व साल 2008 में अपराधियों ने शहर के चर्चित दवा दुकान नवीन मेडिकल हॉल के मालिक वर्तीद्र खेतान से रंगदारी की मांग की थी. तब जिला पुलिस प्रशासन की ओर से व्यवसायी को अंगरक्षक मुहैया करा दिया गया था. वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान प्रशासनिक स्तर पर अंगरक्षक वापस ले लिया गया. नतीजा हुआ कि 2014 की आखिरी रात यानी की 31 दिसंबर की रात को दुकान से घर जाने के दौरान रास्ते में ही कुछ अपराधियों ने जिला केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष सह दवा व्यवसायी वर्तीद्र खेतान की गोली मार कर निर्मम हत्या कर दी.

घटना के बाद जनाक्रोश का आलम रहा कि सदर अस्पताल परिसर में लोगों ने स्थानीय सांसद राम कुमार शर्मा, नगर भाजपा विधायक सुनील कुमार पिंटू, परिहार विधायक राम नरेश यादव के अलावा एसपी नवल किशोर सिंह समेत अन्य प्रशासनिक पदाधिकारियों को भला-बुरा कहने से परहेज नहीं किया. अगले दिन पहली जनवरी को जब हर कोई देश में नया साल के जश्न में डूबा था, तब सीतामढ़ी की सड़कों पर आक्रोश की चिंगारी दहक रही थी. बाज़ार बंद से लेकर धरना-प्रदर्शन तक व्यापक स्तर पर किया जाता रहा. जिला दवा व्यवसायी संघ की घोषणा के आलोक में तीन दिनों तक जिले में दवा की दुकानों में ताला लटका रहा. शहर के मेहसौल चौक पर घंटों धरना पर बैठे सांसद व विधायकों के पास डीएम व एसपी खुद पहुंचने का साहस नहीं जुटा सके. बाद में भारी पुलिस बल की मौजूदगी में मुजफ्फरपुर प्रक्षेत्र के आईजी पारसनाथ एवं डीआइजी अजय कुमार मिश्रा धरना स्थल पहुंचे तब लोगों ने एसपी नवल किशोर सिंह को बदलने की मांग करने लगे. परंतु आलाधिकारियों ने आनन-फानन में नगर थानाध्यक्ष रामाकांत सिंह पर लाईन हाज़िर की कार्रवाई करते हुए नगर की कमान थाम चुके सुरसंड थानाध्यक्ष विमल कुमार सिंह के हाथ में पुनः नगर थाना की कमान थमा दी.

जबकि दूसरी ओर जिला पदाधिकारी डॉ. प्रतिमा ने कर्तव्यहीनता के आरोप में जिला गोपनीय प्रशाखा के लिपिक विष्णु ठाकुर, आदेशपाल राज मंगल पासवान व कार्यालय परिचारी राम श्रेष्ठ महतो को निलंबित कर दिया. हालांकि उक्त कर्मियों के निलंबन को लेकर चर्चाओं का बाज़ार गर्म होने लगा है. बताया जाता है कि डीएम डॉ. प्रतिमा द्वारा अघोषित तौर पर अपने आवासीय कार्यालय में किसी से मुलाकात अथवा किसी भी प्रकार का आवेदन नहीं लेने का फरमान जारी किया गया है. दवा व्यवसायी वर्तीद्र खेतान हत्या कांड के संबंध में जिला केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन का प्रतिनिधि मंडल जब डीएम से मिलने उनके आवासीय कार्यालय पहुंचे तब कर्मियों ने डीएम के जारी मौखिक फरमान के आलोक में प्रतिनिधि मंडल में शामिल एसोसिएशन के सचिव राज कुमार, उपाध्यक्ष मनोज कुमार सिंह व सह सचिव राजू श्रीवास्तव को लौटाया था. बताया जाता है कि बाद में किसी का फोन आने पर डीएम प्रतिनिधिमंडल से मिली थी. डीएम के फरमान को युवा शक्ति के प्रदेश पदाधिकारी दिलीप सिन्हा सही ठहराते हुए कहा है कि उनके संगठन के सदस्यों के साथ भी पूर्व में ऐसा ही व्यवहार किया गया था, जिसके कारण डीएम आवास से लौटना पड़ा था. लोगों का कहना है कि अगर इस बात में तनिक भी सच्चाई है तो डीएम को कर्मियों पर निलंबन की कार्रवाई से परहेज़ करते हुए जारी अघोषित फरमान को जनहित में वापस लेना चाहिए.

अब जिला पदाधिकारी इस पहलू को कितना गंभीरता से लेती हैं यह तो उनके विवेक पर निर्भर करता है. परंतु वर्तीद्र हत्याकांड के बाद सूबे के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के आगमन ने सीतामढ़ी के सियासी तापमान को जरूर बढ़ा दिया है. भले ही वर्तीद्र के अंतिम संस्कार में उनका आगमन मानवीय संवेदनाओं का अहम हिस्सा हो, परंतु मामले को लेकर उनके राजनीतिक बयान ने जिले की राजनीति को नयी दिशा देने लगी है. मोदी ने ओल्ड एक्सचेंज रोड स्थित पूर्व पर्यटन मंत्री सह नगर भाजपा विधायक सुनील कुमार पिंटू के आवास पर सांसद राम कुमार शर्मा, विधायक राम नरेश यादव, मोतिलाल प्रसाद समेत अन्य की मौजूदगी में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि नये गठबंधन के बाद राजद से जुड़े अपराधियों का मनोबल बढ़ा है. राजद के सहारे चल रही सरकार को गिरने का भय सता रहा है. जिसके कारण सरकार कार्रवाई से परहेज़ कर रही है. इधर सूबे के सूचना प्रावैधिकी मंत्री शाहिद अली खान ने कहा है कि वर्तीद्र की हत्या दुःखद है. इसके लिए किसी भी राजनीतिक बयानबाजी उपयुक्त नहीं है. घटना के लिए सीधे तौर पर एसपी सीतामढ़ी ज़िम्मेदार हैं. सरकार की भी दोषी नहीं है. इस मामले को राज्य सरकार गंभीरता से ले रही है. जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विमल शुक्ला ने कहा कि अपराध के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए. भयमुक्त माहौल बनाने में जनप्रतिनिधियों को अपनी भूमिका का निर्वाह करना चाहिए. उन्होंने राज्य सरकार से कुंदन कृष्णन को मुजफ्फरपुर प्रक्षेत्र का आईजी बनाने की मांग की.

घटना के बाद अब जिले में राजनीति नयी करवट लेने लगी है. एक ओर भाजपा के सुशील कुमार मोदी समेत सांसद व विधायकों को व्यवसायी समर्थक तो दूसरी ओर इसे जातिवादी राजनीति करार दिया जाने लगा है. चर्चा यह भी जोर पकड़ रही है कि वर्तीद्र हत्याकांड से पूर्व भी जिले में अन्य व्यवसायियों की हत्या हो चुकी है, परंतु उस वक्त ऐसा प्रदर्शन व व्यवहार करने के लिए किसी को फुर्सत नहीं थी. परंतु अब वोट की राजनीति की जा रही है. सच्चाई चाहे जो भी हो परंतु फिलहाल सभी की नज़र जिले में बढ़ते अपराध पर नियंत्रण को लेकर शासन और प्रशासन के स्तर पर की जा रही कार्रवाई पर टिकी है. जिले के अमन पसंद लोगों को राहत मिलती है या अपराधियों का तांडव जारी रहता है, इस पर सबकी नज़र है.■

feedback@chauthiduniya.com

बेगूसराय

मूर्ति बनाने वालों की जिंदगी बदहाल

सुरेश चौहान/पंकज कुमार झा

क्रियाशील पूंजी का अभाव, महंगी मिट्टी, बढ़ते रबर एवं प्लास्टिक उद्योग, बाज़ार की कमी तथा सरकारी सहयोग एवं प्रोत्साहन नहीं मिलने से दो सौ वर्ष पुराने मंसूरचक का विख्यात मूर्ति निर्माण कला उद्योग दम तोड़ रहा है. दूसरों के बच्चों के चेहरे की लाली बरकरार रखने एवं उन्हें हंसाने के लिए तरह-तरह के मुखौटों का निर्माण करनेवाले कारीगरों के बच्चे बदहाल हैं. सरकारी उपेक्षा ने उनके बच्चों के चेहरे की लाली एवं मुस्कान छीन ली है. शिक्षा से वंचित एवं गरीबी की मार झेल रहे कारीगरों के कुछ बच्चे किसी तरह पुश्तैनी धंधे को जीवित रखे हुए हैं जबकि आजीविका की तलाश में सैकड़ों युवक पलायन कर चुके हैं.

बेगूसराय से 40 किलोमीटर उत्तर-पश्चिम जिले का मंसूरचक प्रखंड मूर्ति निर्माण कला का केंद्र हुआ करता था. मिट्टी से अनेक प्रकार की मूर्ति एवं मुखौटा-खिलौना निर्माण में यहां के कारीगरों को महारथ हासिल था. उनकी आजीविका का एकमात्र साधन मूर्ति निर्माण करना ही था. इस कला से यहां के कारीगर काफी संतुष्ट एवं खुशहाल थे. कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित मूर्तियां, खिलौने एवं मुखौटे का बाज़ार बिहार के बाहर उत्तर प्रदेश, कलकत्ता एवं जम्मू-कश्मीर तक फैला था. यहां के कारीगर मिट्टी से गणेश, शंकर, सरस्वती, विश्वकर्मा, श्रीकृष्ण, श्रीराम-जानकी, बजरंगबली, सूर्य, काली, दुर्गा, लक्ष्मी सहित अन्य देवी-देवताओं की मूर्ति, तरह-तरह के आकर्षक मुखौटे एवं खिलौने आदि का निर्माण करते थे. अवसर विशेष पर मुंबई से गणेश जी की प्रतिमा बनाने, कलकत्ता एवं उत्तर प्रदेश से दुर्गा तथा काली की प्रतिमा बनाने एवं बिहार के अनेक भाग से सरस्वती, विश्वकर्मा, श्रीकृष्ण, सूर्य की प्रतिमा बनाने के काफी संख्या में आदेश प्राप्त होते थे. कारीगरों को अच्छा-ख़ासा पारिश्रमिक मिलता था और वे सपरिवार खुशहाल जीवन जीते थे. यहां के कारीगरों के वंशजों का कहना है कि ढ़ोका पंडित, दुःख हरण पंडित एवं बद्री पंडित ने मिट्टी से घरेलू उपयोग के सामान बनाने के अलावा मूर्ति, खिलौने एवं मुखौटे बनाने की कला का श्री गणेश किया था. यहां की निर्मित मूर्ति की काफी मांग थी. मूर्ति खरीदने के लिए बाहरी व्यापारियों का जमघट लगा रहता था. ऑर्डर मिलने के तीन महीने बाद ही आपूर्ति संभव हो पाती थी. व्यापारी यहां से थोक भाव में मूर्ति खरीदकर वनारस, दिल्ली, जमशेदपुर, पटना, आसनसोल, धनबाद, कश्मीर, कलकत्ता आदि नगरों में ले जाकर बेचते थे. गर्मी के दिनों में यहां की निर्मित सुराही की मांग काफी बढ़ जाती थी. लेकिन अब रबर एवं प्लास्टिक से निर्मित मूर्ति, मुखौटे एवं खिलौने ने इस उद्योग की कमर तोड़ डाली है.पैंतीस वर्षीय मेघू पंडित कहते है कि पूर्वजों से विरासत में प्राप्त कला को जीवन में इतारकर काली, दुर्गा, सरस्वती, शंकर, महावीर, सूर्य, भारत माता की प्रतिमा एवं अनेक प्रकार का मुखौटा, खिलौना, सामा-चकेवा आदि बनाकर किसी तरह परिवार का भरण-पोषण कर रहे है.

38 वर्षीय लक्ष्मी नारायण पंडित एवं 40 वर्षीय विनय पंडित कहते हैं कि मूर्ति एवं खिलौना निर्माण के लिए अधिक कीमत पर मिट्टी, बांस एवं धान का पुआल आदि खरीदना पड़ता है जबकि निर्मित सामानों का बाज़ार में लाभकारी मूल्य नहीं मिल पाता है. इससे परिवार का गुज़ारा मुश्किल से हो पाता है और बच्चों को शिक्षा नहीं देकर इसी कला में ढाल रहे हैं. 16 वर्षीय राम दयाल पंडित कहते हैं कि गरीबी के कारण पढ़ नहीं पाया. पूर्वजों से प्राप्त मूर्ति निर्माण कला के सहारे जी रहे हैं. आजीविका सुचारू रूप से नहीं चल रहा है. पैंसठ वर्षीय जीवछी देवी कहती हैं कि पैसों के अभाव में बच्चों को पढ़ा नहीं पायीं. पति की मृत्यु के बाद इस कला को अपनाकर परिवार का पालन-पोषण कर रही हूं. लेकिन रबर एवं प्लास्टिक की मूर्ति एवं खिलौने ने जीना हराम कर दिया है. 70 वर्षीय भुल्ली देवी कहती हैं कि सरकार के पास कई बार आवेदन दिया लेकिन सहायता या ऋण नहीं मिला.

बिहार लोक सेवा आयोग के पूर्व सदस्य प्रोफेसर डॉ.ओम प्रकाश राय, शिक्षाविद् गणेश शंकर दत्त ईश्वर, प्राचार्य भोला कुमार मिश्र कहते हैं कि मिट्टी निर्मित्त मूर्तिकला उद्योग को जीवित रखने के लिए सरकारी सहायता एवं प्रोत्साहन की जरूरत है. स्वरोजगार गारंटी योजना के तहत इन कारीगरों को ऋण मिलना चाहिए जिससे कारीगर अपनी कला और आजीविका को सुदृढ़ करते हुए समाज की मुख्यधारा से जुड़े रह सकें. यदि मंसूरचक में मूर्ति निर्माण करनेवाले कारीगरों को बेहतर प्रशिक्षण, क्रियाशील पूंजी एवं बाजार उपलब्ध कराया जाय तो यह कुटीर उद्योग देश का आकर्षण केंद्र बन सकता है.■

feedback@chauthiduniya.com

मोदी ही बनेंगे भाजपा के मांझी

पृष्ठ 17 का शेष

भाजपा से इनके जुड़ाव का बड़ा कारण रालोसपा और लोजपा का एनडीए में होना बताया जाता हैं. यह पूर्ण सत्य नहीं हैं. वस्तुतः गत कुछ चुनावों के दौरान कुछ जातियों- जिनमें अगड़ी, पिछड़ी, अति पिछड़ी भी हैं-की मतदान शैली जाति केंद्रित होने लगी हैं. इसी तरह दलित का एक समूह पिछले दो-तीन चुनावों से किसी भी कीमत पर नीतीश-लालू को स्वीकार करने को तैयार नहीं है. सो, आज के बिहार में विभिन्न सामाजिक समूहों के ऐसे राजनीतिक आचरण का लाभ हासिल करने में भाजपा अव्वल रही है. लेकिन राजनीतिक पूंजी यह नहीं बन सकी है, इन सामाजिक समूहों को बांध कर रखने के लिए इसके पास सम्यक कार्यक्रम और ताकतवर नेता का तो अभाव रहा ही है, बिहार के ग्रामांचल में बहुत बड़े सामाजिक समूहों में पार्टी की छवि बड़े लोगों के दल की रही है. यह छवि दशकों पुरानी है और नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बावजूद यह छवि धूमिल नहीं हुई है.

राजनेताओं की भाजपा दौड़ भी पार्टी की परेशानी का बड़ा कारण है. पहले भाजपा की ओर कटु भाजपा विरोधियों तक की दौड़ शुरू हुई और संसदीय चुनावों के बाद इसमें सेसेंक्स जैसी उछाल आ गई थी. लोकसभा चुनावों के दौरान देश के अन्य भागों की तरह बिहार में भी मोदी लहर थी और इसका पूरा लाभ भाजपा को मिला. लेकिन विधानसभा उपचुनावों में हालत वैसी नहीं रही, भाजपा अपनी सीटें भी नहीं बचा सकी. फिर भी, प्रवासी राजनेताओं का आना कम नहीं हुआ. पर, झारखंड में ऐसे प्रवासी राजनेता चुनाव मैदान में खेत रहे. इसके बाद यहां आने वाले और लानेवाले दोनों चेत गए हैं. फिर भी, यह सवाल भाजपा के आंतरिक हलकों में तो गंभीरता से तैर ही रहा है कि प्रवासी राजनेताओं का क्या होगा. पार्टी ने इसे लेकर आधिकारिक तौर पर कुछ भी फैसला नहीं लिया है. लेकिन इतना तो तय है कि झारखंड चुनाव के बाद दल के पुराने व निष्ठावान, मगर उपेक्षित, नेता-कार्यकर्ताओं को नई ताकत मिली है. मौका नहीं, तो बदला का भाव बिहार में भी अपना पैर जमाने लगा है.

ऐसी नौबत पार्टी को निन्यानब्बे का फेरा लगा देती है जैसा महाराष्ट्र में हुआ, झारखंड में हुआ. पिछले महीनों में जिस उम्मीद भरे आग्रह के साथ भाजपा के बड़े-बड़े नेताओं ने अपना गुट बनाने के ख्याल से पार्टी में प्रवासी राजनेताओं की लंबी-चौड़ी जमात खड़ी की है, वे फिलहाल खामोश हैं. और ऐसे क्षत्रपों के केन्द्रीय सरपरस्त किंकर्त्तव्यविमूढ़. यही कारण है कि पार्टी के बड़े-बड़े मंचों पर भी ऐसे सवालात को टालने की कोशिश होती रही है, पटना में भी यही हुआ.■

feedback@chauthiduniya.com

एक नज़र

दूसरी बार हारे सत्यानंद भोक्ता

चतरा विधानसभा के पूर्व विधायक सत्यानंद भोक्ता को दूसरी बार राजनिति में हार का स्वाद चखना पड़ा है. ज्ञात हो कि 2009 के विधान सभा चुनाव में चतरा जिले के सिमरिया विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी के रूप में वह चुनाव लड़ रहे थे. वहीं झावीमो के उम्मीदवार के रूप मे जयप्रकाश सिंह चुनावी मैदान में थे. उस वक्त झाविमो ने ही पूर्व कृषि मंत्री सत्यानंद भोक्ता को हार का सवाद चखाया था. ठीक इसके उलट 2014 के विधानसभा के चुनाव में चतरा विधान सभा से ये दोनो प्रत्याशी एक दूसरे आमने-सामने खड़े थे लेकिन स्थिति पहले से बिल्कुल भिन्न थी. भिन्नता इस प्रकार है कि सत्यानंद भोक्ता भाजपा छोड़ कर झाविमो के प्रत्याशी बने और जयप्रकाष सिंह भोक्ता भाजपा का प्रत्याशी बन कर चुनावी समर में आए. दुर्भाग्य ने सत्यानंद भोक्ता का पीछा यहां भी नहीं छोड़ा.

महारुद्र यज्ञ को लेकर ध्वजारोहण

हंटरगंज प्रखेड के ग्राम हिरींग के ग्रामवासी 11 दिवसीय महारुद्र यज्ञ का आयोजन किया है, जो 24 मार्च से 4 अप्रैल तक चलेगा जिसको लेकर ग्राम वासियों में काफी उत्साह है तथा सफल संचालन को लेकर एक कमेटी का गठन किया गया है. इस कमेटी में 11 सदस्य को प्रतिनिधित्व सौंपा गया है जिसमें उदय नारायण सिंह, प्रो. अरविंद कुमार सिंह (भुरकुंडा कॉलेज) भूतपूर्व प्राचार्य राजेश्वरी प्रसाद सिंह कौशलेंद्र कुमार सिंह बड़े बाबू इंटर कॉलेज हन्टरगंज बैजनाथ प्रसाद सिंह प्रोफेसर जैनेंद्र कुमार सिंह, प्राचार्य डिग्री कॉलेज हन्टरगंज पंचायत समिति प्रेम किशोर सिंह कमल कुमार केशरी बृज किशोर सिंह प्रोफेसर अरविंद कुमार सिंह समस्त यज्ञ प्रेमी उपस्थित थे.

– अमरेन्द्र प्रताप

मजबूर नहीं मजबूत हैं महिलायें

नवगछिया नगर पंचायत के सभागार में रविवार को अनुमंडल विधिक सेवा समिति द्वारा आयोजित विधिक जागरूकता शिविर में नवगछिया व्यवहार न्यायालय के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी एसके गुप्ता ने कहा कि भारत की महिला अब अबला से सबला हो चुकी हैं. महिलायें मजबूर नहीं पूरी तरह से मजबूत हैं. आज महिलाओं को घरेलू हिंसा का शिकार बनाया जा रहा है. जो एक चिंतनीय विषय है. जबकि इनके पक्ष में कई मजबूत कानून और अधिकार बने हुए हैं. जरूरत है अपने हक और अधिकार को जानने समझने और लेने की. शिविर में कई कानूनों की जानकारी भी दी गयी. जिसकी अध्यक्षता मुंसिफ मजिस्ट्रेट छेदी राम तथा संचालन अधिवक्ता विभाष प्रसाद सिंह ने की. इस मौके पर नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी संजीव कुमार, मुख्य पार्षद इंद्रा देवी, प्रमुख समाजसेवी सह वार्ड पार्षद विनोद मंडल, वीरेंद्र सिंह, चंदेश्वरी सिंह, सोनी इकराम सहित दर्जनों महिलायें भी मौजूद थीं.

खेतों में हुई खाद की किल्लत

भागलपुर जिले के नवगछिया अनुमंडल में लगातार मची यूरिया खाद की किल्लत से किसानों में काफी हाहाकार मचा है. किसानों की इस विकराल होती समस्या को लेकर भागलपुर के जिला पार्षद सह बिहपुर विधानसभा संघर्ष मोर्चा के संयोजक गौरव राय ने सदस्यों के साथ नवगछिया के अनुमंडल पदाधिकारी से समाधान कराने का अनुरोध किया. जिनके अनुसार खाद की कमी को लेकर दुकानदारों ने दुकान के शटर गिरा दिये हैं. संयोजक राय ने बताया कि अगर समय रहते इस समस्या का समाधान नहीं होगा तो किसान सड़क पर भी उतर सकते हैं. इस मौके पर रोहित आनंद शुक्ला, अधिवक्ता राधाकृष्ण सिंह, नीरज राय, मधु चौधरी, अमरेन्द्र चौधरी उर्फ बाबू राय, सोनू राय, बिपिन कुमार इत्यादि कई प्रमुख किसान भी थे.

पुण्यतिथि पर प्रेरणा दिवस

नवगछिया अनुमंडल के बिहपुर विधानसभा क्षेत्र के गौरीपुर गांव में रविवार को अमर शहीद स्वतंत्रता सेनानी स्व. सत्यदेव राय की 69वीं पुण्यतिथि को प्रेरणा दिवस के रूप में मनाया गया. जिसका उद्घाटन बिहपुर के भाजपा विधायक ई. कुमार शैलेंद्र ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया. गौरीपुर कॉलेज के प्राचार्य प्रो. वरुण कुमार राय ने सत्यदेव बाबू के जीवन पर विस्तार से चर्चा की. समारोह की अध्यक्षता श्यामसुंदर राय तथा संचालन विधानचंद्र राय ने किया. मौके पर मौजूद लोगों ने उनके सादगी भरे जीवन से प्रेरणा लेते हुए आदर्श जीवन जीने के साथ-साथ नशामुक्त समाज बनाने का संकल्प भी लिया. इस दौरान मो. इरफान आलम, सदानंद चौधरी, निरंजन चौधरी, राम बहादुर सिंह, त्रिलोचन ठाकुर, राम निवास कुंवर, लल्लू झा, सुरेश साह इत्यादि सैकड़ों लोगों ने पुष्पांजलि भी अर्पित की.

भाजपा विधायक अनशन पर

नवगछिया अनुमंडल को भागलपुर जिला मुख्यालय से जोड़ने वाले गंगा नदी पर बने विक्रमशिला सेतु पर अक्सर लगने वाले जाम और महाजाम से मुक्ति के स्थायी समाधान की मांग को लेकर भाजपा के बिहपुर विधायक ई. कुमार शैलेंद्र लगातार अनशन कर रहे हैं. इसी क्रम में 30 दिसंबर से पहली जनवरी तक विधायक ने भागलपुर आयुक्त कार्यालय के समक्ष अनशन किया. जबकि इससे पहले भी विधायक द्वारा आयुक्त कार्यालय के समक्ष तथा पुल पर अनशन किया जा चुका है. भागलपुर आयुक्त कार्यालय के समक्ष किए गए अनशन स्थल पर भागलपुर नगर निगम की डिप्टी मेयर प्रीति शेखर, विधान पार्षद एनके यादव, जिलापार्षद पंकज कुमार राय, भाजपा जिलाध्यक्ष सुबोध सिंह कुशवाहा, पूर्व सांसद अनिल यादव, प्रो. भोला कुंवर, चक्रधर सिंह सहित दर्जनों प्रमुख भाजपा तथा क्षेत्रीय लोगों ने इस अनशन का समर्थन करते हुए समाधान की मांग जिला प्रशासन से की है.

– राजेश कनौजिया

नागरिक मंच ने निकाला मौन जुलूस

सीतामढ़ी जिले में बढ़ती आपराधिक घटनाओं के खिलाफ नागरिक मंच के तत्वावधान में मौन जुलूस निकाला गया. मंच के संयोजक डॉ. बृजेश शर्मा के नेतृत्व में शहर के जानकी देवी मंदिर परिसर से जुलूस निकाला गया. जुलूस नगर के मुख्य मार्ग से गुजरा. जिले में बढ़ते अपराध पर अंकुश की मांग को लेकर निकाले गये जुलूस में नागेंद्र प्रसाद सिंह, पूर्व विधायक खलील अंसारी, राजद जिलाध्यक्ष मो. शफीक खां, मो जियाउल्लाह, डॉ. राजेश सिंह, डॉ. राजेश सुमन, अभय प्रसाद, डॉ. विजय सर्राफ, प्रो राज कुमार गुप्ता, प्रो. जितेंद्र कुमार वर्मा, दिनेशचंद्र द्विवेदी, सुरेंद्र पटेल, शंकर बैठा, ईश्वरचंद्र मिश्र, रकटू प्रसाद, केदार शर्मा, प्रमोद नील, गणेश गुप्ता, आफताब अंजुम बिहारी, मुन्ना सिंह यादव, शिव शंकर यादव समेत अन्य शामिल थे.

– ब्रजेश

बैठक का आयोजन

सीतामढ़ी जिले के सोनबरसा प्रखंड कार्यालय परिसर स्थित सभाकक्ष में पंचायत समिति सदस्य व मुखिया की एक बैठक उप प्रमुख अहिराज शैलेंद्र भूषण की अध्यक्षता में हुई. बैठक में बीडीओ रितेश कुमार, सीओ सत्येंद्र कुमार दत्त, पीओ कुमार गौरव, पंचायती राज पदाधिकारी मुकेश कुमार, प्रभारी कृषि पदाधिकारी सुशील कुमार सिंह, सीडीपीओ कृष्णा सिंह, जिला परिशद उपाध्यक्ष ईश्वर नारायण साह, उपेंद्र प्रसाद यादव, लालबाबू मंडल, जागेश्वर महतो, देवल साह, विनोद राय, हबीबुल रहमान, बैद्यनाथ प्रसाद, जय नारायण पासवान, मंजू देवी व आशा देवी समेत अन्य थे. ■

– अमरनाथ

एक नज़र

क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन

सीतामढ़ी जिला मुख्यालय डुमरा स्थित स्टेडियम में 7 दिवसीय राज्य स्तरीय अंतरजिला महिला क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया. उद्घाटन नगर भाजपा विधायक सुनील कुमार पिंटू, परिहार विधायक राम नरेश यादव व जिला आपूर्ति पदाधिकारी कृष्ण कुमार उपाध्याय ने संयुक्त रूप से की. बिहार क्रिकेट संघ के तत्वावधान में जिला क्रिकेट संघ द्वारा आयोजित प्रतियोगिता के उद्घाटन में संघ के अध्यक्ष प्रो. नीरज, सहायक सचिव मनोज कुमार सिंह, सबीह अहमद, अखिलेश कुमार, पंकज कुमार अग्रवाल, कृष्ण रंजन वर्मा, पंकज कुमार सिंह, शैलेंद्र कुमार, ज्ञान प्रकाश उर्फ रिंकू सिंह, निशांत कुमार सिंह, कोच रीतेश कुमार सिंह समेत अन्य थे.

विद्युत आपूर्ति शुरू

सीतामढ़ी जिले के रुन्नीसैदपुर प्रखंड में ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति की कवायद शुरू कर दी गयी है. पिछले दिनों क्षेत्र के पुनरवारा गाव में जदयू नेता राजेश चौधरी ने विद्युत आपूर्ति का शुभारंभ किया. इस अवसर पर चौधरी ने लोगों को भरोसा दिलाया कि साल 2015 में क्षेत्र के गांव-गांव में बिजली उपलब्ध कराना ही स्थानीय विधायक गुड्डी देवी का मकसद है. कहा कि अब लोगों को डिबिया युग में समय नहीं गुजारना होगा. मौके पर मुखिया रामबाबू साह, सरपंच संतलाल ठाकुर, रामा षंकर सिंह, अमरनाथ राय, धर्मेंद्र यादव, इपेंद्र बैठा, गौरी षंकर सिंह, रत्नेष्वर चौधरी, राम सज्जन राय, राम सिकिल राय थे. मजरोहा में पंकज कुमार, प्रेम किशोर चौधरी, अषोक चौधरी व दिवाकर चौधरी समेत अन्य थे.

– विभा

कंबल वितरित

समस्तीपुर प्रखंड के चकनूर पंचायत के रहमतपुर व पोखरैरा में कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया. भाजपा ग्रामीण मंडल के तत्वावधान में पार्टी के प्रांतीय उपाध्यक्ष राम सुमिरन सिंह के सौजन्य से उक्त कार्यक्रम में गरीब व असहायों के बीच कंबल का वितरण किया गया. देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेयी के 90 वें जन्मदिवस पखवाड़े पर आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता मुरारी चौधरी व मनोज कुमार सिंह ने किया. धन्यवाद ज्ञापन रोशन राय व अमित कुमार ने किया. कार्यक्रम में बतौर अतिथि क्षेत्रीय प्रभारी शशिकांत आनंद, शैलेंद्र सिंह, राकेश कुमार, प्रभात कुमार, राकेश रंजन पिंटू, रंजीत कुमार, अरविंद राय, अजय राय, हेमंत मिश्रा, अरुण झा, टुनटुन सिंह, अमित कुमार, मुकेष कुमार व नवीन झा समेत अन्य थे.

– अमृता

नियमों की उड़ रही है धज्जियां

परबत्ता प्रखंड में आंगनबाड़ी केंद्र संचालन में नियमों की धज्जियों उड़ रही है. भवन रहते भी किराये के नाम पर राशि का लूट हो रहा है. जिलाधिकारी राजीव रोशन ने गत माह जिले से 350 आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन निर्माण को लेकर हरी झंडी दी थी. उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया है कि जहां भवन बना हुआ है. उसमें आंगनबाड़ी का संचालन हो. लेकिन परबत्ता में उनके आदेश की अनदेखी हो रही है. प्रखंड के मेहदीपुर में भी आदेश अनदेखी की बानगी देखने को मिल जाती है. यहां के ज्ञान दयाकांत सिंह प्राथमिक विद्यालय परिसर में वर्ष 2010 में ही आंगनबाड़ी केन्द्र का भवन ग्रामीण कार्य विभाग से 4 लाख 70 हजार की राशि से बन कर तैयार है. किन्तु अब तक इसमें केन्द्र का संचालन नहीं कर भाड़ा के नाम पर सरकारी राशि ली जा रही है. यही हाल माधवपुर पंचायत के मुरादपुर गांव स्थित मध्य विद्यालय मुरादपुर परिसर में आंगनबाडी केन्द्र भवन 2010 में बन कर तैयार है. लेकिन अभितक यहां केन्द्र का संचालन नहीं किय जा रहा है. वहीं कबेला पंचायत के संस्कृत उच्च विद्यालय डुमरिया खुर्द परिसर में वर्षो से आंगनबाड़ी केन्द्र का भवन बनकर तैयार हैं किन्तु आज तक इसमें केन्द्र का संचालन नहीं हो रहा है. ऐसे बहुत से इदाहरण हैं जहां पर आंगनबाड़ी केन्द्र भवन बनकर तैयार है लेकिन वहां पर केन्द्र का संचालन नही किया जा रहा है. जिस कारण सरकार को लाखों रुपये की क्षति हो रही है.■

– गीता कुमार

झारखंड

> मुख्यमंत्री ने ऊर्जा विभाग के साथ आज राज्य में बिजली के जेनरेशन, ट्रांसमिशन एवं डिस्ट्रीब्यूशन के संबंध में विस्तृत समीक्षा की. उन्होंने विगत तीन दिनों से रांची में बिजली आपूर्ति की खराब स्थिति पर जानकारी मांगी. लाईटनिंग के कारण हटिया ग्रिड के खराब होने की जानकारी दिए जाने पर इन्होंने कहा कि लाईटनिंग की समस्या पूरानी है समाधान आपको निकालने हैं. चौदह साल बीत चुके हैं अब तक ग्रिड के लाईटनिंग प्रोटेक्शन की दिशा में कार्य क्यों नहीं हो सका.

रघुबर राज में मोदी की छाया

मंगलानंद

झारखंड के विधानसभा सत्र के पहले दिन नव निर्वाचित 75 विधायक विधानसभा पहुंचे. इनमें 35 विधायक पहली बार चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे. सत्र के पहले दिन नये विधायक काफी उत्साहित थे. किसी ने विधानसभा की चौखट पर मत्था टेका, तो कई विधायकों ने झारखंड के विकास को लेकर संकल्प लिया. नये विधायकों में से कुछ विधायकों ने अपना अनुभव पत्रकारों से भी शेयर किया. प्रोटेम स्पीकर स्टीफन मरांडी ने विधायकों के शपथ ग्रहण की प्रक्रिया पूरी करायी. लगभग एक घंटे के अंदर 76 विधायकों ने शपथ ली. अनुपस्थित रहने की वजह से पांच विधायक शपथ नहीं ले पाये. झारखंड विधानसभा में पहली बार राज पालिवार ने मैथिली में शपथ ली. वहीं, जय प्रकाश वर्मा ने

चिकित्सा भवन के निर्माण के साथ ही साथ वहां चिकित्सा सुविधा आमजनों को देने के लिए अन्य व्यवस्थाओं की भी तैयारी रहनी चाहिए. उन्होंने कहा कि ऐसी अनेक शिकायतें मिल रही है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बंद रहते हैं, चिकित्सक अनुपलब्ध हैं, दवाएं समाप्त हो चुकी है. ऐसी व्यवस्था से जनता को स्वास्थ्य सुविधा देना संभव नहीं है. विभाग यह आकलन स्वयं करें कि कमियां कहां हैं एवं इन कमियों का निराकरण भी वह स्वयं निकालें. हर कार्य के लिए विभाग समय सीमा स्वयं निर्धारित करें एवं समयबद्ध तरीके से कार्य करें. जनता को स्वास्थ्य सुविधा चाहिए एवं सरकार को परिणाम चाहिए.

अंगरेजी में शपथ ली. उनके अलावा पांच विधायकों ने संथाली और दो विधायकों ने बांग्ला में शपथ ली. सबसे पहले मुख्यमंत्री रघुबर दास ने पद और गोपनीयता की शपथ ली. इसके बाद मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा, संसदीय कार्य मंत्री सीपी सिंह, मंत्री चंद्र प्रकाश चौधरी, मंत्री लुईस मरांडी, प्रदीप यादव, आलमगीर आलम, दिनेश उरांव ने शपथ ली. विलंब से आने के कारण पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बीच में शपथ दिलायी गयी. उनके बाद क्रमानुसार विधायकों ने शपथ ली. विधायकों के शपथ ग्रहण के बाद विधानसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गयी.

झारखंड में रघुबर सरकार ने सभी सुस्त पड़े विभागों के कामों की समीक्षा शुरू की. इस क्रम में मुख्यमंत्री रघुबर दास ने प्रोजेक्ट भवन स्थित अपने सभा कक्ष में स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा करते हुए कहा कि स्वास्थ्य सेवा आपात सेवा है, इसमें किसी तरह की कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. जनता चिकित्सा के लिए इंतजार नहीं कर सकती. गरीब जनता को इलाज चाहिए, दवाएं चाहिए. अत: यह सुनिश्चित करें कि इसमें कोई विलंब न हो. मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग के तहत बन रहे अस्पताल भवनों तथा चिकित्सकों एवं दवाओं की उपलब्धता के संबंध में विस्तृत समीक्षा की. उन्होंने कहा कि राज्य में जिन अस्पताल भवनों का निर्माण हो चुका है, उन्हें शीघ्र चालू कराएं. चिकित्सा भवन के निर्माण के साथ ही साथ वहां चिकित्सा सुविधा आमजनों को देने के लिए अन्य व्यवस्थाओं की भी तैयारी रहनी चाहिए. उन्होंने कहा कि ऐसी अनेक शिकायतें मिल रही है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बंद रहते हैं, चिकित्सक अनुपलब्ध हैं, दवाएं समाप्त हो चुकी है. ऐसी व्यवस्था से जनता को स्वास्थ्य सुविधा देना संभव नहीं है. विभाग यह आकलन स्वयं करें कि कमियां कहां हैं एवं इन कमियों का निराकरण भी वह स्वयं निकालें. हर कार्य के लिए विभाग समय सीमा स्वयं निर्धारित करें एवं समयबद्ध तरीके से कार्य करें. जनता को स्वास्थ्य सुविधा चाहिए एवं सरकार को परिणाम चाहिए. मुख्यमंत्री ने कहा कि चिकित्सकों के रिक्त पदों को शीघ्र भरा जाए. भारत सरकार द्वारा प्राप्त राशि के व्यय की स्थिति के संबंध में अब तक मात्र 50 प्रतिशत व्यय होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि व्यवस्था में शीघ्र सुधार की जाए. जनता की भलाई की सोच बनाएं. राशि का सदुपयोग होना चाहिए एवं विभाग यह सुनिश्चित करें कि राशि लैप्स न होने पाए. उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि अन्य विकसित राज्यों में स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे कार्य रहा है, इसका अध्ययन करें और अपने राज्य की स्वास्थ्य सेवा में उसके अनुसार सुधार लाएं.

स्वास्थ्य सेवा सीधे–सीधे जनता से जुड़ी है, अन्य राज्यों की बेहतर व्यवस्था को अपने राज्य में लागू करें. उन्होंने कहा कि तमिलनाडु एवं राजस्थान में राज्य सरकार द्वारा उच्च कोटि की स्वास्थ्य सुविधाएं दी जा रही हैं, स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारी इन राज्यों में जाकर वहां के व्यवस्था का अध्ययन करें एवं तदनुसार प्रस्ताव दें. मुख्यमंत्री ने पीपीपी मोड पर अस्पतालों को चलाने के संबंध में भी स्वास्थ्य विभाग से जानकारी मांगी. इस संबंध में भी उन्होंने अन्य राज्यों की व्यवस्था का अध्ययन करने का निदेश दिया. बैठक में अपर मुख्य सचिव बीके त्रिपाठी, प्रधान सचिव वित्त राजबाला वर्मा, निदेशक प्रमुख डॉ. सुमंत मिश्रा समेत स्वास्थ्य विभाग के वरीय पदाधिकारीगण उपस्थित थे. इसके बाद ऊर्जा विभाग की समीक्षा करते हुए कहा कि राजधानी रांची में चौबीसों घंटे अबाध बिजली की आपूर्ति व्यवस्था सुनिश्चित की जाए. विभाग अपनी कार्य योजनाएं तैयार करें, प्राथमिकता तय करें और समयबद्ध तरीके से अपनी कार्य योजनाओं को धरातल पर उतारें.

मुख्यमंत्री ने ऊर्जा विभाग के साथ आज राज्य में बिजली के जेनरेशन, ट्रांसमिशन एवं डिस्ट्रीब्यूशन के संबंध में विस्तृत समीक्षा की. उन्होंने विगत तीन दिनों से रांची में बिजली आपूर्ति की खराब स्थिति पर जानकारी मांगी. लाईटनिंग के कारण हटिया ग्रिड के खराब होने की जानकारी दिए जाने पर इन्होंने कहा कि लाईटनिंग की समस्या पूरानी है समाधान आपको निकालने हैं. चौदह साल बीत चुके हैं अब तक ग्रिड के लाईटनिंग प्रोटेक्शन की दिशा में कार्य क्यों नहीं हो सका. मुख्यमंत्री ने राज्य में ग्रामीण विद्युतिकरण की समीक्षा करते हुए कहा कि गांव–गांव तक विद्युत आपूर्ति होनी चाहिए. गांववालों को बिजली चाहिए और यह व्यवस्था करना हमारा दायित्व है. गांवों तक तीन फेज विद्युत लाईन लगाएं एवं सभी ग्रामीणों को मुफ्त कनेक्शन दें. इसमें एपीएल, बीपीएल सभी को सम्मिलित किया जाए. उन्होंने कहा कि किसानों को कम से कम छह घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाए. इस दिशा में तिलका मांझी, कृषि पंप योजना को मूर्त रूप दें. इसे अगले वित्तीय वर्ष की योजना में निश्चित रूप से समाहित किया जाए. सौर ऊर्जा की व्यवस्था के संबंध में उन्होंने कहा कि जिन जगहों पर ऊसर भूमि है एवं जहां तेज धूप है इन क्षेत्रों में सौर ऊर्जा को वैकल्पिक ऊर्जा के रूप में अपनाया जा सकता है. इस हेतु विभाग अग्रतर कार्रवाई सुनिश्चित करें. समीक्षा के क्रम रिसोर्स गैप की जानकारी दिए जाने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि रिसोर्स गैप कम करना विभाग की जिम्मेदारी है इसके लिए चेकस्लिप तैयार करें. समस्याएं तभी स्पष्ट होंगी. समस्याओं की जानकारी नहीं होने पर विभाग समाधान के विषय में कैसे सोचेगा.■

feedback@chauthiduniya.com

गया

नक्सलियों के निशाने पर मोबाइल टावर

सुनील सौरभ

एक लंबे अंतराल के बाद पुन: प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी ने अपना निशाना संचार सेवा को बनाया है. जब मोबाइल फोन का ज़माना नहीं आया था, तब नक्सली आवागमन की सुविधा के लिए बनाये जाने वाले सड़क, पुल–पुलिया को निशाना बनाते थे. नक्सली बिहार–झारखंड के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में आवागमन की सुविधा के लिए किये जाने वाले कार्यों पर रोक लगा देते थे. निर्माण कंपनियां भी कार्य छोड़कर भागने लगी थीं. लेकिन जबसे मोबाइल फोन का ज़माना आया और ग्रामीण क्षेत्रों में भी संचार क्रांति का प्रभाव पड़ा तो इससे नक्सलियों को भी परेशानी झेलनी पड़ी. नक्सलियों की गतिविधि पर सुरक्षा बलों की कड़ी निगरानी होने लगी. सुरक्षा बलों को इनकी हर गतिविधि की जानकारी मिलने लगी. सैकड़ों नक्सली मारे गये. सुरक्षा बलों से मुठभेड़ होने लगी. नतीजा हुआ कि नक्सली ग्रामीण क्षेत्रों मे लगाये गये मोबाइल टावरों को जलाने लगे, नष्ट करने लगे. लेकिन पिछले कुछ वर्षों से नक्सलियों ने मोबाइल टावरों को अपने निशाने से अलग रखा था. गत 28 दिसंबर 2014 को भाकपा माओवादी ने झारखंड के चाईबासा में बिहार–झारखंड स्पेशल एरिया कमेटी के सदस्य संजय गंझू को गत 12 दिसंबर 2014 को गिरफ्तार किये जाने के ख़िलाफ बिहार–झारखंड बंद का आह्वान किया था. इस दौरान मगध के जहानाबाद–गया जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित चार मोबाइल टावरों को फूंक दिया. इससे उक्त ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल फोन सेवा ठप हो गई है. 28 दिसंबर 2014 की रात नक्सलियों ने गया जिले के टिकारी अनुमंडल के मऊ ओपी, शेरघाटी अनुमंडल के बाराचट्टी थाना क्षेत्र के महूआईन गांव तथा जहानाबाद जिले के पारसबिगहा थाना क्षेत्र के लाखापुर गांव मे

लगे मोबाइल टावरों को फूंक दिया. बाराचट्टी के महुआईन गांव में भारत संचार निगम लिमिटेड और एयर सेल के मोबाइल टावर के पास पचास से अधिक संख्या में पहुंचे हथियार बंद दस्ते ने मोबाइल टावर को ब्लास्ट कर उड़ा दिया. इसके बाद से आसपास के ग्रामीणों में दहशत व्याप्त है. इसी रात टिकारी के मऊ ओपी के अन्तर्गत लोहानीपुर गांव में एयरटेल के टावर को माओवादियों ने डीजल छिड़क कर आग के हवाले कर दिया. वहीं दूसरी ओर नक्सलियों ने अपने बिहार झारखंड बंद को सफल बनाने के लिए उसी रात जहानाबाद जिले के पारसबिगहा थाना क्षेत्र के लाखापुर गांव में करीब दो दर्जन की संख्या में पहुंचे हथियार बंद नक्सलियों ने मोबाइल टावर के गार्ड को बंधक बना टावर में आग लगा दी. टावरों को फूंके जाने के दौरान नक्सलियों ने सभी स्थानों पर अपना पर्चा छोड़ा. इसमें कहा गया था कि भाकपा माओवादी की बिहार–झारखंड स्पेशल एरिया कमेटी के सदस्य संजय गंझू की गिरफ्तारी के ख़िलाफ बिहार–झारखंड बंद को सफल करें. इसमें लोगों से अपील की गयी थी कि संजय गंझू को चाईबासा पुलिस द्वारा 12 दिसंबर 2014 को गिरफ्तार कर गोली मारकर हत्या करने के प्रयास के ख़िलाफ व्यापक जनता सशस्त्र जनसंघर्ष को तेज करें. हालांकि इन सभी घटनाओं के बाद पुलिस घटना स्थल पर पहुंची. लेकिन घटना को अंजाम देने वाले किसी नक्सली को गिरफ्तार नहीं कर सकी है. मगध के ग्रामीण क्षेत्रों में माओवादियों की कार्रवाई से दहशत व्याप्त है हालांकि पिछले कुछ महीनों से नक्सलियों ने मोबाइल टावरों व स्कूलों को निशाना बनाना छोड़ दिया था. लेकिन 2014 की समाप्ति के अंतिम दो दिनों में एक साथ चार टावरों में आग लगाने की घटनाओं से सवाल उठने लगा है कि क्या नक्सली पुन: पुराने ढर्रे पर लौट रहे हैं?■

feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया
हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार
19 जनवरी–25 जनवरी 2015
Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2015-17, RNI No. DELHIN/2009/30467

भ्रष्टाचार उजागर करने वाली समाजसेवी को धमकियां मिल रही हैं

लोकायुक्त की जांच में सच्चाई सामने आ रही है

दीनबंधु कबीर

उत्तर प्रदेश के खनन मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति के भ्रष्टाचार की कहानी में कई रोचक मोड़ सामने आ रहे हैं. खनन मंत्री का भ्रष्टाचार उजागर करने वाले ओमशंकर द्विवेदी ने अचानक नाटकीय तरीके से अपनी शिकायत वापस ले ली. तब तक मामला लोकायुक्त के समक्ष पेश हो चुका था और लोकायुक्त की जांच की औपचारिकताएं भी शुरू हो चुकी थीं. शिकायत वापस लेने पर समाजसेवी नूतन ठाकुर ने खनन मंत्री के साथ-साथ ओमशंकर द्विवेदी की मिलीभगत के खिलाफ भी लोकायुक्त से शिकायत की और मोर्चा खोल दिया.

खनन मंत्री के खिलाफ मोर्चा खोलते ही सामाजिक कार्यकर्ता नूतन ठाकुर को धमकियां मिलनी शुरू हो गईं. मंत्री की तरफ से उन्हें धमकियां देने वालों में पत्रकार भी शामिल हैं. ऐसे एक पत्रकार के खिलाफ लखनऊ पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही. सही तरीके से एफआईआर भी नहीं लिखी गई. जबकि लोकायुक्त भी यह शिकायत कर चुके हैं कि खनन मंत्री की तरफदारी में उनके पास भी किसी पत्रकार का फोन आया था. नूतन ठाकुर को फोन करने वाले कथित पत्रकार ने तो उन्हें प्रजापति मामले से दूर रहने की सख्त हिदायत दी. खुद को टीवी चैनल का पत्रकार बताने वाले उस व्यक्ति ने उन्हें फोन कर धमकियां भी दीं. नूतन ठाकुर ने गोमतीनगर थाने में तहरीर दी, पर कोई एफआईआर नहीं लिखी गई है. थाने के एसओ जहीर खान ने कहा कि सर्विलांस के जरिये नंबर के बारे में पड़ताल की जा रही है. मामले की तस्दीक करने के बाद ही एफआईआर दर्ज की जाएगी. नूतन ठाकुर का कहना है कि उन्हें और उनके आईपीएस पति अमिताभ ठाकुर को टेलीफोन पर दी गई धमकी में पुलिस की भी मिलीभगत है. इसी वजह से गोमतीनगर थाने में पूरी तरह गलत तरीके से सनहा दर्ज किया गया. नूतन ठाकुर के प्रार्थनापत्र के अनुसार यह मामला 506 आईपीसी तथा 66-ए आईटी एक्ट 2000 का संज्ञेय अपराध बनता है. लेकिन थाना प्रभारी ने इसे सिर्फ धारा 507 आईपीसी के असंज्ञेय अपराध में दर्ज किया. आम तौर पर धमकी देने पर 506 आईपीसी का अपराध होता है जबकि 507 आईपीसी तब होता है, जब कोई आदमी अपना नाम और पहचान छिपाने की सावधानी रख कर धमकी देता है. एक निश्चित मोबाइल नंबर (09389025750) से दी गई धमकी कभी भी अनाम नहीं मानी जा सकती, क्योंकि इसे आसानी से ट्रेस किया जा सकता है. संज्ञेय अपराध में पुलिस स्वयं विवेचना और गिरफ्तारी करती है जबकि असंज्ञेय अपराध में मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद ही विवेचना या गिरफ्तारी होती है. लिहाजा, पुलिस ने बड़े सोचे-समझे तरीके से इस मामले को असंज्ञेय धाराओं में दर्ज किया. अब नूतन ठाकुर ने लखनऊ के एसएसपी यशस्वी यादव से सही धाराओं में मुकदमा दर्ज कराने का औपचारिक रूप से आग्रह किया है. फोन पर धमकियां देने वाले कथित पत्रकार ने नूतन ठाकुर से कहा था कि खनन मंत्री गायत्री प्रजापति की सम्पत्ति और कथित अवैध प्लॉटिंग के बारे में उन्होंने लोकायुक्त को जो बातें कही हैं वे पूरी तरह गलत और निराधार हैं. पत्रकार ने यह भी कहा कि खनन मंत्री की अवैध सम्पत्ति और अवैध प्लॉटिंग के मामले में पड़ने से उन्हें दिक्कत होगी. इस व्यक्ति का नूतन ठाकुर के पास कई बार फोन आया. नूतन ठाकुर ने कहा, उसने मुझे कई प्रकार से समझाना चाहा कि मैं अवैध प्लॉटिंग या प्रजापति की सम्पत्ति मामले में न पड़ूं और इस मामले में उलझने से बचूं. सम्पत्ति वाले मामले में पड़ने से मुझे दिक्कत हो सकती है. उसने सधे अंदाज में यह भी कहा कि भैया (नूतन ठाकुर के पति) नौकरी में हैं, इस कारण उन्हें भी दिक्कत हो सकती है. उसने आखिर में यह भी कहा कि प्रजापति अमेठी में बहुत लोकप्रिय हैं और लोग उन्हें देवता की तरह पूजते हैं.

उल्लेखनीय है कि इसके पहले लोकायुक्त ने नूतन ठाकुर को खनन मंत्री से सम्बद्ध साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए तलब किया था. नूतन ठाकुर ने भूतत्व और खनन मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति के सीधे संरक्षण में उत्तर प्रदेश में अवैध खनन कराए जाने और इसके माध्यम से अवैध सम्पत्ति अर्जित किए जाने के बारे में दायर अपने परिवाद के सम्बन्ध में लोकायुक्त न्यायमूर्ति एन के मल्होत्रा के समक्ष साक्ष्य, अभिलेख व विशिष्ट तथ्य प्रस्तुत किए. पूरे प्रदेश के विभिन्न जिलों के कई स्थानों पर हो रहे भारी अवैध खनन को अलग-अलग चिन्हित कर लोकायुक्त को विस्तार से बताया गया. साथ ही विभिन्न प्रकार के वाहनों से की जा रही अवैध वसूली की दर और वसूली के तरीके के बारे में भी उन्हें बताय गया. लोकायुक्त को यह भी बताया गया कि 2013 में 26 जिलों के जिला मजिस्ट्रेट ने राज्य सरकार को पत्र द्वारा सूचित किया था कि बिना पट्टे के ही पुलिस और खनन विभाग की मदद से नदी किनारे अवैध खनन हो रहा है, लेकिन राज्य सरकार ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की. 2 जुलाई 2013 में गोंडा डीएम रोशन जैकब द्वारा नवाबगंज तथा तरबगंज तहसील में एसडीएम और तहसीलदार द्वारा अवैध खनन कराने के पत्र पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई. सोनभद्र के डीएम दिनेश कुमार सिंह द्वारा जारी आधिकारिक प्रेस नोट का भी हवाला दिया गया जिसमें उन्होंने कहा है कि जिले में अवैध खनन करने वालों की खैर नहीं है. इसके अलावा लोकायुक्त के समक्ष खनन मंत्री गायत्री प्रजापति द्वारा 65 वर्षीया शिव देवी की अमेठी स्थित जमीन की बाउंड्री तोड़ने के साक्ष्य रखे गए. साथ ही डायरेक्टर, एमजीए कोलोनाइजर के रूप में ग्राम हरिहरपुर में अवैध प्लॉटिंग के अभिलेख भी प्रस्तुत किए गए.

उल्लेखनीय है कि चौथी दुनिया ने पिछले अंक में उत्तर प्रदेश के खनन मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति के अकूत सम्पत्ति का स्वामी बनने की विकास-यात्रा की कहानी प्रकाशित की थी. राज्य मंत्री से कैबिनेट मंत्री बने गायत्री प्रसाद प्रजापति देखते ही देखते अरबपति हो गए. उनकी सम्पत्ति 500 गुणा से ज्यादा हो गई. गायत्री प्रसाद प्रजापति ने जब विधानसभा चुनाव में नामांकन दाखिल किया था तब उनकी सम्पत्ति 1.81 करोड़ रुपये थी. मंत्री बनने के बाद गायत्री ने 942.57 करोड़ रुपये की सम्पत्ति बनाई. लोकायुक्त से यह शिकायत करने वाले प्रतापगढ़ के ओम शंकर द्विवेदी और उनके वकील अजय प्रताप सिंह राठौर ने 1725 पन्ने साक्ष्य के रूप में संलग्न किए. लोकायुक्त से की गई शिकायत में खनन मंत्री की 943 करोड़ की सम्पत्ति की बात कही गई थी. लेकिन बाद में कई और सम्पत्तियों का ब्यौरा मिला. अब तक गायत्री की 1350 करोड़ की सम्पत्तियों की रजिस्ट्री मिल चुकी है. ओम शंकर द्विवेदी ने लोकायुक्त के यहां दाखिल शिकायत में इल्जाम लगाया कि खनन मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति ने पद का दुरुपयोग कर अपने सम्बन्धियों, ड्राइवर और नौकरों के नाम पर कई सौ करोड़ रुपये की सम्पत्ति जुटाई है. उनके परिवार वालों के नाम से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल में भी काफी जमीनें हैं. शिकायत पर लोकायुक्त ने जांच शुरू कर दी. लेकिन खनन मंत्री का घोटाला सार्वजनिक करने के बाद ओम शंकर द्विवेदी ने फौरन ही अपनी शिकायत वापस लेने की घोषणा कर दी. लेकिन तब तक तो गोली दग चुकी थी. हालांकि बाद में ओमशंकर द्विवेदी ने पलटते हुए कहा कि उन्होंने शिकायत वापस नहीं ली है. लेकिन लोकायुक्त का कहना है कि शिकायतकर्ता ओम शंकर द्विवेदी मुकर गया है. इसलिए अगली कार्यवाही के लिए वह नियमों का अध्ययन कर रहे हैं.

बहरहाल, अब तो विधिक तौर पर यह तथ्य दर्ज हो चुका कि वर्ष 2002 तक गायत्री प्रसाद प्रजापति अमेठी के ग्राम परसांवा के बीपीएल कार्ड धारक थे. 2012 में वे एपीएल कार्डधारक बने. गायत्री की सालाना आय 24 हजार रुपये थी. बावजूद इसके उनकी कम्पनियों व परिवार के सदस्यों के मालिकाना अधिकार वाली कम्पनियों ने कुछ अरसे में 105 भूखंडों की खरीद-फरोख्त की. मंत्री के परिवारिक सदस्यों के पास इंडीवर, फार्च्युनर, बीएमडब्लू जैसी 11 कीमती गाड़ियां हैं. लाखों के हीरे, सोने व चांदी के गहने हैं. लखनऊ के आलमबाग के प्रजापति भवन की अस्थाई और अमेठी की मूल निवासी श्रीमती गुड्डा ने मंत्री के कथित ड्राइवर रामराज के पक्ष में एक रजिस्टर्ड मुख्तारनामा किया है, जिसमें उसे देशभर में उनके नाम से सम्पत्ति खरीदने और बेचने का अधिकार दिया गया है. गुड्डा खुद एपीएल कार्ड धारक हैं. आरोप यह भी है कि गुड्डा जिस प्रजापति भवन में रहती हैं, उसके कर्ताधर्ता मंत्री गायत्री प्रजापति ही हैं और गुड्डा उनकी विश्वसनीय हैं. ओमशंकर द्विवेदी ने सूचना के अधिकार के जरिये प्रजापति परिवार की 1350 करोड़ रुपये की सम्पत्ति के दस्तावेज जुटाने का दावा किया था, जिनमें लखनऊ सदर, मेरठ, मोहनलाल गंज, फतेहपुर में खरीदी गई सम्पत्तियों की रजिस्ट्री भी शामिल है. बसपा के पूर्व मंत्री बाबूलाल कुशवाहा का फतेहपुर स्थित इंजीनियरिंग कॉलेज भी प्रजापति ने खरीदा है. प्रजापति का ड्राइवर रामराज 37 करोड़ रुपये की सम्पत्ति का मालिक है. इसी तरह दूसरे ड्राइवर राम सहाय के पास सात करोड़ 80 लाख रुपये की सम्पत्ति है. बेटे अनुराग के नाम पर छह करोड़ 50 लाख रुपये की सम्पत्ति है. दूसरे बेटे अनिल के पास करीब तीन करोड़ 48 लाख रुपये की सम्पत्ति है, जिसकी जायदाद की कीमत 32 करोड़ 18 लाख रुपये है. इसी तरह भाई, पत्नी और कम्पनियों के नाम पर बेहिसाब सम्पत्ति है. विकास वर्मा कम्पनियों का कामकाज संभालता है. ■

feedback@chauthiduniya.com

नाबालिग बेटे कई कम्पनियों के निदेशक, नोटिस जारी

प्रदेश के खनन मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति के दोनों नाबालिग बेटे, अनिल और अनुराग दर्जन भर कंपनियों में निदेशक हैं. लोकायुक्त जांच के दौरान कंपनी सेक्रेटरी की रिपोर्ट से यह खुलासा हुआ है. 10 साल के अनुराग प्रजापति 24 दिसम्बर तक अपनी उम्र से ज्यादा 12 कंपनियों के निदेशक थे. 13 वर्ष के अनिल 11 कंपनियों को निदेशक हैं. गायत्री प्रजापति के खिलाफ जांच कर रहे लोकायुक्त ने कंपनियों की पड़ताल के लिए कंपनी सेक्रेटरी की मदद ली. कंपनी सेक्रेटरी की रिपोर्ट में कहा गया कि गायत्री प्रसाद प्रजापति के बड़े पुत्र अनिल प्रजापति 11 कंपनियों के निदेशक हैं. इन कंपनियों में लाइफ क्योर मेडिकल एंड रिसर्च सेंटर, सुभांग एक्सपोर्ट, डीसेंट कंस्ट्रक्टर दया बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड, एक्सेल विलटेक, कान्हा बिल्डवेल, एमजीए हास्पिटैल्टी, एमएसए इंफ्रावेंचर, एमजीएम एग्रोटेक, एमएसजी रियलचर और एमएजीएस इंटरप्राइजेज हैं. गायत्री के छोटे बेटे अनुराग 24 दिसंबर 2014 तक 12 कंपनियों के अलावा एमजीए कॉलोनाइजर के भी निदेशक थे, लेकिन इसके बाद उन्होंने पिछले तारीखों में छह कंपनियों के निदेशक पद से त्याग पत्र दे दिया. खनन मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति की पत्नी, पुत्रों, भाइयों, महिला मित्र गुड्डा देवी और ड्राइवर रामराज को भेजी गई नोटिस उनके लोकायुक्त के दफ्तर में वापस आ चुकी है. गायत्री की पत्नी और पुत्रों को दोबारा उनके गांव और पार्क रोड स्थित आवास के पते पर नोटिस भेजी गई थी. अब उन्हें एक बार फिर नोटिस भेजी गई है. इस बार नोटिस पुलिस के जरिये भेजी जा रही है. साथ ही मंत्री की महिला मित्र गुड्डा देवी को भी दूसरी नोटिस उनके सुल्तानपुर स्थित मूल पते पर भेजी गई है. लोकायुक्त ने उनके साथ गायत्री प्रसाद प्रजापति के चारों भाइयों को भी नोटिस जारी की है. ■

उत्तर प्रदेश की खबरें इंटरनेट पर पढ़ने के लिए www.up.chauthiduniya.com लॉगऑन करें.

www.chauthiduniya.com चौथी दुनिया

सपा सरकार नहीं होने दे रही थी छात्र संघ का चुनाव

राज्यपाल ने चुनाव का खोला रास्ता

दीनबंधु कबीर

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जिस मसले को अर्से से लटकाए रखा था, उसे राज्यपाल राम नाईक ने एक झटके में हल कर दिया. प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति राज्यपाल राम नाईक ने वर्षों से लम्बित छात्र संघ चुनाव का रास्ता साफ कर दिया. अब छात्र संघों के चुनाव होंगे. कुलाधिपति ने नए सत्र से छात्रसंघ चुनाव कराने के लिए सारी बाधाएं दूर करने के निर्देश दिए हैं. लिंगदोह समिति की सिफारिशों के अनुरूप चुनाव का रास्ता निकाला जा रहा है. लखनऊ विश्वविद्यालय ने लिंगदोह समिति की सिफारिशों को आधार बनाकर अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कराने पर सहमति पहले से दे रखी है.

लखनऊ विश्वविद्यालय ने 25 नवम्बर को शासन के साथ हुई बैठक में अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कराने के पक्ष में बात कही थी. विश्वविद्यालय ने एक से अधिक कैंपस और अधिक छात्रसंख्या वाले संस्थानों के लिए लिंगदोह समिति की अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की सिफारिश का हवाला दिया था. विश्वविद्यालय ने यह भी तर्क दिया था कि प्रत्यक्ष चुनाव से अकादमिक गतिविधियों में व्यवधान होगा. पिछले बार हुए चुनावों में दस फीसदी से अधिक छात्रों के वोट कभी नहीं पड़े. ऐसे में पूरे छात्र समुदाय का प्रतिनिधित्व चुनावों के दौरान नहीं होगा. जबकि अप्रत्यक्ष प्रणाली में ज्यादातर छात्रों की हिस्सेदारी की सम्भावना जताई जा रही है.

नए सत्र से छात्रसंघ चुनाव का रास्ता साफ हुआ तो लखनऊ विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कॉलेज में भी चुनाव के रास्ते खुले हो गए. लखनऊ विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कॉलेज में सीधे चुनाव के लिए परोक्ष चुनाव का रास्ता अपनाना पड़ सकता है. जहां ज्यादा कॉलेजों में बड़ी संख्या में छात्र पढ़ते हैं. कुछ कैंपस में छात्रों की संख्या लखनऊ विश्वविद्यालय से ज्यादा है. ये कॉलेज भी लखनऊ विश्वविद्यालय की आचार संहिता का पालन करेंगे. अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली पर छात्र संगठनों को ऐतराज है. समाजवादी छात्रसभा की विश्वविद्यालय ईकाई के अध्यक्ष अनिल यादव मास्टर का कहना है कि विश्वविद्यालय अपने मन से नीतियां बना रहा है. चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से ही होना चाहिए. अप्रत्यक्ष प्रणाली से एजेंडे बैठाए जाते हैं. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की प्रदेश कार्यसमिति के सदस्य अनुराग तिवारी भी कहते हैं कि लखनऊ विश्वविद्यालय प्रशासन का तरीका लोकतंत्र का मजाक है. शासन की बैठक में लखनऊ विश्वविद्यालय को ऐसा प्रस्ताव ही नहीं रखना चाहिए था. ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष सुधांशु बाजपेई भी इसे लोकतंत्र की आवाज दबाने वाला तरीका बताते हैं.

बहरहाल, राजभवन में कुलपतियों-कुलसचिवों की बैठक में राज्यपाल सह कुलाधिपति ने छात्र संघ का चुनाव कराने का निर्देश दिया और कहा कि परीक्षाओं में व्यवधान न हो, इसलिए अगले शैक्षिक सत्र में अगस्त में लिंगदोह समिति की सिफारिशों के अनुसार छात्रसंघ चुनाव कराए जाएं. बैठक में यह भी स्पष्ट किया गया कि चिकित्सा और प्राविधिक विश्वविद्यालयों में छात्रसंघ चुनाव कराने पर कोई रोक नहीं है. बैठक में गोरखपुर स्थित दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. अशोक कुमार ने सुझाव दिया कि राजस्थान में पिछले पांच वर्षों से हर साल एक ही दिन पूरे प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में छात्रसंघ चुनाव कराए जा रहे हैं. विश्वविद्यालय अपने यहां चुनाव कराते हैं जबकि कॉलेजों में इसके आयोजन की जिम्मेदारी उच्च शिक्षा निदेशक की होती है. इस पर राज्यपाल राम नाईक ने सभी विश्वविद्यालयों को राजस्थान मॉडल का अध्ययन करने को कहा. यदि उपयुक्त पाया गया तो प्रदेश में भी इसे अपनाया जा सकता है.

छात्र संघ का चुनाव पिछले लम्बे अर्से से लम्बित है. मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और उनकी समाजवादी पार्टी छात्र संघों का चुनाव नहीं होने दे रही है. जबकि सत्ता में आने के साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों तथा कॉलेजों में छात्रसंघ की बहाली कर लिंगदोह समिति की सिफारिशों के आधार पर चुनाव कराने का शासनादेश जारी किया था. 2012 में ही मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने निर्देश दिया था कि आगामी शैक्षणिक सत्र में छात्र संघ के चुनाव करा लिए जाएं. अखिलेश सरकार के इस फैसले के बाद शासन ने स्नातक स्तर पर चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार की उम्र 17 से 22 वर्ष के बीच, परास्नातक छात्रों के लिए अधिकतम आयु 25 साल तथा शोध छात्रों की उम्र ज्यादा से ज्यादा 28 साल निर्धारित कर दी थी. छात्रसंघों में आपराधिक तत्वों की घुसपैठ रोकने के लिए किसी तरह के मामले में अभियुक्त बनाए गए छात्र-छात्राओं के चुनाव लड़ने पर पाबंदी भी लगाई गई थी. इसके अलावा प्रत्याशी बनने वाले छात्रों के लिए सम्बन्धित विश्वविद्यालय या कॉलेज में 75 प्रतिशत या उससे ज्यादा उपस्थिति जरूरी होने की शर्त भी लगाई गई थी. यह याद रखें कि लिंगदोह समिति ने 2006 में छात्र संघ चुनाव सुधार के लिए केन्द्र सरकार को अपनी सिफारिशें दी थीं. प्रदेश में उस समय भी मुलायम सिंह यादव के मुख्यमंत्रित्व वाली सपा की सरकार थी, लेकिन मुलायम सरकार ने भी उस समय उन सिफारिशों पर अमल नहीं किया था. अखिलेश सरकार के शासनादेश के मुताबिक छात्र संघ के चुनाव की प्रक्रिया 10 दिनों में पूरी कर ली जानी थी. चुनाव हर साल होने थे और शैक्षणिक सत्र शुरू होने की तारीख के यथासम्भव छह से आठ हफ्ते के बीच इन चुनावों को सम्पन्न कराना था. अखिलेश यादव सरकार के शासनादेश से उत्साहित लखनऊ विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्र संघ चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) के उपयोग की कवायद भी शुरू कर दी थी. लेकिन अखिलेश सरकार का यह शासनादेश ढ़ाक के तीन पात ही साबित हुआ.

मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने छात्र संघ के चुनाव को लेकर खूब राजनीति की. चुनाव की घोषणा से उत्साहित होकर छात्र नेताओं ने जो पोस्टर-बैनर लगाए थे उस पर मुख्यमंत्री खूब नाराज हुए और उसे हटाने का फरमान जारी कर दिया. मुख्यमंत्री अपना ही शासनादेश भुला कर फिर लिंगदोह कमेटी की सिफारिशों के अनुरूप चुनाव कराने को कह रहे हैं, लेकिन चुनाव होने नहीं दिया. मुख्यमंत्री ने छात्रसंघ चुनाव की बहाली की घोषणा के बाद विभिन्न स्थानों पर हुए कथित बवालों को आधार बनाया और छात्रसंघ चुनाव के नियम और सख्त किए जाने की हिदायत दे डाली. अखिलेश यादव की ताजा हिदायतों के बाद फिर लखनऊ विश्वविद्यालय प्रशासन ने सारी तैयारियां करके 15 अक्टूबर 2012 को छात्र संघ का चुनाव कराने का निर्णय लिया, लेकिन शासन ने इसकी मंजूरी नहीं दी. ■

लिंगदोह समिति की यह हैं प्रमुख सिफारिशें

- उम्र सीमा स्नातक (यूजी) में 22 वर्ष, स्नातकोत्तर (पीजी) के लिए 25 वर्ष व शोध छात्र के लिए 28 वर्ष.
- चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम 75 प्रतिशत उपस्थिति जरूरी.
- चुनाव लड़ने के लिए नियमित छात्र होना जरूरी.
- आपराधिक रिकॉर्ड, मुकदमा, सजा या अनुशासनात्मक कार्रवाई पर चुनाव लड़ने से पाबंदी.
- एक प्रत्याशी का अधिकतम खर्च पांच हजार रुपये.
- छपे हुए पोस्टर, पैम्फलेट या प्रचार सामग्री के प्रयोग की अनुमति नहीं.
- प्रचार में लाउड स्पीकर, वाहन एवं जानवरों का प्रयोग प्रतिबंधित.
- छोटे कैंपस में सीधे प्रतिनिधि चुनने की व्यवस्था.
- एक से अधिक कैंपस या अधिक संख्या वाले कॉलेजों में अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव.

सियासत की दुकान पर बिकती स्वच्छता

अंशु दीनमणि

गंगा की सफाई के नारों के बीच गोमती नदीं कहीं खो गई है. लखनऊ के सांसद और देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने चुनाव जीतते ही कहा गोमती की सफाई जरूरी है. राजनाथ जब-जब लखनऊ आते हैं और उन्हें मौका मिलता है तो वे गोमती की स्वच्छता के मसले पर संजीदगी दिखाते हैं, लेकिन स्वच्छता के लिए कुछ ठोस होता नहीं है. मौजूदा राजनीतिक माहौल में स्वच्छता भी बिकाऊ माल हो गई है. केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों से वादा किया था कि गंगा की तरह ही गोमती भी साफ होगी. राजनाथ ने नदियों को देश की जीवन रेखा बताते हुए कहा था कि गंगा सफाई की तर्ज पर जल्द ही गोमती नदी को भी स्वच्छ और अविरल बनाया जाएगा. राजनाथ सिंह ने ये बातें लखनऊ विश्वविद्यालय के पास गोमती तट पर पर्यावरण स्वच्छता जागरूकता कार्यक्रम में कही थीं. उन्होंने कहा था कि भारत सरकार का मकसद देश को आर्थिक क्षेत्र के रूप में ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक क्षेत्र के रूप में भी विकसित करना है. इसके लिए नदियों की स्वच्छता और उसका अविरल बहाव जरूरी है. उन्होंने लखनऊ में कुड़िया घाट से लेकर लामार्टिनियर कॉलेज तक गोमती तट को उसी तरह सुंदर रूप से विकसित करने का वादा किया था जैसा अहमदाबाद में साबरमती तट को किया गया है. केंद्रीय जल संसाधन मंत्री उमा भारती ने भी कहा था कि तीन साल में ही गंगा निर्मल दिखने लगेगी और दस साल में गंगा को पूरी तरह साफ और अविरल बना लिया जाएगा. गंगा की तरह गोमती को भी स्वच्छ और निर्मल किया जाएगा. साध्वी ने कहा था कि गोमती सफाई के लिए भी सर्वेक्षण हो चुका है.

लेकिन असलियत क्या है. असलियत यह है कि गोमती नदी में लखनऊ का एक तिहाई से भी अधिक कचरा खुलेआम बहाया जाता है. इसमें न किसी को शर्म आती है और न किसी को डर लगता है. गोमती का प्रदूषण तकनीकी मानकों के मुताबिक चरम पर पहुंच चुका है. गोमती को साफ रखने के सारे उपक्रम चौपट हैं और जल निगम की प्रदूषण इकाई और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नाकारा हैं. गोमती प्रदूषण नियंत्रण इकाई ने तो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को पत्र लिखकर गोमती में किसी भी सुधार की संभावना को असंभव बताया है. सैकड़ों लीटर सीवर के अलावा लखनऊ परिक्षेत्र की छह डिस्टिलरी और पांच चीनी मिलें गोमती में अपना उच्छिष्ट धुआंधार डाल रही हैं, कोई देखने वाला नहीं है. लखीमपुर से लखनऊ के बीच पांच चीनी मिलें और छह डिस्टिलरी हैं. गोमती को साफ रखने में पूंजीपतियों की चीनी मिलें और डिस्टिलरीज़ दुश्मन का रोल अदा कर रही हैं, जिनके आगे सत्ता नतमस्तक है. एशिया का सबसे बड़ा भरवारा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट फेल है. इस पर सैकड़ों करोड़ रुपये बर्बाद किए जा चुके हैं.

गोमती की आत्मकथा

मैं गोमती हूं. कुछ लोग मुझे आदिगंगा के नाम से भी पुकारते हैं. इंद्र ने एक बार गौतम ऋषि का रूप धर कर उनकी पत्नी अहिल्या से छल किया था. कुपित गौतम ऋषि ने इंद्र और अहिल्या को श्राप दे दिया था. काफी अनुनय, विनय करने पर गौतम ऋषि ने श्राप मुक्ति के लिए इंद्र को मेरे तटों पर 1001 शिवलिंग स्थापित कर तपस्या करने को कहा था. इंद्र ने मेरे तटों पर शिवलिंगों की स्थापना कर तपस्या की तब कहीं जाकर उनको ऋषि के श्राप से मुक्ति मिल सकी. इंद्र को श्राप से मुक्ति मिल गई लेकिन मैं आज प्रदूषण, जलीय जीवों की हत्या, तटों पर की जा रही खेती से इस कदर घायल और व्याकुल हूं कि आज मुझे ही किसी भागीरथ की जरूरत है. मेरी यात्रा पीलीभीत के माधौटांडा कसबे के पास (गोमत ताल) फुलहर झील से शुरू होती है. पीलीभीत में उद्गम स्थल के अलावा त्रिवेणी बाबा आश्रम, उकोत्तरनाथ, शाहजहांपुर में सुनासिरनाथ (बंडा), बजरिया घाट, पन्नघाट, मंशाराम बाबा, भंजई घाट, मंझरिया घाट, लखीमपुर में सिरसाघाट, टेढ़ेनाथ बाबा, मढ़िया घाट, हरदोई में धोबियाघाट, प्राकृतिक जलस्रोत, हत्याहरण, नल दमयंती स्थल, सीतापुर में नैमिषारण्य, चक्रतीर्थ, ललिता देवी, अठासी कोस परिक्रमा, दधीचि आश्रम, मनोपूर्णा जल प्रपात, लखनऊ में चंद्रिका देवी मंदिर, कौडिन्य घाट, मनकामेश्वर मंदिर, संकटमोचन हनुमान मंदिर, बाराबंकी में महदेवा घाट, टीकाराम बाबा, सुल्तानपुर में सीताकुंड तीर्थ, धोपाप, प्रतापगढ़ में ढकवा घाट, जौनपुर में जमदग्नि आश्रम, वाराणसी में गोमती गंगा मिलन स्थल, मार्कंडेश्वर नाथ आदि आश्रम और तट हैं. मुझे सदानीरा बनाने में पीलीभीत में वर्षाती नाला, शाहजहांपुर में झुकना, भैंसी, तरेउना, लखीमपुर में छोहा, अंधराछोहा, सीतापुर में कठिना, सरायन, गोन, लखनऊ में कुकरैल, अकरद्दी, बाराबंकी में रेठ, कल्याणी, सुल्तानपुर में कादूनाला, जौनपुर में सई नदी का योगदान रहता है. 960 किलो मीटर का सफर तय कर बनारस गाजीपुर के बीच मार्कंडेय आश्रम के पास मैं गंगा मैया की गोद में विश्राम लेती हूं. अपनी कहानी सुनाते हुए मेरा मन बेहद आहत है. मेरा भविष्य मुझे चिंता में डाल रहा है. जिस मनुष्य के लिए मैं इतना सब करती हूं वह थोड़े लालच में मेरे घर आंगन में रहने वाले जीवों की हत्या कर रहे हैं. मुझमें गंदगी बढ़ती जा रही है. मेरे तट तक अतिक्रमण कर लिया गया है. खेतों में डाली जाने वाली जहरीली दवाओं का असर है कि मेरे घर में रहने वाले जंतु मरते जा रहे हैं. तटों के पेड़ पौधे बेरहमी से काटे जा रहे हैं. मैं उनकी करुण पुकार सुनकर भी कुछ नहीं कर पाती. लोग घरों में हवन आदि कराने के बाद राख, कागज, सूखे फूल आदि मेरे ऊपर फेंक देते हैं. लोग मुझे मां कहते हैं, क्या कोई अपनी मां के ऊपर भी गंदगी फेंकता है. गंदगी में मेरा दम घुटने लगा है. जहरीले पानी और कचरे से मेरे घर के जीव मर रहे हैं. पीलीभीत में जहां से मैं निकलती हूं वहां से शाहजहांपुर, लखीमपुर, हरदोई में कई जगह मुझे बांध दिया गया है. लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर से लेकर वाराणसी तक कारखानों का इतना गंदा पानी मिल चुका होता है कि मेरा अमृत समान पानी जहर बन चुका है. मैं जीवनदायिनी कैसे रह पाउंगी. तटों और जंगलों के पेड़ काटने से बारिश नहीं होगी तो मुझमें पानी कहां से आएगा, खेतों की सिंचाई कैसे होगी, मैं जिस वजह से छटपटा रही हूं वह आप क्यों नहीं सोचते? जब मेरी मौत हो जाएगी तब फिर सोचने से क्या होगा? क्या कोई भागीरथ नहीं है जो मुझे इस त्रासदी से बचा सके? कब पूरी होगी मेरी प्रतीक्षा?

-हरिओम त्रिवेदी

दौलतगंज सीवर ट्रीटमेंट प्लांट भी ठीक से काम नहीं कर रहा. नालों का पानी गोमती नदी में निर्बाध गति से बह रहा है. नदी में ज्यादा सिल्ट जमा हो जाने की वजह से इसकी ड्रेजिंग कराने का खाका खींचा गया था. 2001 में ही शासन के निर्देश पर इसका प्रस्ताव तैयार किया गया था. कोलकाता की स्वाति ड्रेजर को इसका ठेका भी दिया गया था. लेकिन पैसे की बंदरबांट में असली काम नहीं हुआ और कंपनी अपना काम बीच में ही छोड़ कर चली गई. गोमती साफ हुई नहीं और गोमती के घाटों के सौंदर्यीकरण का पैसा भी अधिकारियों-कर्मचारियों की जेब में चला गया. कुड़िया घाट के सौंदर्यीकरण का पहला खेप पूरा हुआ. लेकिन दूसरा खेप शुरू ही नहीं हुआ. इस बारे में दोषी अधिकारियों-कर्मचारियों से कोई पूछताछ करने की जरूरत भी नहीं समझी गई. गोमती की स्वच्छता बहाली के लिए प्रतिबद्ध समाजसेवी ऋद्धि किशोर गौड़ कहते हैं कि जब गोमती नदी ही साफ नहीं तो घाटों को साफ करके क्या होगा. गौड़ कहते हैं कि कुड़ियाघाट, लक्ष्मण झूला और शहीद स्मारक पार्क गोमती नदी के घाटों की शोभा तो बढ़ाते हैं, मगर उनकी सुंदरता का क्या मतलब जब साथ बहने वाली गोमती नदी ही नाले की तरह मैली हो. गोमती किनारे पर्यटन को बढ़ाने का सरकार का सपना तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक गोमती को प्रदूषणमुक्त कराने की ठोस कार्रवाई नहीं होगी. अन्यथा गोमती के घाटों के सौंदर्यीकरण पर करोड़ों खर्च करना व्यर्थ है. नदी के पानी को साफ रखने की पहल समाज के साथ-साथ सरकार को भी करनी होगी. नदी किनारे बसे गांवों और मोहल्लों में शौचालय की व्यवस्था करनी होगी, जिससे लोग नदी तट को गंदा न करें. इसके साथ ही प्रदूषण फैलाने वाली फैक्टरियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने होंगे.

पर्यावरण विशेषज्ञ बताते हैं कि कभी लखनऊ में 300 झीलें थीं, लेकिन उन्हें पाट कर कंक्रीट बिछा दिए गए. गोमती नदी भूमिगत और वर्षा जल के सहारे जीवित रही है. लेकिन शहर के जलस्रोत सूखने से इसे अब पानी नहीं मिल रहा. भूमिगत जलस्रोत में तेजी से गिरावट हो रही है. कभी गोमती नदी अपने साथ बालू और कंकर लेकर आती थी. बालू और कंकर की परतें जमा होते-होते भूजल का स्रोत बन जाती थीं. यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया थी. मगर अब नदी अपने साथ केवल गंदगी और कचरा बहाकर लाती है. इससे प्राकृतिक चक्र टूट गया और नदी का स्वास्थ्य खराब हो गया.

एक वैज्ञानिक अध्ययन बताता है कि गोमती नदी के पानी में अनगिनत जहरीले तत्व हैं. नैमिषारण्य, इटौंजा, गंगागंज, सुलतानपुर और जौनपुर तक गोमती नदी के जल के अध्ययन में जहरीले रासायनिक तत्व पाए गए. गोमती नदी में पाया गया अधिक आयरन जीवाणुओं को बढ़ाने में मददगार हो रहा है. गोमती नदी में मिला सल्फेट आंतों में जलन होने की समस्या बढ़ाता है. मर्करी होने के कारण गोमती का पानी पीने लायक नहीं रहा. गोमती के पानी में आर्सेनिक भी पाया गया है जो त्वचा के कैंसर का कारक है. इसके अलावा गोमती में पाया गया क्रोमियम भी त्वचा का कैंसर पैदा करता है.

गोमती नदी में प्राणलेवा रसायनों के कारण आए दिन मछलियों के मरने की तस्वीरें अखबारों में छपती रहती हैं. हजारों हजार मछलियां तड़प-तड़प कर मरती रहती हैं और अधिकारी कहते रहते हैं कि ऑक्सीजन की कमी के कारण मछलियां मर रही हैं. गोमती के कछुए समाप्त हो गए. गोमती अब केवल खतरनाक कीटाणुओं का घर बन कर रह गई है. ■

feedback@chauthiduniya.com

विवाद में स्वाद..!

कोर्ट ने बताया कौन असली टुंडे कबाबी, कौन नकली

सूफी यायावर

अपनी गौरवशाली ऐतिहासिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले लखनऊ की पहचान अदब, आदाब और कबाब से भी है. कोई भी हस्ती हो, लखनऊ पहुंचते ही उसे याद आता है लखनऊ का लाजवाब-कबाब. कबाब का नाम लें तो टुंडे का नाम बिकता है. हालांकि लखनऊ के कई और ठिकानों पर बढ़िया स्वाद वाले कबाब बनते हैं, लेकिन काकोरी कबाब और टुंडे कबाब का नाम भी स्वाद की तरह ही बिकता है. इधर कुछ दिनों से टुंडे का कबाब स्वाद के कारण नहीं बल्कि विवाद के कारण मशहूर होने लगा. टुंडे कबाब के नाम को लेकर इतने दावेदार खम ठोक कर सामने आ खड़े हो गए कि स्वाद ही कन्फ्यूज़ हो गया. हर गली नुक्कड़ पर आपको टुंडे कबाबी का बोर्ड लगा हुआ दिखने लगा और कबाब का स्वाद भी नुक्कड़ छाप होने लगा. फिर यह मामला अदालत पहुंच गया. वह भी लखनऊ नहीं, बल्कि दिल्ली की अदालत में. दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया और टुंडे कबाब अब विधिक शब्दावली में टीके हो गया. दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब टीके वाला कबाब ही असली टुंडे कबाब, बाकी सब नकली. अब देखना है कि टुंडे कबाब का स्वाद दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर टिक जाता है या इसका स्वाद फाइनल करने का रास्ता सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक जाता है.

फिलहाल, दिल्ली हाईकोर्ट ने ब्रैंड टीके को ही असली टुंडे कबाबी बताया है. इस फैसले के बाद प्रशासन ने फर्जी बोर्ड हटवाने शुरू कर दिए. टुंडे कबाबी के परिवार की तीसरी पीढ़ी के मोहम्मद उस्मान आखिरकार विरासत की कानूनी लड़ाई जीतने में कामयाब हो गए. दिल्ली हाईकोर्ट ने लखनऊ की पांच और रायबरेली की एक दुकान को नकली करार देते हुए उस्मान के ब्रैंड टीके को ही असली टुंडे कबाबी के परिवार का माना है. कोर्ट के आदेश पर लखनऊ में टुंडे कबाबी के नाम से चल रही फर्जी दुकानों के बोर्ड प्रशासन ने हटवा दिए. बीते कुछ साल में शहर के अलग-अलग हिस्सों में मामूली कबाब की दुकानों पर भी टुंडे कबाबी के नाम का इस्तेमाल शुरू हो गया था. इनमें से कुछ तो टुंडे कबाबी के ननिहाल से ताल्लुक रखने का दावा भी करते थे. मोहम्मद उस्मान का कहना है कि ये लोग बाहर से आने वाले पर्यटकों को निशाना बनाते थे, क्योंकि वे बोर्ड पर टुंडे कबाबी लिखा देखकर सैकड़ों साल पुराना जायका लेने वहां चले जाते थे. नकली टुंडे कबाबी जायके में कहीं ठहरते नहीं, लिहाजा, उनके पुरखों का नाम खराब हो रहा था. कई दूसरे शहरों में भी ऐसी दुकानें खुल गई थीं.

ऐसे ही एक दावेदार टुंडे कबाबी ने इस नाम पर कॉपीराइट का दावा भी ठोक दिया. तब बाकायदा कानूनी लड़ाई शुरू हो गई. उस्मान ने रिट दाखिल कर अदालत को बताया कि दावेदारों का असली टुंडे कबाबी से कोई संबंध नहीं है. साथ ही उन्होंने टुंडे के नाम का अवैध इस्तेमाल करने का केस भी दर्ज करवाया. 24 दिसम्बर 2014 को दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने फैसले में इन सभी आउटलेट पर टुंडे के नाम के इस्तेमाल को अवैध करार दे दिया. उस्मान बताते हैं कि टुंडे कबाबी और ग्रैंडसन ऑफ टुंडे कबाबी के नाम से आठ आउटलेट हैं. इनमें चौक और अमीनाबाद की दुकानें सबसे पुरानी हैं. इसके अलावा आलमबाग, कपूरथला, कानपुर रोड चुंगी, रहीमनगर, सहारागंज और रायबरेली रोड स्थित तेलीबाग में भी उनका आउटलेट है जहां टुंडे के कबाब का असली स्वाद मिलेगा. इसके अलावा लखनऊ में कोई भी आउटलेट टुंडे कबाबी से सम्बद्ध नहीं है. अब लखनऊ वाले टुंडे कबाब की कोई नकली फ्रेंचाइजी नहीं खोली जाएगी. मोहम्मद उस्मान ने कहा कि उनके दादा मुराद अली ने कबाब मसाले का नुस्खा उनके पिता रईस अहमद को दिया और अपने पिता से वह नुस्खा उन्हें मिला. उस्मान ने कहा, मेरे पास टुंडे का पेटेंट है, मैं पहले भी केस जीत चुका हूं. हमने लखनऊ के स्वाद को आगे बढ़ाया, पुरखों का नाम बढ़ाया, यही बहुत है. बताया जाता है कि टुंडे खानदान करीब 200 साल पहले भोपाल से लखनऊ आया था. ये लोग भोपाल के नवाब के बावर्ची थे. नवाब खाने के शौकीन थे लेकिन बुढ़ापे में नॉनवेज नहीं खा पाते थे. उनकी मांग पर मांस को बारीक पीस कर, मसाला मिलाकर ऐसा बनाया गया कि वो आसानी से खा सकें. स्वाद लोगों को ऐसा भाया कि देखते ही देखते यह मशहूर हो गया. कहते हैं कि टुंडे के कबाब में करीब 100 तरह के मसालों का इस्तेमाल किया जाता है, जिनमें कुछ मसाले इराक और अन्य देशों से भी आते हैं. हाजी मुराद अली का हाथ बचपन में पतंग उड़ाते हुए टूट गया था जिसे बाद में काटना पड़ा. वह दुकान पर बैठते थे और उन्हीं के कारण धीरे धीरे दुकान टुंडे कबाबी की दुकान के नाम से मशहूर होती चली गई. ■

लजीज कबाब का लाजवाब इतिहास

मांसाहार के शौकीन लोग या पाक कला के विशेषज्ञ बताते हैं कि कबाब जैसा कोई आइटम दुनिया में इतना मशहूर नहीं हुआ. अब तो कबाब इतना चल गया कि इसके तरह-तरह के प्रकार बनने लगे और यह दुनियाभर में छा गया. इसकी शुरुआत भले ही मध्य एशिया से हुई हो लेकिन अब क्या भारत और क्या अमेरिका-यूरोप और क्या सुदूर अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका, सब जगह कबाब का स्वाद मिल जाएगा. अफगानिस्तान में आपको भेड़ के गोश्त से बना चपली कबाब मिलेगा तो ईरान में कबाब कूबिदे और ग्रीस में सुअर के मांस से बना सोव्लाकी. हर देश में कबाब अपने अलग नाम से मिलेगा, लेकिन है तो कबाब ही. प्राचीन समय में सिपाही जंग के मैदान या लंबे सफर में मांस को तलवारों में फंसा कर आग पर भूनते थे. यह धीरे-धीरे सींक कबाब के नाम से मशहूर हो गया. फिर कीमे को चने और विभिन्न मसालों में मिला कर और तवे पर सेंक कर शामी कबाब का नाम दिया गया. भारत में कबाब का आगमन फारसी, मंगोल और अरबी सेनाओं और इन देशों के व्यापारियों के साथ हुआ. हिंदुस्तान में कबाबों पर जितने प्रयोग हुए, उतने कहीं नहीं हुए. अवध के नवाबों और उनके रईसों की तो मिसाल दी जाती है. उन्हें कबाब बनाने में महारत हासिल थी. ऐसे ही प्रयोग में काकोरी कबाब का भी जन्म हुआ. लखनऊ के कबाबों की बात हो तो टुंडे कबाबी का जिक्र जरूरी है. दुनिया भर में उनके कबाबों के चर्चे हैं. अब तो लखनऊ शहर में कई जगह टुंडे कबाब की शाखाएं हैं. लेकिन सबसे पुरानी दुकान के कबाबों का स्वाद और वहां का माहौल नायाब है. अकबरी गेट के पास एक-मीनारी मस्जिद के बगल वाली गली में टुंडे मियां की पुरानी रसोई है. वहां का गलावटी कबाब और कबाब के साथ शीरमाल या रुमाली के क्या कहने. उल्टे तवे का पराठा भी कबाब के साथ कम नहीं. लखनऊ में स्वादिष्ट गलावटी, शामी और सींक कबाब की अनगिनत दुकानें हो गई हैं. लखनऊ के कबाब केवल यूपी वालों के लिए ही नहीं, बल्कि देश-विदेश से यहां आने वाले हर किसी के स्वाद पर चढ़े हुए हैं. लखनऊ के कबाब केवल रईसों के दस्तरखान की शान नहीं रहे बल्कि वे अवाम के भी नाम हैं.

प्रधानमंत्री से कांग्रेस का सवाल

कालेधन की कब होगी घर वापसी

रेनू शर्मा

कालाधन के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में ठनी रार थमने का नाम नहीं ले रही है. जिस हथियार से भाजपा ने कांग्रेस को सत्ता से बाहर किया. उसी हथियार से कांग्रेस अब मोदी सरकार को निशाने पर ले रही है. केंद्र सरकार को काला धन वापस लाने और उसे जनता में बांटने का वादा याद दिलाने के लिए कांग्रेसी जोर शोर से सड़क पर उतरे और मोदी सरकार को घेरा. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं बाबा रामदेव ने पिछले लोकसभा चुनावों और इससे पहले देश की जनता से वादा किया था कि केंद्र में भाजपा की सरकार बनने के 100 दिन के अंदर विदेशों में जमा किये गए कालेधन को देश में वापस लाया जाएगा और इस धन को युवाओं और महिलाओं के विकास पर लगाया जाएगा. कांग्रेस के नेता मानते है कि आज दो गुना समय व्यतीत होने को है, अब तक न तो पीएम नरेंद्र मोदी और

न ही बाबा रामदेव देश की जनता को यह बता पाए हैं कि विदेशों में काला धन किसका है और वह देश में कब आएगा. कांग्रेस ने चार जनवरी को काला धन लाओ, वादा निभाओ दिवस के रूप में मनाया. इस मौके पर कांग्रेस के नेता जनपद मुख्यालयों पर पीएम व बाबा को जनता से किया वादा याद दिलाने को जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा. कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय का मानना है कि तमसो मां ज्योतिर्गमय की भावना से दीपक लेकर प्रतीकात्मक आन्दोलन का प्रथम चरण है, इसके लिए कांग्रेस मोदी सरकार की ईंट से ईंट बजा देगी. भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतिपक्ष अजय भट्ट का मानना है कि कांग्रेस अध्यक्ष जनता को अपने स्वभाव के अनुरूप भ्रमित कर रहे है. केन्द्र सरकार कालाधन के मामले में गम्भीर है, सतत प्रयास जारी है.

काला धन लाओ, वादा निभाओ दिवस मनाते हुए प्रदेश मुख्यालय, राजीव भवन से जिलाधिकारी आवास तक रैली निकाली. बाद में डीएम देहरादून के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम ज्ञापन भेजा गया. पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत सैकड़ों की संख्या में प्रदेश कार्यालय में एकत्र कांग्रेस नेताओं ने प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय के नेतृत्व में तमसो मां ज्योतिर्गमय की भावना के साथ दीपक लेकर काला धन लाओ, वादा निभाओ के नारे लगाते हुए जिलाधिकारी निवास की ओर पैदल मार्च निकाला. इससे पूर्व बड़ी संख्या में उपस्थित कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने कहा कि उत्तराखंड के समस्त कांग्रेस नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व योगगुरु बाबा रामदेव को याद दिलाना चाहते हैं कि पिछले लोकसभा चुनावों और इससे पहले नरेंद्र मोदी व बाबा रामदेव ने देशवासियों से यह वादा किया था कि इनकी पार्टी यदि केंद्र में सत्ता में आती है तो 100 दिन के भीतर विदेशों में जमा कालाधन देश में वापस लाएंगे और इस धन को युवाओं व महिलाओं के विकास में लगाया जाएगा.

देश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व बाबा रामदेव से पूछना चाहती है कि इनका यह वादा कब पूरा होगा उन्होंने कहा कि दोनों महानुभावों ने चुनावों से पूर्व जनता को भ्रमित करने के साथ धोखा देने का काम किया और राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति कर राजनीतिक अपराध करने के साथ देशवासियों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ भी किया है. जिलाधिकारी निवास पहुंचने के उपरांत रैली सभा में बदल गई, जिसे पूर्व सांसद महेंद्र सिंह पाल, पूर्व विधायक केदार सिंह रावत, निजामुद्दीन, विजय सारस्वत, योगेंद्र खंडूड़ी, रजनी रावत, कमलेश रमन ने संबोधित किया. झूठ के दम पर केंद्र में सत्ता में काबिज हुई भाजपा को बेनकाब करना जरूरी है, यह मानने वाले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने प्रदर्शन की सफलता के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि भाजपा की हर चुनौती का मुकाबला किया जाएगा. भाजपा नेताओं ने कांग्रेस नीत यूपीए प्रगतिशील गठबंधन सरकार के खिलाफ झूठा प्रचार कर देश की जनता को छला है. इसलिए कांग्रेस जनों का दायित्व बनता है कि जिन मुद्दों को उठाकर भाजपा ने चुनाव में विजय हासिल की, इन्हीं मुद्दों पर भाजपा की केंद्र सरकार को जनता को जवाब देने के लिए दबाव बनाया जाए. कांग्रेस ने केंद्र सरकार द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम से शुरू केंद्रीय योजनाओं के नाम को बदलने का कड़ा विरोध किया है. कांग्रेस नेताओं का कहना है कि कांग्रेस इसे किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी मोदी सरकार द्वेष भावना से ग्रस्त होकर धीरे-धीरे स्वर्गीय राजीव गांधी के नाम की योजनाओं का नाम बदल रही है. इन्होंने कहा कि मोदी सरकार ऊर्जा मंत्रालय की राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का नाम दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना कर चुकी है.

विदेश से कालाधन धन लाने की मांग को लेकर एक तरफ प्रदेश कांग्रेस आंदोलन के रास्ते पर है, जबकि प्रदेश की सत्ता में गठबंधन धर्म का निर्वाह कर रहे पीडीएफ नेता यह मान कर चल रहे हैं कि कालाधन विदेश से देश में लाना कोई सहज काम नहीं है. पीडीएफ की राग अलग सुनकर कांग्रेस के कान खड़े हो गए हैं. हरीश सरकार में पर्यटन मंत्री व वरिष्ठ पीडीएफ नेता दिनेश धनै का कालाधन के बारे में स्पष्ट मानना है कि यह काम सहज नहीं है. कालाधन लाने की प्रक्रिया काफी जटिल है. उन्होंने कहा कि कालाधन विदेश से देश में लाने का मुद्दा केवल कांग्रेस का ही नहीं है, अन्य पार्टियां भी चाह रही हैं कि कालाधन जल्द से जल्द देश में लाया जाए. पीडीएफ नेता ने कहा कि देश का हर आदमी चाह रहा है कि कालाधन शीघ्र आए. इसलिए यह कहना कि केवल कांग्रेस ही कालाधन देश में लाने को लेकर गंभीर है. यह बात ठीक नहीं है. उल्लेखनीय है कि पीडीएफ के नेता व श्रम मंत्री दुर्गापाल की कांग्रेस में वापसी को लेकर जिस तरह से पेच फंस गया है, इससे अब कांग्रेस और पीडीएफ के बीच दिनों दिन दूरी बढ़ रही है. ■

feedback@chauthiduniya.com

विश्व योग गुरु बनने के लिए बाबा कुछ भी करेंगे

राजकुमार शर्मा

योग गुरु बाबा रामदेव विश्व योग गुरु बनने के लिए हर कलाबाजी दिखाने के लिए तैयार हैं. पतंजलि योग पीठ के स्थापना दिवस पर जिस तरह अति उत्साहित बाबा ने स्वयं कुश्ती लड़ कर अपने हजारों भक्तों को हैरान कर दिया. बाबा की हर कोशिश है कि अब विश्व योग दिवस पर उनके ही गले में विश्व योग गुरु की माला पड़े. बाबा को इस बात को समझना चाहिए कि यह धरती अभी वीरों से खाली नही है. फिर इस समय जब बाबा ने दोस्त कम दुश्मन कुछ जादा ही पाल रखे है. बाबा अपने धर्मनगरी हरिद्वार स्थित पीठ प्रागढ़ में नितिन गडकरी, रमेश पोखरियाल निशंक जैसे दिग्गज भाजपायी नेताओं की मौजूदगी में अपने मुंह मिया

मिठ्ठू बन रहे थे इसी दौरान कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्गविजय सिंह बाबा की सोहरत की हवा निकालते हुए उन्हें सिर्फ एक व्यापारी बता रहे थे. अब धर्म नगरी में बाबा डाल डाल तो कांग्रेस ने पात पात चलने का मन बना लिया है. कांग्रेस 29 जनवरी को हरिद्वार में योग गुरू को सन्मति दे भगवान गांधी जी का प्रिय गीत गा कर उन्हें उनके किए गए वादे की याद दिलाएगी. उत्तराखंड कांग्रेस ने कालेधन वापसी पर बाबा रामदेव पर निशाना साधा है. कांग्रेस का मानना है कि योगगुरु बाबा रामदेव को सन्मति मिले और लोकसभा चुनाव के दौरान कालेधन को लेकर दिए गए उनके वचनों की रक्षा हो. संतों के भगवा चोले की विश्वसनीयता खतरे में न पड़े.

उत्तराखंड के कांग्रेसी लामबन्द हो कर महात्मा गांधी की पुण्यतिथि(30 जनवरी) से एक दिन पूर्व कांग्रेस कार्यकर्ता धर्मनगरी हरिद्वार में धरना देंगे. रामदेव को उनका वादा दिलाया जाएगा और वे दोबारा आंदोलन छेड़े नहीं तो आगे से देश का जनमानस संतों पर विश्वास नहीं करेगा. लोकसभा चुनाव से पहले बाबा रामदेव ने कहा था कि उनकी समर्थित यानी भाजपा सरकार आने के 30 दिन के भीतर कालाधन वापस आ जाएगा. इससे हर नागरिक को 15-15 लाख रुपये दिए जाएंगे और हर परिवार को 25 हजार रुपये प्रतिमाह पेंशन भी मिलेगी. इतना ही नहीं नागरिकों को कोई कर नहीं देना होगा और सभी चीजें सस्ती हो जाएंगी. रसोई गैस सिलिंडर भी 200 रुपये से कम कीमत पर मिलेगा. मोदी सरकार के शासन के सात माह बाद भी इस दिशा में कुछ नहीं हुआ है. जनता खुद को ठगा महसूस कर रही है. प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने कहा कि बाबा रामदेव को अपने वादे याद कर उन्हें पूरा करवाना चाहिए. बाबा रामदेव ने लोकसभा चुनाव से पहले संकल्प लिया था कि जब तक तत्कालीन यूपीए सरकार हट नहीं जाती व कालाधन वापस नहीं आ जाता तब तक वह पतंजलि योगपीठ नहीं जाएंगे. अब उन्हें संकल्प लेना चाहिए कि वह तब तक पतंजलि योगपीठ नहीं जाएंगे, जब तक केंद्र सरकार विदेशों में जमा कालाधन नहीं लौटा लाती. इसी के साथ मोदी सरकार की वादा खिलाफी के विरुद्ध भी ठीक इसी तरह एक आंदोलन चलाना चाहिए, जैसा कि उन्होंने यूपीए सरकार के विरुद्ध चलाया था. 29 जनवरी को कालेधन वापसी के संकल्प का बाबा रामदेव को स्मरण कराने के लिए कांग्रेस हरिद्वार में धरना देगी.

बाबा पर करारा व्यंग बाड़ छोड़ते हुए किशोर उपाध्याय ने कहा कि वैसे भी हरिद्वार में एक पत्थर उठाओ तो दस संत निकल आते हैं. केंद्र सरकार को दो सौ से अधिक दिन हो गए हैं ऐसे में रामदेव अब मोदी की भक्ति को परित्याग कर बिल से बाहर आएं ये इनकी अस्मिता का सवाल है. इनका कहना है कि केंद्र सरकार गंगा को भी धोखा दे सकती है गंगा उत्तराखंड की बेटी हैं ऐसा करने नहीं देंगे. ■

उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन बिजली की दरों में जल्दी ही बड़ा इजाफा करने का मन बना रहा है. पावर कॉरपोरेशन ने 2015-16 के टैरिफ प्रस्ताव में जो सिफारिशें की हैं, अगर वो लागू हो जाती हैं, तो प्रदेश में बिजली की नई दरें जनता की जेब पर अच्छा खासा बोझ डालेंगी. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, उत्तर प्रदेश में वर्ष 2015-16 में शहरी, कॉमर्शियल व औद्योगिक बिजली दरों में आठ फीसदी औसत वृद्धि का प्रस्ताव विद्युत नियामक आयोग को दिया गया है. जानकारों का कहना है कि आयोग जरूरी प्रक्रिया पूरी करने के बाद नई दरें तय कर सकता है.

अखिलेश सरकार फिर बढ़ाएगी बिजली की दरें

वैष्णवी वंदना

जनता की जेब काटने की तैयारी

नए साल में अच्छे दिन आने का इंतजार कर रही उत्तर प्रदेश की जनता को सपा सरकार जोरदार आर्थिक झटका देने जा रही है. मंहगाई, भ्रष्टाचार, लचर कानून व्यवस्था और हाल ही में बिजली की बढ़ी दर से बेदम जनता पर एक बार फिर से बिजली की दरें बढ़ाने की कवायद सरकार ने शुरू कर दी है. प्रदेश वासियों को एक बार फिर बिजली की दरों में संभावित बढ़ोतरी का डर सताने लगा है. समाजवादी पार्टी को सत्ता में आए हुए बमुश्किल तीन साल हुए होंगे और इन तीन सालों में उत्तर प्रदेश सरकार चौथी बार बिजली की कीमत बढ़ाने की तैयारी कर रही है.

उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन बिजली की दरों में जल्दी ही बड़ा इजाफा करने का मन बना रही है. पावर कॉरपोरेशन ने 2015-16 के टैरिफ प्रस्ताव में जो सिफारिशें की हैं, अगर वो लागू हो जाती हैं, तो प्रदेश में बिजली की नई दरें जनता पर अच्छा खासा बोझ डालेगी. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, उत्तर प्रदेश में वर्ष 2015-16 में शहरी, कॉमर्शियल व औद्योगिक बिजली दरों में आठ फीसदी औसत वृद्धि का प्रस्ताव विद्युत नियामक आयोग को दिया गया है. जानकारों का कहना है कि आयोग जरूरी प्रक्रिया पूरी करने के बाद नई दरें तय कर सकता है. पावर कॉरपोरेशन के प्रस्ताव में बीपीएल उपभोक्ताओं पर दोहरी मार पड़ने की संभावना है. राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के मुताबिक अगर कॉरपोरेशन के बढ़ोतरी प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है, तो बीपीएल उपभोक्ता की बिजली दरें दोगुनी, और शहरी घरेलू उपभोक्ता की दरें 30 से 35 प्रतिशत बढ़ जाएगी. सूत्रों का कहना है कि अब 300 यूनिट तक खपत करने वाले उपभोक्ताओं को 4.75 रुपये प्रति यूनिट, 300-500 यूनिट की खपत पर 5.25 रुपये प्रति यूनिट और 500 से ऊपर के लिए 5.75 रुपये प्रति यूनिट लिया जाएगा. जिससे हरियाणा से भी ज्यादा उत्तरप्रदेश की जनता को बिजली बिल की दरें अदा करनी होंगी.

उत्तर प्रदेश सरकार बिजली की दरें लगातार बढ़ाए तो जा रही है, लेकिन बिजली की आपूर्ति नियमित करने में नाकाम साबित हो रही है. 2014-15 के दौरान यूपी में बिजली आपूर्ति की स्थिति अत्यन्त दयनीय रही है. सरकारी संस्था सीईए के आंकड़ों पर नजर डालें तो अप्रैल से लेकर नवंबर के बीच प्रदेश में मांग के मुकाबले करीब 17 प्रतिशत कम बिजली का आपूर्ति हुई है. अखिलेश सरकार बिजली की उपलब्धता एवं अन्य बुनियादी सुविधाओं को बढ़ाने की बात तो करती है, लेकिन कार्यान्वित करने में विफल रही है. इससे पहले उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग की ओर से प्रदेश में बढ़ाए गए बिजली के नए रेट पिछले साल एक अक्टूबर से लागू किए गए थे. प्रदेश सरकार पर बिजली की चोरी रोकने में विफल होने पर बोझ जनता पर डालने के तरीके की भरपूर आलोचना भी हुई. लोगों का मानना है कि सरकार को दरें बढ़ाने से पहले बिजली आपूर्ति को सुधारने, बिजली चोरी कम करके रेवेन्यू बढ़ाने के तरीके पर विचार करना चाहिए.

उत्तर प्रदेश में बिजली के लगभग सवा करोड़ उपभोक्ता हैं. उन्हें निरंतर बिजली देने के लिए लगभग 25 हजार मेगावाट बिजली चाहिए. राज्य के सरकारी कारखानों में करीब ढ़ाई हजार मेगावाट बिजली बनती है और करीब चार हजार मेगावाट बिजली केन्द्रीय बिजली घरों से मिल जाती है. बिजली संकट का सबसे बड़ा कारण यही है कि बढ़ती हुई मांग के अनुरूप नए बिजली घरों की स्थापना नहीं की गई और एक दो को चालू भी किया गया है. उसका उत्पादन कोयला की कमी के कारण बाधित है. दरअसल कोयले की कमी नए बिजली घरों की स्थापना में भी एक बड़ी बाधा है. बाकी जरूरत के लिए निजी ट्रेडिंग कम्पनियों से खासा महंगे दरों पर बिजली खरीदनी पड़ती है. उत्तर प्रदेश का ऊर्जा क्षेत्र फिलहाल देश के निजी घरानों के चंगुल में है और उसका खामियाजा प्रदेश की जनता भुगत रही है. सी.ए.जी रिपोर्ट में 5000 करोड़ से ऊपर की अनियमितता का खुलासा होने के बाद भी बजाज व रिलायन्स से मंहगी बिजली खरीदना सरकार ने जारी रखा है. अब हालात ऐसे हो गए हैं कि उत्तर प्रदेश में न तो मांग के अनुरूप बिजली की आपूर्ति हो पा रही है और न ही बिजली खरीदने के लिए बिजली पावर कॉरपोरेशन के पास पैसे हैं. ऐसे में आम जनता को ही बिजली दर बढ़ाकर शिकार बनाया जा रहा है.

पिछली बार जब दरों में बढ़ोतरी की गई थी तो कुछ वादे किए गए थे, जिन्हें पूरा कर पावर कॉरपोरेशन का घाटा भरना था. तय किया गया था कि लाइन हानियों को कम कर 23 फीसदी तक लाया जाएगा, लेकिन पावर कॉरपोरेशन इस लक्ष्य को प्राप्त करने में नाकाम हुआ और उसने हाथ खड़े कर दिए. मार्च 2015 तक बिना मीटर बिजली खर्च कर रहे सभी उपभोक्ताओं के यहां मीटर लगाने का लक्ष्य था. अब पावर कॉरपोरेशन का कहना है कि अधिक से अधिक दस फीसदी अन्य उपभोक्ताओं को ही मीटरयुक्त उपभोक्ता बनाना संभव होगा. बिजली कर्मचारियों के घरों में भी मीटर लगाने का लक्ष्य निर्धारित था. जिसे पूरा करने में पावर कॉरपोरेशन फेल रहा. उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन में घाटे का सबसे बड़ा कारण बिजली की चोरी है. जितनी बिजली सप्लाई होती है उसका लगभग साठ फीसदी दाम ही वसूल हो पाता है यानी लगभग चालीस फीसदी बिजली का दाम नहीं मिलता. बिजली की चोरी ज्यादातर बड़े कारखानों और बाजारों में अक्सर विभागीय अधिकारियों की मिली भगत से होती है. कई इलाकों में घरों में भी कटिया डालकर बिजली जलाई जाती है. जानकार लोगों का कहना है कि अगर बिजली की चोरी रोक दी जाए तो बिजली बोर्ड का घाटा काफी कम हो सकता है, लेकिन नाकारा पावर कॉरपोरेशन बिजली चोरी रोक पाने में नाकाम रहा. बिजली विभाग इन चोरी के खिलाफ अभियान चलाने की लगातार बात तो करता है. पर कार्यान्वित नहीं कर पा रहा है. इन्हीं सब कारणों को पूरा करने में फेल पावर कॉरपोरेशन को बार-बार बिजली की दरें बढ़ाना ही सबसे आसान तरीका लगता है. लाइन हानि, बिजली चोरी, बिना मीटर के उपभोक्ता मिलकर जो बिजली खर्च करते हैं उसका खमियाजा ईमानदारी से बिल जमा करने वाले को भुगतना पड़ता है. अगर पावर कॉरपोरेशन अपनी कार्य क्षमता का सही इस्तेमाल इन कारणों को रोकने पर अपना ध्यान केंद्रित करे तो बार-बार बिजली दरों में बढ़ोतरी की संभावना ही न बने. प्रदेश में बिजली के हालात पहले से ही खराब हैं, ऊपर से बिजली कम्पनियां सरकार से दाम बढ़ाने के लिए जोर डालती रही है. प्रदेश की बिजली कम्पनियां अन्य राज्यों की तुलना में पहले से ही काफी अधिक दाम वसूल रही हैं, और आपूर्ति भी अन्य प्रदेशों की तुलना में काफी खराब है. पिछले बारह सालों में विद्युत निगम लगभग चालीस हजार करोड़ के घाटे में चला गया है. उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्य में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार व मध्य प्रदेश जैसे राज्य हैं, जहां की बिजली दरें उत्तर प्रदेश से सस्ती हैं.

लोगों का मानना है कि विद्युत निगम में घाटे की एक बड़ी वजह घोर कुप्रबंध और भ्रष्टाचार भी है. पावर कॉरपोरेशन में भ्रष्टाचारी भीषण लामबंद हैं. भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने पर वहीं काम कर रहे व्हिसल ब्लोअर नन्दलाल जायसवाल को इसका खमियाजा आपनी नौकरी गंवा कर और प्रताड़नाएं झेल कर भुगतना पड़ा है. लिहाजा, केवल बिजली की दरें बढ़ाने से काम नहीं चलेगा. इसके लिए सरकार को बिजली विभाग में हो रहे भ्रष्टाचार, कुव्यवस्था और निजी क्षेत्र पर निर्भर रहने के बजाय अपने बिजली घर लगाने होंगे और कार्य कुशलता में सुधार लाना होगा. ■

उत्तर प्रदेश सरकार बिजली की दरें लगातार बढ़ाए तो जा रही है, लेकिन बिजली की आपूर्ति नियमित करने में नाकाम साबित हो रही है. 2014-15 के दौरान यूपी में बिजली आपूर्ति की स्थिति अत्यन्त दयनीय रही है. सरकारी संस्था सीईए के आंकड़ों पर नजर डालें तो अप्रैल से लेकर नवंबर के बीच प्रदेश में मांग के मुकाबले करीब 17 प्रतिशत कम बिजली का आपूर्ति हुई है.

इन राज्यों में यूपी से कम हैं बिजली दरें

उत्तराखंड-(दर रुपये प्रति यूनिट में) 0 से 100 तक 2.30 रुपये, 101 से 200 तक 2.70 रुपये, 201 से 400 तक 3.35 रुपये, 400 से ऊपर 3.50 रुपये.

बिहार- (दर रुपये प्रति यूनिट में) 0 से 100 2.85 रुपये, 101 से 200 तक 3.50 रुपये, 201 से 300 4.20 रुपये, 300 से ऊपर 5.30 रुपये.

हरियाणा-(दर रुपये प्रति यूनिट में) 0 से 40 तक 2.70 रुपये , 41 से 250 तक 4.50 रुपये, 251 से 500 तक 5.25 रुपये 500 से 800 5.98 रुपये.

उत्तर प्रदेश- (प्रस्तावित दरें रुपये प्रति यूनिट) 0 से 300 तक 4.%5 रुपये, 301 से 500 तक 5.25 रुपये 500 से ऊपर 5.75 रुपये.

घरेलू उपभोक्ताओं के बिजली दरों में बढ़ोत्तरी

दो साल में 50 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी

2013-14 - 0 से 200 प्रति यूनिट 4.00 रुपये, 201 से 500 प्रति यूनिट 4.50 रुपये, 500 से ऊपर 5.00 रुपये.

2014-15- 0 से 150 प्रति यूनिट 4.00 रुपये, 151 से 300 प्रति यूनिट तक 4.50 रुपये, 301 से 500 तक प्रति यूनिट 5.00 रुपये और 500 से ऊपर 5.50 रुपये प्रति यूनिट.

सरकार का प्रस्ताव जनविरोधी

राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय सचिव अनिल दुबे ने यूपी पावर कॉरपोरेशन द्वारा बिजली मूल्य में बढ़ोत्तरी हेतु विद्युत नियामक आयोग को भेजे गए प्रस्ताव को जनभावनाओं के विपरीत बताते हुए इस प्रस्ताव को तत्काल वापस लेने की मांग की है. उन्होंने कहा कि बिजली मूल्य में बढ़ोत्तरी न्याय संगत नहीं है. दुबे ने कहा कि पावर कॉरपोरेशन अपने घाटे और बैंक से ऋण प्राप्त करने के लिए प्रदेश के उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त भार डालने की साजिश कर रहा है. जबकि उसे मूल्य बढ़ाने के बजाय अपने घाटे और लाइन हानियों को कम करना चाहिए. पावर कॉरपोरेशन अपनी नाकामियों को काबू करने, बिजली चोरी और राजस्व वसूली को सुदृढ़ करने के बजाय प्रदेश के निरीह जनता पर बिजली मूल्य बढ़ाकर उसकी वसूली कर रहा है. अभी पिछले तीन माह पूर्व ही बिजली के दाम बढ़ाए गए थे जिसके तहत 2500 करोड़ रुपये की राजस्व वसूली विभाग को आनी थी, लेकिन विभाग की लापरवाही के चलते लगभग 2100 करोड़ रुपये की ही राजस्व वसूली हो रही है और 400 करोड़ रुपये की हानि हो रही है. रालोद नेता ने कहा कि बिजली विभाग एक तरफ आम जनता को पूरी तरह से बिजली नहीं दे पा रहा है और गांव और किसानों को बिजली न के बराबर मिल रही है. इसे ठीक करने के बजाय उपभोक्ताओं के ऊपर 10 प्रतिशत मूल्य वृद्धि का प्रस्ताव भेज दिया गया है. उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से इस प्रस्ताव को जनहित में वापस लेने की मांग की और कहा कि बिजली मूल्य में बढ़ोत्तरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और यदि कीमतें बढ़ीं तो इसके खिलाफ आन्दोलन शुरू किया जाएगा. ■